हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

21 मार्च 1995

खण्ड 1, अंक 10

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 21 मार्च 1995

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(10)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर,	(10)32
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(10)37
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
समस्त जिला फरीदाबाद में प्रदूषण सम्बन्धी	(10)38
वक्तव्य–	
उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बंधी	(10)39
वाक आउट	(10)43
वर्ष 1995–96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(10)44
वाक आउट	(10)71
वर्ष 1995– 96 कें बजट पर सामान्य चर्चा (पूनरारम्भ)	(10)72
बैठक का समय बढ़ाना	(10)83
वर्ष 1995– 96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(10)83
बैठक का समय बढ़ाना	(10)89
वर्ष 1995– 96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(10)89

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 21 मार्च, 1995

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर– 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ईश्वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Repair of Dam

***1137. Shri Krishna Lal :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether the Dam on Yamuna River in village Tamsabad, district Panipat at Burji No . 2 and 3 is in damaged condition; and

(b) if so, the time by which the said Dam is likely to be repaired?

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra) :

(a) Yes. The bund along River Yamuna in village Tamsabad in reach RD 1600 to 2300 was damaged during floods of 1994.

(b) The bund will be repaired before monsoon of 1995 on availability of funds.

श्री कृष्ण लालः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि तमसाबाद बांध का काम कब तक हो जाएगा? अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने सवाल के जवाब में यह बताया मश कि तमसाबाद डैम 1994 मे टूटा था, क्या सरकार को अब तक उसको ठीक करने की सुध नहीं आई है?

अध्यक्ष महोदय, बुर्जी 1600 से 2300 तक यह बांध टूटा है। मन्त्री जी ने दूसरा जवाब दिया है कि धन की उपलब्धि पर इसको बनवाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, 10– 12 गांव इसमे बिल्कुल बरबाद हो रहे हैं क्योंकि बांध में 100 से 200

मीटर तक के कट लगे हुए है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या वर्तमान बजट में इन बांध के लिए कोई पैसे का प्रावधान किया गया है यदि किया गया है तो कर तक इस बांध को कम्पलीट करवा देंगे?

चौधरी जगदीश नेहराः अध्यक्ष महोदय, जै सा कि मैंने अर्ज किया है कि इस बार की मौनसून जो कि जुलाई महीने तक आएगी, इसको इस साल कर दिया जाएगा। स्पीकर सर, जैसे मैंने मान नीय साथी को बताया कि यह बांध 700 फुट तक लगातार काफी टूट गया है। 26–7– 1993 को यमुना रिवर में 93 हजार क्यूस्कि पानी आ गया था जिसकी वजह से यह नुकसान हुआ है। दिनांक 2– 2– 1995 को फ्लड कण्ट्रोल बोर्ड की मीटिग में इस मामले को रखा गया था। इस फल्ड कण्ट्रोल बोर्ड के चेयरमैन माननीय मुख्य मन्त्री जी हैं, उन्होने इस बांध के लिए 50 लाख रुपये का प्रावधान किया है। जल्दी ही सारा पैसा मिल जाएगा और 740 फुट बांध जो टूट गया है या जो उसमें कटाव हुए हैं, उनकी रिपेयर हो जाएगी। जो कटाव आए हें, उनके लिए 3 स्टडज बनाने के लिए तथा मुरम्मत के लिए 50 लाख रु पये मानसून के शुरू होने से पहले–पहले इस काम को करने के लिए खर्च कर दिए जाएंगे।

श्री कृष्ण लालः अध्यक्ष महोदय, मेरा तुक दूसरा सप्लीमैंटरी है जो बहुत ही जरूरी है। मैं कहना चाहता हूं कि जब कही बान्ध टूट जाता है तो फसल बिल्कुल बरबाद हो जाती है जिसका मुआवजा किसानों को दिया जाना चाहिए। मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि इस बांध के टूटने से जिन किसानों की फसलें बरबाद हुई ऐं, क्या उनको मुआवजे के रूप में कोई राशि दी गई हैय यदि दी गई है तो कितनी राशि दी गई है?

चौधरी जगदीश नेहराः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि फसलों के लिए किसानों को मुआवजे के रूप में कोई

राशि न हीं दी गई है। अध्यक्ष महोदय, बांध के टूटने से किसानों की फसल कुछ खराब हुई है। इस बांध के टूटने का कारण यद् है कि यू०पी० साईड में उन्होंने स्टडज काफी बड़े–बड़े बनाए हैं। हुमने इस बा रें में सी ० डब्ल्यू ० सी० में अपना एतराज भी दर्ज किया है। इसकी वजह से बांध टूटते हैं और लम्बे स्टडज की वजह से इमा रा नुकसान होता है क्योकि रिवर जो है, वह रास्ता बदल लेती है, यह एतराज हम ने दर्ज करवाया है। दूसरे माननीय श्री कृष्ण लाल जी ने वह पृ छा है कि किसानों को कोई मुआवजा दिया गया है या कि नहीं? मैं उस बारे में इनको बताना चाहूंगा कि इसके लिए किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिय गया है।

प्रो० राम बिलाश शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को यह बतान चाहूंगा कि बाढ के समय महेन्द्रगढ़ जिले में तीन जगह से बांध टुट गया था। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वे प्राथमिकता के आ धार पर इमको ठीक करवाएंगे?

चौधरी जगदीश नेहराः अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का मेन सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है। जो ये कह रहे हैं वह यमुना का ऐरिया है। स्पीकर सर, जहां का ये कह रहे हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि जहां–जहां बांध टूट गया है उसको ठीक करवाया जाये।

Upgradation of School of village, Singwal

*** 1048. Shri Bharath Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the school of village Singwal to 10+2 system school in District Kaithal ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid school is likely to be upgraded ?

शिक्षा मन्त्री (चौधरी फूल चाह मुलाना):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भरथ सिंहः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने जवाब दिया है कि प्रश्न ही नहीं उठता। मन्त्री जी तो कोई काम करके राजी नहीं हैं। स्पीकर साहब, 10–12 गांवों के लोगों की डिमांड है कि गांव सिगवाल के स्कूल के अपग्रेड किया जाए। सिंगवाल, अदकन, नयोधार, भालूग खेड़ीशेरखां, सींसर, ढाकल, थोह, बदड़यांना आदि। इन गांवों के लोगों की यह डिमांड है कि इस स्कूल को अपग्रेड किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम सै माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि लोगों की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए, क्या सिंगवाल के स्कूल का दस जमा दो में दर्जा बढाया जाएगा?

चौधरी फूल चन्द सुलानाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस स्कूल के बारे में पूछा है वह नार्मज पूरे नहीं करता है। इस स्कूल में गोबी कक्षा में 23 बच्चे और दसवीं कक्षा में 26 ही बच्चे है। इतने बच्चों पर दस जमा दो नहीं बन सकता है।

Cases of Rape/Murder etc. registered in the State

***1093. Prof. Sampat Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state

(a) the total number of cases of murder/rape, kidnapped/abducted registered in the State during the year 1994-95 to date ;

(b) the number of cases out of those referred to in part (a) above relate to minors and the persons belonging to Schduled Castes and Backward Classes ;

(c) the number of cases out of those referred to in part (a) above remain unsolved and the number of cases in which arrests have not been made so for ; and

(d) the number of cases ; if any, out of those referred to in part

(a) above have been handed over to C.B.I. togetherwith the details thereof ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन जेल): विवरण तालिका सदन के पटल पर रखी है।

"स्टेटमेंट "

भाग (क)

अपराध का शीर्षक	दर्ज किय गये मुकदमें:	
	1994	1995 (28— 2— 95 तक)
हत्या	661	78
बलात्कार	254	46
अपहरण/अपनयन	350	75

भाग (ख) उपरोक्त भाग (क) में से

	अवयस्क		अनुसूचित जातियां		पिछड़ी श्रेणियां	
	1994	1995	1994	1995	1994	1995
हत्या	18	3	35	1	13	1
बलात्कार	82	9	36	4	26	9
अपहरण/अपनयन	57	9	39	2	12	1

भाग (ग)

	1. हल न हो सके मुकदमों की संख्या:	
	1994	1995 (28— 2— 95

		तक)
हत्या	48	1
बलात्कार	8	1
अपहरण/अपनयन	15	

	2. मुकदमों की संख्या जिनमें गिरफ्तारी नही हुई है	
	1994	1995 (28— 2— 95 तक)
हत्या	83	16
बलात्कार	11	4
अपहरण/अपनयन	68	15

भाग (घ)

	सी०बी०आई ० को दिये गये मुकदमों की संख्या तथा ब्यौराः	
	1994	1995
हत्या	1	1
बलात्कार		
अपहरण/अपनयन		

1. सतिन्द्र सिंह सेखो की हत्या से संबान्धित मुकदमा नं 89 दिनांक 16—7— 94 धारा धनि 302/34/449/,120 बी. भा०द ०स ० तथा

25/30/54/59 शस्त्र अधिनियम थाना सदर अम्बाला, दिनांक 12–8– 94 को सी० बी ० आई० को दिया गया जो जेर समायत

2. रणबीर सिंह सुहाग की हत्या से सम्बन्धित मुकदमा नं० 5 दिनांक 9– 1– 95 धाराधीन 365/302 भा ०द० स० थाना सिविल लाईन रोहतक दिनांक 22– 1–95 को सी०बी ०आई० को दिया गया जिसमें तफतीश की जा रही है।

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने बताया कि सूचना सदन के पटल पर रखी गई है ओर सूचना के मुताबिक 28–2–95 तक मर्डर केस 739, रेप केसिज 300 और किडनैपिंग /ऐबडक्शन के 425 केस हुए हैं। इसमें मोस्टली मर्डर, रेप और किडनैपिंग वगैरह माईनर्ज कलासिज के केस हैं जो एस०सीज० और बी०सीज० लोगों के साथ हुए हैं। मैं मंत्री जो से पूछ ना चाहता हूं कि मर्डर के कितने ऐसे केसिज हैं जो पुलिस कस्टडी में हुए हे या जिनमें पुलिस के लोग इन्वाल्वड हैं? रेप के कितनै ऐसे केसिज हैं, जिनमें पुलिस के लोग इन्वाल्वड हैं। किडनैपिंग/रैनसम के कितने केसिज हैं?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सवाल तो कुछ और पूछा था और अब कुछ और ही पूछ रहे हैं। ये इस बारे में अलग से पूछ लें तो हम अलग से बता देंगे। इन्होंने तो टोटल नम्बर पूछे थे और वे हमने इनको बता दिए हैं। इस बारे में ये जवाब को पढ़ कर देख लें।

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, हेंने सप्लीमैंटरी पूछी है और उसमें मर्डर केसिज के बारे में पू छा है। ग्रुप्स में झगड़ा हो जाए तो मर्डर के केस होते हैं। पुलिस थानों में मर्डर के केसिज होते हैं और किडनैपिंग के बाद मर्डर केसिज होते हैं। मैं तो इनसे यह पूछ रहा हूं कि पुलिस कस्टडी में कितने मर्डर केसिज हुए हैं?

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी, आगे भी इसी तरह का प्रश्त आ रहा है और उसमें यह पूछा गया है। अब आप बैठ जाएं।

Prof. Sampat Singh : I am asking supplementary, Sir. Mr. Speaker : No. Please take your seat.

Prof. Sampat Singh: Why the Chief Minister is trying to hide the facts ? (interruptions)

Mr. Speaker : You may kindly give a separate notice.

Prof. Sampat Singh : But this supplementary arises out of this question. (Interruptions) Why the Government is trying to hide the facts ? If the Government is not prepared to reply to my supplementary, then the Government can say that they will reply afterwards. If the Government is ready, the reply should come now.

Mr. Speaker ; Sampat Singh Ji, please take your seat.

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय 1994 में हत्या के 661 केसिज हुए हैं जनमें 22 केसिज कैंसिल हुए, 48 केसिज अंदमपता है, 472 केसिज में चालान हुए और उनमें से 435 केसिज न्यायालय मे विचाराधीन है। इसके इलावा, 119 के सिंज जैरे–तफतीश हैं। हमने इनको टोटल आकड़े बताए हैं लेकिन ये पूछ रहे हैं कि कस थाने में कितने लोग मारे गए।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, मैं थानों के बारे में नहीं कह रहा हूं बल्कि मैं तो पुलिस कस्टडी के बारे में पूछ रहा हूं। आप ही बताएं कि फिर सप्लीमैटरी क्या हो सकती है?

बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर सर, इन्होंने केवल रीजस्टर्ड केसिज के बारे में पूछा है किं कितने केसिज रजिस्टर्ड हुए हें, कितने कत्ल हुए हैं इसलिए इससे तो सप्लीमैंटरी अराईज ही नहीं होती।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, वे रजिस्टर्ड केसिज में से ही पूछ रहा हूं। ये तो टोटल फिगर्ज हैं मैं इनमें से ही पू छ रहा हूं। पुलिस थानों के अन्दर जो

लोग मारे जाते हैं वहां पर 302 का ही केस बनता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे केसिज कितने हैं?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने टोटल केसिज पूछे हैं और टोटल केसिज के ही हमने आकड़े दे दिए हैं।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, इनका टोटल आकड़ों के बारे में रिटन जवाब आ गया है, यह तो मैं भी जानता हूं।

श्री अध्यक्षः आप केवल प्रश्न पूंछें।

प्रो० सम्पत सिंहः सर, पुलिस वालों की बात से तो इनको एलर्जी है। इसलिए मैं अपना दूसरा सवाल यह पूछना चाहता हूं कि फिरौती यानी रैनसम के कितने केसिज हुए हैं? (Interruptions) He is well prepared to reply but he is hiding the facts. सर, मैं इसमें यह पूछना चाहता हूं कि इन केसिज में से कितने केसिज के चालान पुट–अप हो चुके है? इसके अलावा, मैं इसमें यह भी पूछना चाहत। हूं कि एम० डी ० यूनिवर्सिटी के अन्दर जो प्रो० रणबीर सिंह सुहाग का मर्डर हुआ था, उस केस में अब क्या प्रोग्रैस है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, 1994 में 661 मुकदमें कत्ल के दर्ज हुए, जिनमें से 22 केसिज कैंसिल हो गए। 48 केसिज अदमपता हैं और 472 केसिज में चालान हो गए, जिसमें से 37 बरी हो गए और 435 केसिज न्यायालय के पास विचाराधीन हैं। इसके अलावा, 119 केसिज जैरे तफतीश हैं। इसी तरह से 1995 में कत्ल के 78 केसिज हैं, जिनमें दो केसिज कैंसिल हो गए, एक अदमपता है और सात केसिज में चालान हो गए है। इसी तरह, से अध्यक्ष महोदय, 1994 में हत्या के 254 केसिज थे जिनमें से 14 केसिज कैसिल हो गए, आठ अदमपता है और 225 केसिज में चालान हुए जिनमें से एक केस में सजा हो गयी है और 14 बरी हो गए तथा 210 केसिज कोर्ट में विचाराधीन हैं और चार केसिज जैरे तफतीश

हैं। इसके अलावा, अपहरण और दूसरे अन्य केसिज 360 है जिसमें 81 केसिज कैसिल हो गए, 15 अदमपता हैं और 173 केसिज में चालान हुए, 12 बरी हो गए और तीन में सजा हो गयी एवं 158 केसिज कोर्ट में विचारा– धनि हैं और 81 केसिज जेरे तफनीश है। इसी तरह से 1995 में हत्या के 78 केसिज थे जिनमें से दो केसिज कैंसिल हो गए, एक अदमपता है तथा 64 केसिज में चालान हुए। इसी तरह से बलात्कार के 46 केसिज थे, जिसमें दो कैंसिल हो गए, एक अदमपता है। तीन केसिज के चालान हो गए। तीन केसिज कोर्ट में विचाराधीन हैं और चालीस केसिज जैरे तफतीश हैं। अध्यक्ष महोदय, यह आकड़े मैंने इनको दिए हैं। इसके अलावा, रणबीर सिंह सुहाग के बारे में भी इन्होंने कहा है। अध्यक्ष महोदय, यह केस सी ०बी ०आई० के जैरे तफतीश है। सी ०बी० आई० इसकी जांच कर रही है। आप जानते हैं कि जब सी०बी०आई ० केस ले लेती है तो आगे की कार्यवाही भी वही करती है। हम उनसे कोई भी इंफर्मेशन लेते या देते नही हैं।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, मैं एक बात इन से कैटेगरीकली पूछना चाहता हूं। पुलिस कस्टडी में लेखू हत्याकांड के बारे में जैसा कि पुलिस के वर्शन में आया हं कि जब अपराधी को ले आ रहे थे तो रास्ते में कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया और दो लोगों को मार दिया। स्पीकर सर जिन दो लोगों को हमला करके कुछ लोगों ने मारा है क्या उस केस में कोई गिरफतारी हुई हैं या नही हुई है? उस केस की अब क्या प्रोग्रेस है? वह केस तो आपकी पुलिस के पास ही है। सर, यह भी बड़ा सीरियस मामला शै क्योंकि जब वे लोग पुलिस कस्टडी में जा रहे थे तो उसके बावजूद भी कुछ लोगों द्वारा उन पर हमला हुआ और वहां दो लोग मारे गए। सर, पब्लिक में यह धारणा है कि ये लोग फाल एनकाऊंटर में मार दिए गए थे और अगर वे लोग इस तरह से नही मारे गए हैं तो उस केस की

प्रोग्रेस, के बारे में मुख्य मंत्री जी हमें बता दें कि क्या उस केस में कोई गिरफतारी हुई है या नहीं हुई है?

चौधरी भजन लालः अष्यक्ष महोदय, उसमें वाकई दो आदमी मारे गए। उसकी जांच एक सीनियर डी० एस० पी ० कर रहे हैं। अभी तक तफतीश जारी है। पूरी तफतीश होने के बाद हम बताएंगे कि इस केस में किसका फाल्ट है, कैसे हुआ, कौन मुलजिम है? सही मामला पूरी तफतीश के बाद सामने आएगा, तब बता दिया जाएगा।

श्री अध्यक्षः आपने जो यह डैथस इन पुलिस कस्टडी और इन एनकांटर पूछा था आगे इस बारे में 24 मार्च, 1996 को श्री छ तर सिंह चौहान का क्वैश्चन आ रहा है जो यह हैः–

"Will the Chief Minister be pleased to state the total number of deaths, if am, occured in Police custody and in encounter with the police during the period from July, 1991 todate in the State togetherwith the detaills thereof"

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, रैनसम के बारे में जवाब नहीं आया, किडनैपिंग रैनसम के लिए हुई हे। (विध्न)

श्री अध्यक्षः उसके लिए आप अलग से क्वैश्चन दें।

प्रो० राम विलास शर्माः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होने अपने लिखित जवाब में 1994 में जो मुकदमें हल नहीं हो सके उनकी संख्या इस प्रज्ञपर बताई हैः हत्या के 48 मामले हल नही हो सके, बलात्कार के 8 और अपहरण के 15 मामले हरन नही हो सके। इसी तरह जिन मुकदमों में गिरफतारी नहीं हुई उनका ब्यौरा भी दिया है। हत्या के 83 मुकदमें ऐसे बताए हैं, जिन्में गिरफतारी नहीं हुई, बलात्कार के 11 और अपहरण के 18 मुकदमें ऐसे बताए हैं, जिनमें गिरफतारी नहीं हुई। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना

चाहता हूं कि हत्या जैसे जघन्य अपराध में और अपहरण व बलात्कार के इतनी बडी सख्यां में मुकदमें हैं, जिनमें गिरफतारी नहीं हुई, जो हल नहीं किए जा सके, इसके क्या कारण हैं?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इसके कई कारण हैं। बम कारण यह है कि एक हत्या हो गई और मुलजिम को किसी ने देखा नहीं। मूलजिम का एफ०आई०आर० में नाम दर्ज नही करवाया। पुलिस तफतीश करती है। हत्या हो गई लेकिन कोई ग्वाह नहीं, कोई बताने काला नहीं। अध्यक्ष महोदय, कई ऐसे केसिज भी हैं जिनमें शिनाख्त नहीं हो सकती। शिनाखत नहीं हो तो गिरफतारी नहीं की जा सकती। इन हालात में जव तक सामने कोई सबूत न आएं, 302 के मामले में सजा होना बड़ा भारी मुश्किल है।मुलजिम वही पकड़ा जाना चाहिए जो सही माने में मुलजिम हो। सबूत बकायदा पर्याप्त माता में उपलब्ध हों, तभी गिरफतारी की जाती है, चाहे वह केस बलात्कार का है, चाहे हत्या का है।

Irregular Supply of Drinking Water

***1100. Shri Dhir Pal Singh :** Will the Minister for Public Health be pleased to state—

(a) the number of villages of Jhajjar and Bahadurgarh Sub-Divisions which are facing drinking water problem; and

(b) if so, the steps taken or preposed to be taken to provide regular supply or drinking water in the villages as referred to in part (a) above ?

जन स्वास्थय मंत्री (श्रीमती शान्ति देवी राठी):

(क) उप–मण्डलवार गांवों का व्यौरा जहां पेयजल समस्या गम्भीर है निम्न– लिखित हैं –

झज्जर उप–मण्डल	27
बहादुरगढ़ उप–मण्डल	4

(ख) इन गांवों में पीने के पानी की कमी का मुख्य कारण नहरी पानी का अपर्याप्त माता में, उपलब्ध होना है। फिर भी जून, 1996 के अन्त तक 14 गांवों में स्वीकृत अनुमानों के अन्तर्गत कम गहराई वाले नलकूप लगाकर पेय जल उपलब्ध कराने की संभावना है। झज्जर उप–मण्डल के शेष 13 गांवों मै रेयन न समस्या केवल पर्याप्त मात्रा में नहरी पानी उपलब्ध होने पर ही दूर की जा सकती है क्योकि इस क्षेत्र मैं भूगर्भ जल स्त्रोत खारा होने के कारण कम गहराई वाले नलकूप लगाना संभव नहीं है। जहांतक बहादुरगढ उप–मण्डल का सम्बन्ध है, दो गांवों में पेय जल व्यवस्था स्वीकृत अनुमान के अन्तर्गत कम गहराई वाला नलकूप लगवाकर प्रदान करने की सम्भावना है, परन्तु शेष 2 गांवों में नहरी पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने पर ही सुधार होगा।

श्री धीर पाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री साहिबा ने यह स्वीकार किया है कि झज्जर उप–मण्डल में 27 और बहादुरगढ़ उप–मण्डल में 4 गांव ऐसे हैं, जहां पेयजल की समस्या गम्भीर है। उनका टोटल 31 बनता है। इसी तरह की आशंका मैंने कल भी जाहिर की थी, मैं तो यही कहूंगा कि झज्जर सब–डिवीजन में व बहादुरगढ़ सब–डिवीजन में सरकार ने नहरी पानी का स्वयं ही बेड़ा गर्क कर दिया है, सारा पानी हमसे इन्होंने छीन लिया। लोग पानी के लिये तरस रहे हैं। पानी का गम्भीर संकट इन इलाको में आ गया है। मैं मुख्य मन्त्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि 1991 से पहले का ये रिकार्ड उठा कर देख लें तब आज के अनुपात से पानी ज्यादा आता था। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदया से जानना चाहता हूं कि जो इन्होंने अपने जवाब में माना है कि 14 गांवों में जून, 1995 तक शैलो टयूबवैल्ज लगाकर पेयजल उपलब्ध कराने की सम्भावना

है, यह स्कीम किन–किन गांवों की है और इन पर कितनी राशि लगने की सम्भावना

श्रीमती शान्ति देवी राठीः अध्यक्ष महोदय, झज्जर उप–मण्डल के 27 गांवों में से 10 गांवों में कम गहराई वाले ट्यूबवैल्ज लगाये जा चुके है और उन पर खर्चा आया है 3.52 करोड़ रुपये। शेष 9 गांवों में हमारी जो योजना है, वह विभाग के अनुसार जून, 1995 तक की है लेकिन मैं इस हाउस में कहती हूं कि जुलाई–अगस्त 1995 तक इन गांवो में कम गहराई वाले ट्यूबवैल्ज लग कर तैयार हो जाएंगे जिन पर लागत आएगी लगभग 1. 65 करोड़ रुपये। शेष जो 8 गांव और बच गए हैं, उनकी समस्या तब हल हो जाएगी जब कि सिंचाई विभाग पीने के पानी का पूरा प्र बन्ध करेगा। अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपने विभाग के बारे में दो–तीन बातें विस्तार से कहना चाहूंगी। जहां तक जन स्वास्थ्य विभाग का सम्बन्ध है, यह अन्य दो विभागों पर डिपैन्ड करता है। वैसे हमारे अपने बहुत सुयोग्य इंजीनियर्ज हैं और पैसे का भी विशेष अभाव नही है क्योंकि वर्ल्ड बैंक की सहायता हमें मिल रही है। हरियाणा के अन्दर जो विकास के कार्य हो रहे हैं, वैसे तो अध्यक्ष महोदय आप पूरी तरह से जानकार हैं। इस बारे में, विकास के प्रतीक आदरणीय मुख्य मन्त्री महोदय से यह कहूंगी कि अगर वे इस मात्रा को सुनिश्चित केर दें कि जहां–जहां हमारा कैनाल बैस्ड सिस्टम हैं, उसके अन्तर्गत सिचाई का पानी कही जाये या न जाए लेकिन स्वच्छ पानी लोगों तक अवश्य ही जाएगा। इसके साथ –साथ सिंचाई विभाग को भी वे कड़े आदेश इस बारे में दे दें कि कैनाल बेस्ड स्कीम्ज के तहत पानी टेलों तक अवश्य जाना चाहिये। जो गाद नहरों में जम गई है, उसको तुरन्त ही निकलवाया जाए ताकि सभी टेलों तक आगे पानी जा सके। मुख्य मन्त्री जी, दूसरी बात यह है कि आप बिजली विभाग को कडे आदेश दें कि जैसे ही हमारा ट्यूबवैल तैयार हो या जल घर तैयार हो तो वे हमे

फौरन कनैकशन दे दें। कंडक्टर हमारा अरना विभाग देता है और खम्भे वे लगाते हैं। वे फौरन खम्भे लगा दें। (शोर)

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब यह मन्त्री जी कैसा जवाब दे रही हैं ? यह तो इनकी कैबिनैट का मामला है। (शोर)

Mr. Speaker : Shanti Devi ji, please take your seat. All the departments of the Government are one and difieron departments are not water tight compartments. This is a matter of coordination of the functions of the Government.

श्रीमती शान्ति देवी राठीः मैं अपने आदरणीय मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध कर रही हूं कि अगर ऐसा हो जाए तो सारी समस्याएं हल हो जाएगा और लोगों को पीने का पानी मिल जाएगा।

चौधरी जिले सिंह जाखडः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया से जानना चाहता है कि इन 27 गांवों में पानी की कमी कब से है? इसके अलावा, जिन गांवों में मीठा पानी है, क्या उनमें भी ऐसे टयूबवैंल्ज लगाने की कोई स्कीम विचाराधीन है?

श्रीमती शान्ति देवी राठीः ऐसे गांवों की डिटेल आपके पास हो सकती है। अगर आप कुछ गाँव सुनिश्चित कर दे कि इनमें मीठा पानी है तो विभाग वहां टयूबवैल लगा देगा। जहां तक यह बात है कि 27 गांवों में पानी की कमी कब से है, यह आपकी सरकार के समय की समस्या है। हमने तो दस गांवों का समाधान कर दिया है और 9 गांवों में ट्यूबवैल लगा दिए है। बाकी के गांव कैनाल वाटर बेस्ड है।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ः स्पीकर साहब, आज हालत यह है कि वाटर सप्लाई स्कीम की जगह पर बच्चे क्रिकेट खेत्र रहे हैं।

श्रीमती शान्ति देवी राठीः यह तो अच्छी बात है कि बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। (शोर)

श्री धीर पाल सिंहः स्पीकर साहब मंत्री महोदया ऐसा ..... जवाब दे रही हैं। आज विरोधी पक्ष के हल्कों में वाटर सप्लाई स्कीमें सूखा पड़ी है अँ ओर वहां पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे है। और ये कहती हैं कि अच्छी बात हे कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं ऐसो बात कहते हुए इनको ..... आनी चाहिए। (शोर)

श्री अध्यक्षः ये शब्द रिकार्ड पर न लाये जाएं

10.00 बजे

श्री धीर पाल सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री महोदया ने जिन 9 गांवों में शेलो टयूबवैल लगाए हें, उनके नाम बताए हैं और यह भी बताया है कि इतने गांवों में और लगाने हैं। स्पीकर साहब, पिछले सैशन में भी मैंने यह आपति जाहिर की थी, उस समय कंवर साहब इस विभाग के मंत्री थे और आज भी मैं बहन जी को यह जान– कारी देता हूं कि खुगाई गांव की पंचायत ने अपने पैसे से वहां पर टयूबवैल लगाया हैं ओर उस टयूबवैल की बिजली का खर्चा खुद गांव के लोग उठा रहे हैं। उस समय मुण्डा खेड़ा गाव के बारे में यह आश्वासन दिया गया था कि दो महीने के अन्दर उस गांव में पीने के पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी लेकिन आज 8 महीने हो गए। उस गांव में आज तक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। उस गांव के साथ एक इसमाईलपुर गांव है। वहां पर शैलो टयूबवैल है। उसके साथ उसको कनैक्ट किया हुआ है, लेकिन उस टयूबबैल का बिजली का कनैक्शन न मिलने के कारण काम अधूरा पड़ा है। उस ट्यूबवैल को बिजली का कनैक्शन नहीं मिल पा रहा है। मंत्री महोदया ने जिन 9 गांवों में शैलो टयुबवैल लगवाए हैं, उनके बारे में मती महोदया यह बता दे कि किस–किस गांव में कब–कब शैलो

ट्यूबवैल लगवाएं हैं और उनको बिजली का कनैक्शन कब तक दिला कर पीने का पानी मुहैया करवा देंगे?

श्रीमती शांति देवी राठीः स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य को उन 27 गावों के नाम बता देती हूं। वे हैं सिलानी, फिर सिलानी, सिलाना, कछरौली, घिराना, खेड़ी होसदरपुर, हसनपुर, कछरौली, कालीबास, धिराना, मरोट, खेडी होसधरपुर, हसनपुर, रणखेडा, खु गाई, बजीदपूर, टखल चना, टम्बाधेडर, उसमानपुर, नीयोला, गवालोसोन, मरोट, सुभाना, खानपुर, खेडी होसादपुर, गिजरोध और हसनपुर गिजरोध।

श्री सूरजमलः स्पीकर साहब, बहादुरगढ़ में वाटर सप्लाई स्कीम के म्यूनिसिपल कमेटी कैं दो टैक हैं उनमें दो–दो अढ़ाई अढ़ाई फुट गाद जमी हुई है। उनकी सफाई नहीं हुई है। तकरीबन वन–थर्ड पानी उनमें कम आता है। इसी तरह से जो जो हुड्डा को नहर गुड़गांव जाती है, उसमें भी गाद जमी हुई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि उस नहर की और उन दोनों टैकों की सफाई कब तक करवाने का प्रावधान है, क्या उनकी सफाई करने का कोई सिस्टम बना रखा है? जो हुड्डा की नहर गुड़गांव जाती है क्या उसका पानी बहादुरगढ़ शहर के लोगों को पीने के लिए मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितना हिस्सा मिलेगा?

श्रीमती शांति देवी राठीः स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने इस बात को स्वीकारा है कि नहर में गाद काफी जमी हुई है, उसकी वजह से जल स्तर कम हुआ है और पानी पूरी मात्रा में नहीं आ रहा है। जहां तक उनकी सफाई की बात है वह हमारा विभाग अवश्य करवा देगा, क्योंकि उसमें पानी आना अनिवार्य है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारी जो कनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम्ज हैं, उनकी गाद निकाली जाए ताकि पानी पूरी माला में आए। मैं आपकी जानकारी के लिए

बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों गाद निकालने का कम युद्ध स्तर पर हुआ है। मेरे खुद के हल्के की राजपुरा माईनर में गाद जमने के कारण टेल पर पानी आने में दिक्कत थी, लेकिन अब उसकी सफाई कर दी गई है और अब उसकी टेल पर दो फुट पानी आता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि चालू वित्तीय वर्ष में गाद निकालने का काम युद्ध स्तर पर हुआ है।

श्रीमती चन्द्रावतीः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने माना है कि पीने के पानी के लिए नहर के पानी पर निर्भर करना पड़ता है। मैं मती महोदया से जानना चाहूंगी कि जहां पर मीठा पानी है, क्या वहां पर बोरिंग वैल के जरिए पानी लोगों को मुहैया करवाएगी?

श्रीमती शांति देवी राठीः सरकार का यह दायित्व है कि प्रत्येक नागरिक को पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध हो। बहन जी जहां–जहां पर बोरिंग वैल्ज की लिस्ट देंगी और वहा पर मीठा पानी होगा, ऐसी जगहों पर बोरिंग वैल्ज लगाने का काम युद्ध स्तर पर करके लोगों को पानी उपलब्ध करवाएंगे।

श्री राम भजन अग्रवालः क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि स्टेट में शैलो टयूब– वैल्व कुल कितने हैं? दूसरे मैं यह जानना चाहूंगा कि जिन गांवों के लोगों ने अपने खर्च पर शैलों टयूबवैल्ज लगा रखें हैं, क्या सरकार उनका खर्च वहन करेगी?

श्रीमती शांति देवी राठीः सरकार ऐसे टयूबवैल्ज का खर्च वहन नहीं करेगी। नहरी पानी का जहां तक सवाल है, जहां पर भी गाद होगी उसको निकलवाने का काम पूरा करेंगे और टंकियों की भी सफाई करायेंगे।

चौधरी जिले सिंह जाखडः वैसे तो यह सारे हरियाणा की समस्या है। क्योंकि जी पानी की टैंकी है, उसका टेल पर पानी नहीं पहुंच पाता। क्या वहां पर

पानी पहुंचाने का प्रबंध सरकार करेगी? दूसरे किन–किन गांवो में मीठा पानी है, क्या उनका सर्वे सरकार करवायेगी?

श्रीमती शांति देवी राठीः टेल पर पानी पहुंचाने के लिए हम सुनिश्चित करेंगे। सरकार यह भी पता लगवा लेगी कि कहां–कहां पर मीठा पानी है।

श्री धीर पाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, बहादुरगढ़ में 9 गांव ऐंसे हैं जहां पर शैलो टयूबवैल्ज नहीं और ये गांव कैनाल वाटर पर आधारित हैं। मेरा कहना यह है कि हुड्डा की जो गुड़गांव कैनाल है क्या उससे इन गांवों को सामूहिक रूप से पीने के पानी का कनैक्शन दियां जायेगा?

श्रीमती शांति देवी राठीः इस समय तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे पूरी जानकारी इस स्कीम की नही है। यदि होने वाले। बात हुई तो हम पानी उपलबध करवाएंगे।

Amount spent on Desilting of Canals in Bhiwani District

***1028 Prof. Chhattar Singh Chauhan :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state the yearwise and canalwise amount spent on the desilting of Canals in Bhiwani District during the period from 1990 to July, 1994?

सिंचाई मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा): नहरों में से गाद निकालने का कार्य वर्ष 1990– 91, 1991– 92, 1992–93 तथा 1993– 94 और 1 –4–94 से 31– 7–94 तथा 1– 4– 94 से 28– 2–95 में किया गया। प्रत्येक नहर पर किए गए खर्च की राशि का ब्यौरा निर्धारित तालिका में संलग्न एनैक्रच– 1 में दर्शाया गया है।

अनैक्श्चर– 1

जिला भिवानी में पड़ने वाली प्रत्येक नहर से प्रतिवर्ष गाद निकालने का खर्चा

क्रमांक	नहर का नाम	गाद निकालने पर किया गया खर्चा रु ० लाखों में					
		1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95 1-4-94 से 31-7-94	1-4-94 से 28-2-95
		3	4	5	6	7	8
क.	यमुना जल सेवाएं परिमण्डल भिवानी						
	भिवानी जल सेवाएं मण्डल भिवानी						
1.	भिवानी डिस्ट्रिव्यूटरी	2.26	0.87	0. 59	0.05	-	3.90
2.	दादरी "	3.35	0.38		0.77	-	1.14
3	सुन्दर "	3.90	0.93	0.30	1.29	-	0.18
4.	बान्द "	1.04	0.17	0.18		-	0.45
5.	गुजरानी माईनर	3.20	0.19	0.21	0. 59	-	2.27
6.	उमरा "	-	0.89	0.20	-	-	-
7.	बवानी खैड़ा "	0.45	0.80	0.30	-	-	-
8.	खनक "	0.39	0.25	0.18	-	-	2.02

9.	तालू "	0.82	1.75	0.28	1.05	-	-
10.	बलियाली सब "	0.20	0.31	-	0.14	-	-
11.	भुरताना माईनर	0.74	1.01	0.32	0.48	-	-
12.	धमाना "	0.49	0.72	-	0.10	-	-
13	कैस "	0.77	0.30	-	-	-	-
14.	तिगड़ाना सब माईनर	0.20	0.05	-	0.05	-	-
15.	बापोड़ा, "	0.24	0.15	0.10	0.02	-	-
16.	मैणी माहु "	0.15	0.20	-	-	-	-
17	कुसम्भी "	0.19	0.23	-	-	-	0.20
18.	फोगाट, "	0.12	-	-	-	-	-
19.	सांगा "	0.31	0.13	-	-	-	0.74
20.	बहलवा "	0.19	0.14	0.1i	-	-	0.25
21.	भांगवी "	0.18	-	-	-	-	-
22.	डांग "	3.61	0.63	0.95	0.25	-	1.50
23	सूई सब माईनर	0.12	-	0.06	0.01	-	0.10
24.	पालूवास "	0.04	-	-	-	-	0.05

25.	मानहेरू "	0.50	0.16	-	-	-	1.70
26	साझरवास माईनर	0.46	-	0.12	0 56	-	1.58
27.	भांगेसवरी "	0.13	-	0.16	-	-	0.47
28.	हालूवास "	0.08	0.72	0.12	0.14	-	0.20
29.	1 एल डांग "	0.29	-	-	-	-	0.26
30.	रनकौली सब "	0.06	-	-	-	-	-
31.	खरक कलां माईनर	0.19	0.14	-	0.59	-	0.26
32.	बामला "	0.18	0.86	0.28	1.41	-	1.01
33.	मिसरी "	0.12	-	-	0.07	-	-
34.	पुलपूरा "	0 .05	-	-	-	-	-
35.	राजपुरा सब "	-	0 .11	0.06	0.01	-	-
36.	बगड़ "	-	0.25	0.17	-	-	-
37	भैणी भैयो माईनर नं ० 1	-	0. 10	-	-	-	-
38.	दादरी फीडर	-	0.88	-	-	-	0.05
39.	बढेसरा माईनर	-	0.25	-	-	-	-
40	रिवासा "	-	0.24	-	0.24	-	-

41	मिथाथल फीडर	-	0. 02	-	0.17	-	0. 46
	जल सेवाएं मण्डल भिवानी						
1.	जुई फीडर	0.59	0. 35	-	-	-	0.96
2.	जुई कैनाल	0.86	0.66	0. 24	-	0.54	-
3.	बहल डिस्ट्रीब्यूट्री	0.86	0 39	-	0.20	1.03	1.64
4.	मालावास माईनर	-	-	-	0.08	-	0.07
6.	धौराना "	0.60	0.40	0.02	0.31	-	0.18
6.	देवसर सब "	-	9.20	0.16	-	-	-
7.	केहरपूरा "	0. 18	0.15	-	-	-	-
8.	1 एल माई	0.11	-	0.09	-	-	-
9.	टिटानी "	-	0.26	0.09	0.51	-	0.15
10.	1 आर सब माईनर	0.11	0. 08	-	-	-	-
11.	चौनपुरा माईनर	0.22	0 16	0. 11	0.14	-	-
12.	नकटा "	0. 27	0.19	0.10	0. 25	-	-
13	लेधा "	0. 41	0, 37	0, 18	0.15	-	3. 27
14.	शिमलीवास सब माईनर	0.03	0. 07	0. 00	0 05	-	-

15.	ढांगर माईनर	0.26	0. 13	0.09	0. 13	-	0. 11
16.	खारीयावास "	0.99	0.89	0. 13	0.34	-	0.53
17.	2–आर सब "	0.04	-	-	-	-	-
18.	पाथरवाली "	1.02	0.89	9.37	0.98	-	0.50
19.	ढाभढ़ाणी सब "	-	0.12	-	-	-	-
20.	लालावास "	0.64	0. 43	-	O. 12	-	-
21.	ओबेरा	0. 18	0.48	-	-	-	-
22.	बिजियाना सब "	0.22	0.17	-	0.08	-	-
23.	बरथु सब माईनर	0.08	-	0. 30	-	-	-
24.	देवरासा सब माईनर	0. 09	0.17	0.09	0. 10	-	-
25.	गौकलपुरा "	0. 19	0. 19	-	0.13	-	-
26.	बिदनोई सब "	0.14	0.10	0.20	0.12	-	-
27.	कासनी "	0.10	0.09	-	0.05	-	-
28.	8 आर सब माइनर	0.27	0.15	-	0.17	-	-
29.	सुरपूरा माईनर	0.09	0.27	0.31	0.09	-	-
30.	गिरवा "	9.03	-	-	-	-	-

31.	निगाना फीडर	0.92	0.37	-	-	-	-
32.	निगाना कैनाल	0.47	1.11	0.28	0.39	-	-
33.	खड़कड़ी डिस्ट्रीव्यूट्री	-	-	0.05	-	-	0.08
34.	निगाना "	0.66	0.29	-	0.73	-	-
35.	निगाना हिल "	0.42	0.27	0.20	-	-	0.13
36.	दुलहेड़ी "	0.17	0.33	0.12	-	-	0.22
37	माहू डिस्ट्रीव्यूट्री	0.40	0.50	-	0.25	-	0.26
38.	गूधा "	0.20	0.11	0.06	-	-	-
39.	झावेरी "	-	0.18	0.08	-	-	-
40.	सरल "	0.10	0.20	0.14	-	-	0.12
41.	आलमपूर "	0.19	-	-	-	-	-
42	बावम "	0.44	0.40	-	0.19	-	-
43.	बादम हील "	0.27	0.19	-	0.12	-	0.04
44.	बालाबास "	0.85	0.72	-	-	-	-
45.	सागवान माईनर	0.20	0.25	0.15	-	-	0.72
46.	मानसरवास "	0.15	0.07	0.04	-	-	-

47.	बागनवाला "	0.36	0.30	-	0.16	-	0.05
48.	कावारी माइनर	0.54	0.20	-	-	-	0.17
49	कांवरी सब "	0.35	0.16	-	0.23	-	0.54
	सिवानी जल सेवाएं मण्डल भिवानी						
1.	सान्धवास डिस्ट्रीब्यूट्री	0.32	0.40	0.38	-	-	-
2.	भरीवास माईनर	0.40	0.59	-	-	-	-
3.	बदौला "	0.51	0.40	-	-	-	-
4	हसन डिस्ट्रीब्यूट्री	0.15	0.59	-	-	0.38	-
5.	साहलेवाला माईनर	0.19	0.20	-	-	-	-
6.	सलीमपुर डिस्ट्रीब्यूट्री	-	0.79	-	-	0.50	-
7.	शिधानूवा माईनर	0.15	--	-	-	-	-
8.	धारापुर डिस्ट्रीब्यूट्री	-	-	-	-	-	-
9.	भूधानी माईनर	-	-	-	-	-	-
10.	बेनी मिरा माईतम	-	-	-	-	-	-
11.	धाणीधीरजा माईनर	-	-	-	-	-	-
12.	गोदवा डिस्ट्रीव्यूट्री	-	-	-	-	-	-

13.	किरण डिस्ट्रीब्यूट्री	-	-	-	-	-	-
14.	एन डी फीडर	-	-	-	-	-	-
15.	शेरपुरा डिस्ट्रीब्यूट्री	-	-	-	-	-	-
16.	गुफा माईनर	-	-	-	-	-	-
17.	मिथी डिस्ट्रीब्यूट्री	-	-	-	-	-	-
18.	गोसियान वाला माईनर	-	-	-	-	-	-
19.	गगला माईनर	-	-	-	-	-	-
20.	मथौली माईनर	-	-	-	-	-	-
21.	ममैतीपुरा माईनर	-	-	-	-	-	-
(ख)	लोहारू जल सेवाएं परिमण्डल, भिवानीं						
1.	उमरावास माईनर	0.11	0.13	0.04	0.06	-	-
2.	हूडी वाला डिस्ट्रीब्यूट्री	0.55	-	-	-	-	-
3.	रूपगढमाईनर	0.20	0.28	-	0.52	-	0.52
4.	बिजना माईनर	0.13	0.06	0.06	-	-	0.10
5.	अटेरना डिस्ट्रीब्यूट्री	0.19	0.15	0.24	0.24	-	0.08
6.	मेहरा	0.21	0.15	0.12	0.12	-	-

7.	नोगल माईनर	0.20	0.07	-	-	-	-
8.	कूराल डिस्ट्रीब्यूट्री	0.50	0.46	0.27	0.44	-	-
9.	दूधवा माईनर	0.07	-	0.10	-	-	-
10.	पेतावास "	0.06	-	0.08	0.06	-	-
11.	पटवान "	0.03	-	-	-	-	-
12.	पोखरवास "	0.05	-	-	-	-	-
13.	सिसवाल सब "	0.32	0.08	-	0.40	-	0.18
14.	कालूवाला "	0.04	0.07	-	0.03	-	-
15.	पोखर सब माईनर	0.13	0.05	0.05	-	-	-
16.	गीरी पुर "	0.06	0.03	-	-	-	-
17.	गोढम "	0.21	-	0.20	0.23	-	-
18.	बरही "	0.06	-	-	0.07	-	0.11
19	कतिलाना डिस्ट्रीब्यूट्री	0.88	1.00	0.39	0.10	-	0.10
20.	जोझू माईनर	0.19	0.16	0.06	-	-	-
21.	रेहरोथो डिस्ट्रीब्यूट्री	0.14	0.64	0.06	0.20	-	-
22.	पेहलगांव गढ़ सब माईनर	0.10	0.05	-	0.16	-	•.10

23.	बुध वाना डिस्ट्रीब्युट्री	0.34	0.83	0.12	0.72	-	0.73
24.	गोंठडा डिस्ट्रीब्यूट्री	0.31	-	-	-	-	-
25.	खेरपूरा माईनर	0.07	0.10	-	0.64	-	-
26.	तोही "	0.12	0.13	0.06	-	-	-
27.	रामपूरा "	0.25	-	-	-	-	0.07
28.	वाडीबास सब "	-	0.4	0.04	-	-	-
29.	गुढाणा "	-	0.03	0.10	0.09	-	-
30.	पिछोपा "	-	.14	-	0.10	-	0.16
31.	नगला सब "	-	0.05	-	-	-	-
32.	खेड़ीसमवाल "	-	0.18	0.03	0.10	-	0.09
33.	पिछोपा कलां डिस्ट्रीब्यूट्री	-	0.19	-	0.20	-	-
34.	असवाड़ी सब माईनर	-	0.15	0.03	-	-	-
35.	खेड़ा बुरा माईनर	-	0.09	0.06	-	-	0.04
36.	पकडाना सब "	-	0.13	0.04	-	-	0.06
37.	गोठड़ा सब "	-	0.11	-	-	-	-
38.	दादरी सब "	-	0.03	-	-	-	0.G3

39.	1 आर दादरी सब ″	-	0.02	-	-	-	-
40.	कलाली सब ″	-	-	0.18	-	-	-
41.	गोकल डिस्ट्रीब्यूट्री	-	-	0.15	0.62	-	0.23
42.	पम्प हाऊस नं० 3 लोहारू कैनाल	-	-	1.00	-	-	-
43.	पम्प हाऊस नं० 2 लोहारू कैनाल	-	-	1.20	-	-	-
44.	पम्प हाऊस नं० 1	-	-	-	1.02	-	-
45.	पम्प हाऊस नं ० 4 लोहारू कैनाल	-	-	-	0.83	-	-
46.	लोहारू कैनाल	-	-	-	0.15	-	0.20
47.	दमकौरा डिस्ट्रीव्यूट्री	0.53	0.18	0.58	0.99	-	-
48.	झूपा डिस्ट्रीव्यूट्री	0.81	0.04	0.31	0.16	-	-
49.	बिछिना सब माईनर	0.10	0.19	-	-	-	-
50.	जाड़ा बास डिस्ट्रीब्यूट्री	0.89	0.48	-	-	-	-
51.	सोरा ″	0.40	1.57	0.11	0.36	-	-
52.	सोरी माईनर	0.13	-	-	-	-	-
53.	मैकीपूर ″	0.66	0.79	-	-	-	-
54.	बहल माईनर	0.13	-	-	-	-	-

55.	डिगांवा सब	0.07	-	0.06	-	-	0.29
56.	उन	0.06	-	-	-	-	-
57.	लौहारू डिस्ट्रीव्यूट्री	0.59	0.10	0.32	0.51	-	-
58.	गोबिन्द पुरा माईनर	0.13	-	0.06	-	-	-
59.	डगरोली डिस्ट्रीब्यूट्री	0.19	-	-	-	-	-
60.	बढ्धु चना माईनर	0.08	-	-	-	-	-
61.	ककरौली "	0.13	0.16	-	-	-	-
62.	बाढ़डा माईनर	-	0.37	-	-	-	-
63.	पम्प हाऊस न ०6, लोहारू कैनाल	-	0.04	0.05	0.41	-	0.50
64.	जाझड़ा माईनर	-	0.06	-	-	-	-
65.	नंथा "	-	0.09	-	-	-	-
66.	हसन पुर "	-	0.19	0.19	-	-	-
67.	सिधनियां "	-	0.07	0.09	-	-	-
68.	बुढेरी "	-	0.08	-	-	-	-
69	पम्प हाउस न ० 8, लोहारू कैन	-	0.01	0.09	-	-	-
70.	पम्प हाउस नं० 7 लौहारू कैनाल	-	0.06	0.07	-	-	-

71	जैवाली माईनर	-	0.03	0.04	-	-	-
72.	खैड़ी टीका सब माईनर	-	0.06	0.12	-	-	-
73.	डबरका माईनर	-	0.08	0.04	-	-	-
74.	भौपाली माईनर	-	0.08	-	-	-	-
75.	व्हेर खौड ″	-	0.15	-	-	-	-
76.	श्याममा ″	-	0.06	-	-	-	-
77.	सिरसो सब ″	-	0.05	-	-	0.05	0.05
	कुल योग =	10.59 लाख	9.97 लाख	6.35 लाख	8.86 लाख	2.45	37.40
	कूल योग क + ख =	53.16	39.77	15.26	21.94	2.45	37.40

प्रो० छतर सिंह चौहानः अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी ने अनेसचर में जो फिर्ग्ज दी हैं अलबत्ता ये सारी फिर्ग्ज ही मैनिपुलेटिड हें। हैरानी की बात है कि दादरी फीडर पर 1–4–1993 से ले कर 28–2–1895 तक 15 हजार रुपये खर्च किए गए हैं। भाई आनन्द सिंह मंगी यहां पर हाउस में बैठे हुए हें। उनका गांव दादरी फीडर के ननदीक पड़ता है। वे भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि नहर में 4 या साढे चार फुट तक मिट्टी है, जूई कैनाल में 20 हजार रुपये खर्च किए गए हैं। दादरी फीडर में 5000/– रुपये, लोहारू मेन कैनाल में 6000 रुपये खर्च किए गए दिखाए टैप। अध्यक्ष महोदय, मैंने इनके महकमे को बार–बार लिख कर दिया कि डी–सिल्टिंग करवाएं और उन्होंने लिख कर दिया है कि 1987 से लेकर 1994–95 तक उनकी डी–सिल्टिग नहीं की गई है। चाहे वह लोहारू कैनाल हैं, सिवानी कैनाल है, दादरी फीडर है, दादरी डिस्ट्रीव्यूटरी है, बौन्द डिस्ट्रीब्यूटरी है, लोहारू कैनाल माईनर है, इसमें इतनी लम्बी चौड़ी लिस्ट मन्त्री जी ने दी है जिसमें से 5– 10– 20 हजार रुपये तक खर्च हुए दिखाए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, ने माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो 5 से 10–20 हजार तक पै सा खर्च किया गया है, क्या यह वास्तव में खर्च किया गया है या केवल कागज काले किए गए हैं? अध्यक्ष महोदय, सभी कैनाल्ज की डी–सिल्टिंग नहीं की गई है। माईनर्ज और सब–माईनर्ज टूटी हुई हैं। माननीय बहन शान्ति देवी राठी जी ने माना है कि नहरों की डी–सिल्टिग नहीं हुई है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रता है। बिजली मन्त्री लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं (विघ्न)

श्री अध्यक्षः चौहान साहब, आप सवाल पूछें।

प्रो० छतर सिंह चौहानः अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जो से यह जानना चाहता हूं कि दादरी फीडर, लोहारू कैनाल, सिवानी कैनाल की सफाई कब तक करवा देंगे कि नम्बर दो, मैं मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि केवल भिवानी जिला ही नहीं, पूरे दक्षिणी हरियाणा में पानी नाम मातं का जाता है। स्पीकर सर, पिछली बार भी मैंनै आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री महोदय का ध्यान इस बात की तरफ दिलाया था कि सिरसा और हिसार जिलों में नहरों में 24 से 26 दिन मही ने में पानी चलता है जब कि भिवानी में महीने में 3 या साढ़े तीन दिन ही पानी चलता है। (विध्न)

श्री अध्यक्षः आप सवाल पूछिये, भाषण मत दीजिए। आपका सवाल क्या हैं?

प्रो० छतर सिंह चौहानः स्पीकर सर, मैं सवाल पर ही आ रहा हूं। रनर नहरों से मिट्टी नहीं निकाली जाएगी तो फिर नहरों में कहा से पानी जाएगा? पूरे हरियाणा मैं केवल दो ही जिले हैं जो पानी से डुबे हुए हैं। बाकी सारे प्रान्त में सारे जिलों में से कहीं पर भी पूरा पानी नहीं जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह आश्वासन चाहूंगा कि वे क्या डी–सिल्टिग का काम जल्दी करवाएगे? हसके साथ ही मैं उनसे यह भी पूछना चाहूंगा कि दादरी फीडर, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी और माईनर्ज, लोहारू क्लौलु– माईनर्ज, डिस्ट्रीव्यूटरी की डी–सिल्टिग कब तक करवा देंगे? (विघ्न) इसके साथ ही इन्होने रिप्लाई में दिया है 1 –4–1994 से 31 –4–94, 1–4– 94 से 28–2– 95 यह डेट में जो ओवर राईटिंग की है, उसका क्या कारण है? जो आज तक डी–सिल्टिंग नहीं हुई है, उसका क्या कारण है तथा डी–सिल्टिग के लिए वे क्या कर्णे प्रबन्ध करवाएंगे?

चौधरी जगदीश नेहराः अध्यक्ष महोदय, डी सिल्टिंग की जहां तक यात, है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में डी–सिल्टिग में दिक्कत है। यह बात हम मानते हैं। इसके साथ ही मैं इनको बताना चाहूंगा कि हर साल का यह प्रोसैस है। जैसे कि पहले भी इस बारे में असैम्बली में सवाल उठता रहा है और उसके जवाब में भी बताया गया है कि भाखड़ा में उतनी सिल्ट नहीं आती जितनी कि यमुना में आती है। यमुना में सिल्ट ज्यादा आती है, जिससे उसमें सिल्ट ज्यादा हो जाती है। यह सब अनैक्सचर में दिया हुआ है। साथ में उनके नाम भी दिए हैं। भिवानी डिस्ट्रिक्ट में 206 माईनर्ज हैं और उनके बारे में भी डिटेलवाईज दिया हुआ है। उसमें यह भी दिया है कि इतने–इतने पैसे वहां पर लगे हैं। अगर इनको कोई शिकायत है तो ये हमें बताएं कि फलानी जगह पर इतना पैसा नहीं लगा है। हम अधिकारियों की खिंचाई करेंगे। इन्होंने भिवानी सर्कल की बात छोड़ दी और लोहारू सर्कल की बात कर रहे हैं। उस बारे में भी मैंने बताया है और उसकॉ भी ब्यौरा दिया है। ये उमरावास माईनर, रूपगढु माइनर, बिजना माईनर, अटेला डिस्ट्रीब्यूटरी, मेहरा, नांगल, कूराल, दूधवा पेतावास, पोखरवास, कालूवाला, गोरीपुर, पोखर सब–माईनर्ज, कतिचाना डिस्ट्रिव्यूटरी और पेहलगावगढ सबमाइनर इत्यादि हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इन्होंने सवाल नहीं किया बल्कि लैक्चर दे दिया है। इतनी सारी माईनर्ज हैं और इन सब पर इकट्ठा काम नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना पैसा नहीं है। इन्होंने लोहारू में जुई, सिवानी और दादरो फीडर के बारे में कहा। अगर हम इसमें शुरू से आखिर तक काम करें तो सात करोड़ से दस करोड़ तक पैसा लग जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सैकड़ों ही माईनर्ज हैं और इन बारे में मैंने डिटेलज अनैक्स्चर में दे रखी है। इसमें 1–4–94 से लेकर 28–2– 95 तक इतना पैसा कैसे खर्च किया? इस बारे में

इनको यह बताना चाहूंगा कि 1990–91 से 1994 की जुलाई तक ही नहों बल्कि इसके बाद भी काम हुआ है। आगे जो फिगर्ज दी हुई हैं, वह उसके बाद की हैं।

श्री सूरजमलः अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी बात से सन्तुष्ट नहीं हूं, मैं, कमेटी के साथ बहादुरगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी, दुलहेड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी और, लूना माजरा डिस्ट्रीब्यूटरी देखने गया था। वहां पर कोई काम नहीं हुआ है। आप आधे घन्टे में ही ये तीनों डिस्ट्रीब्यूरीज देख सकते हैं। अगर वहां पर डिसल्टिंग हुई हो तो मैं कसूरवार हूं।

चौधरी जगदीश नेहराः अध्यक्ष महोदय, मैंने मौके पर जाकर इनके साथ ही देखा था और इनको अब भी दिखा लेंगे और जहां–जहां पर इनको शिकायत होगी, यहां पर अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेंगे। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बहादुरगढ़, दुलहेड़ा और लूना माजरा का नाम ले लिया।। वहां पर 76 हजार आर० डी ० तक का काम हुआ है। अगर वह नही हुआ है तो ये बताएं और हम उसे मौके पर जाकर देख लेंगे। (विघ्न) हम वहां पर पानी भी पहुंचाएंगे। अध्यक्ष महोदय, यह जो मैंने अनैक्स्चर दिया है उसमें से अगर चौहान साहब, यह बताएं कि कहीं पर काम नही हुआ है, तो हम वहां पर भी काम ठीक करेंगे।

श्री धर्मपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, इनके रिप्लाई मे जैसा कि भिवानी वाटर सर्विसिज डिवीजन, भिवानी में 21 नम्बर पर भागवी माईनर, 33 नम्बर पर मिसरी माईनर, 17 नम्बर पर कुसम्भी सब–माईनर, गोठडा डिस्ट्रीब्यूटरी, तथा लोहारू जल सेवाएं परिमंडल, भिवानी में 56 नम्बर पर उन्न माईनर तथा पम्प हाउसिज नम्बर एक और दो हैं तो क् आपके माध्यम से मत्री जी से यह जानना चाहता हू कि 1996–91 के याद से इन माईनर्ज

और डिस्ट्रीब्यूटरीज पर एक भी पैसा खर्च क्यों नहों किया गया, इसका क्या कारण था, क्या इनमें सिल्ट नहीं है या फिर इन माईनर्ज में पानी नहीं जाता? अगर इनमें 1990– 91 के बाद से कोई भी पैसा खर्च हुआ है तो मैथी जी हमें बता दें। यह सारी माईनजं और डिस्ट्रीब्यूटरीज मेरे हल्के की हैं। स्पीकर सर, मैं गगना चाहता हूं कि मेरे हल्के के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है, क्या मली जी इस बारे में बताने की कृपा करेंगे?

चौधरी जगदीश नेहराः स्पीकर सर, 1990–91, 91– 92, 92– 93 93– 94 और 94– 95 में जैसा मैंने अर्ज किया अलग –अलग पैसों का प्रावधान किया गया है। हमारे पास जितना पैसा है और जहां पर ज्यादा अरजैन्सी है, गाद है, रेत है तो पहले वहां पर हम प्राथमिकता देकर काम करवाते हैं। शायद कुछ नहरें 1992– 93 में ठीक हुई हों और उसके बाद ठीक न हुई हों, तो यह हो सकता है यह रात मैं मानता हूं। रिप्लाई में अलग–अलग साल की फिगर्ज दे दी गयी हैं, लेकिन जिन नहरों में गाद ज्यादा है उनको हम ठीक करवाने की कोशिश करेंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसलाः अध्यक्ष महोदय, जहां तक डिसिल्टिग आफ कैनाल्ज की बात है तो न केवल यह भिवानी जिले में जैसा छत्तर सिंह जी ने बताया बल्कि सारे प्रदेश के अंदर यह एक ऐसा सैंसटिव मुद्दा बन गया है। सारे प्रदेश के अन्दर चाहे हमारे ट्रेजरी बैंचिज के साथी हों और चाहे विपक्ष के सम्मानित साथी हों, में रस बात को लेकर एक बड़ा भारी असंतोष सा है। गवर्नर ऐड्रस पर और बजट पर भी बोलते हुए सभी ने इस बारे में कहा है। इसलिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि खा वे सदन को इस बारे मे आश्वासन देंगे कि डिसिल्टिंग के बारे में क्यो न सारे प्रदेश में एक विशेष कम्पेन चलाई जाए। जो रिक्वायर्ड मनी है

उसको इमीडिएटली देकर क्यों न डिसिल्टिंग का काम शुरू करवाया जाए? पानी की बहुत ही कमी है इसलिए जब तक चौनल साफ नहीं होंगे तब तक पानी किसानों के खेतों में कैसे जाएगा? इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे स्वयं अपनी देखरैख में सारे प्रदेश के अंदर डिसिल्टिंग के लिए एक विशेष कम्पेन चलाएं तथा इस काम के लिए पूरा पैसा भी दें तो क्या आने वाले रेनी सीजन से पहले–पहले नहरों में डिसिल्टिंग के लिए एक विशेष कम्पेन चलाई जाएगी?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि सारा सदन इस बात को लेकर चिंतित है और सारे सदन का इस बारे में चिंतित होना स्वाभाविक भी है। जब किसानो के लिए पानी टेल तक नहीं पहुंचेगा तो किसान के लिए भी मुश्किल हो जाएगी और जो गांव टेल पर पड़ते हैं उनके लिए पीने के पानी की भी मुश्किल हो जाएगी। उन गांवों में पीने के पानी की दिक्कत कई दफा हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, जब यह हमारी सरकार बनी थी तो हमने सरकार बनते ही सबसे पहले यह फैसला लिया था कि वार फुटिंग पर सारे प्रदेश की नहरों और माईनर्ज की सिल्ट निकलवाएंगे यह आपको भी याद होगा।

श्री अध्यक्षः आप यह भी बता दें कि नहरों में यह सिल्ट कब से औंर क्यों हो रही थी?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, सदन में बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा कि 95 परसैन्ट तक माईनरो और नहरों की टेल पर पानी पूरा पहुंच रहा है। इन लोगों ने तो प्रदेश का ऐसा सत्यानाश करके रख था चाहे वह बिजली का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो और चाहे सड़कों का मामला हो। सारी सड़कों की भी हमने मरम्मत वार फुटिंग तक

करवायी। इन्होंने तो अपने राज में सड़क पर एक रोड़ी या बजरी भी नहीं डाली थी और न ही किसी माईनर या नहर की सफाई इन्होंने करवायी थी।

प्रो० सम्पत सिंहः 1990– 91 में तो आपके समय से ज्यादा खर्चा इस बारे में हुआ है यह आपकी हे। स्टेटमैंट है। सर, यह असत्य बोल रहे हैं (विघ्न)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, अब हमने पंचायतों के चुनाव करवाए हैं और हम पंचायतों को भी इसमें इन्वोल्व करेगे, चुने हुए जो नुमाईदे हैं उनको भी इन्वौल्व करेंगे और बाकायदा हम सोचते हैं कि इनकी कमेटी बनाएं कि इस माइनर के लिए, इस नहर के लिए इतना पैसा सफाई के लिए दिया जा रहा है ताकि वे देखलें कि क्या यह पैसा ठीक खर्च हो रहा है या नहीं? हमारी कोशिश होगी कि एक अप्रैल से ज्यादा पैसा नहरों की सफाई के लिए देकर प्रदेश की हर माइनर और नहर की सफाई करने की कोशिश करेंगे ताकि सभी जगह टेल पर पानी पहुंच सके।

Upgradation of Schools of Village Bhagal and Cheeka

***1116. Sh. Amar Singh Dhanday :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the schools at village Bhagal and Cheeka to 10+2 system of district Kaithal ; and

(b) if so, the time by which the above said schools are likely to be upgraded ?

Education Minister (Shri Phool Chand Mulana) :

(a) No.

(b) Question does not arise.

श्री अमर सिंह ढाडेः स्पीकर सर, आपका शिक्षा के प्रति लगाव का है। आपने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सराहनीय काम भी किए हैं। स्पीकर सर,

मेरे चीका– भागल गाँव बहुत बड़े कस्बे हैं वहाँ म्युनिसिपल कमेटी भी है, सैकड़ों बच्चे 10 जमा 2 की शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं। 10 जमा 2 स्कूल के लिए शिक्षा विभाग ने जो शर्ते रखी हैं वह शर्तें भी हमारे दोनों गांव पूरी करते हैं। आदरणीय औम प्रकाश चौटाला जी की लोकप्रिय सरकार ने वहा 10 जमा 2 स्कूल मंजूर किया था लेकिन इस सरकार ने डिग्रेड कर दिए थे। क्या वहां 10 जमा 2 स्कूल बनाने के बारे में पुनर्विचार किया जाएगा?

श्री फूल चन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, चीका में एक डी ० ए० वी० कालेज है और उस डी ० एम बी० कालेज में 10 जमा 2 की क्लासिज भी हैं, इसलिए बच्चों को ज्यादा दिक्कत नहीं है, फिलहाल वहाँ किसी नये 10 जमा 2 स्कूल की आवश्यकता नहीं है।

श्री अमर सिंह ढाडे: अध्यक्ष महोदय, डी ० ए ० वी ० कालेज में इतनी फीस लगती है कि आम बच्चों का पढ़ना वहां मुश्किल है अगर वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल होगा तो गरीब बच्चे भी पढ़ सकेंगे। इसके अलावा डी० ए० वी० में बच्चे भी ज्यादा हैं इसलिए बच्चों का पद्मा मुश्किल होता है।

Ethyl Easter

***1171. Chaudhri Om Parkash Beni :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state -

(a) the nominal value percentage of product the 2,4—D Ethyl Easter Content tested in the State Insecticides Testing Laboratory during the years 1992, 1993, 1994 and 1995 respectively ; and

(b) the number of samples found misbranded/Sub-standard on the basis of tests of 2,4—D Ethyl Faster conducted during the period as referred above alongwith the actual values of misbranded samples ?

Agriculture Minister (Shri Harpal Singh,) :

(a) & (b) The information is placed on the table of the House.

Information

(a) The nominal value of 2,4—D Ethyl Ester was 34% (mass/ mass) during the year 1992, 1993 and 1994. However, the contents of 2,4—D Ethyl Ester has been raised to 38% (mass/mass) from 29-9-1994. The formulation of 2,4—D Ethyl Ester 34% was also permitted by Government of India till 2-3-1995.

(b) The number of samples found misbranded/sub-standard on the basis of tests of 2,4—D Ethyl Easter during the year 1992 to 1995 alongwith the actual values of the misbranded samples are as follows :—

	1992	1993	1994	1995
	31.72%	30.84%	30.26%	21.55%
	31.09%	31.04%	28.57%	22 . 23%
	28.34%	30.06%	31.31%	29.13°
	27.76%	21.97%	31.23%	28 . 8%
	26.9%	30.06%	31.62%	20 . 15%
	27.43%	30.90%		28.61%
	30 82%	29.79%		28 33%
				(Against 38%)
	27.29%	27.22%		
		29.79%		
		29.37%		
		20.96%		
		30.01%		
		31.03%		
		30.9%		
		27.1%		
		30.40%		
		30.40		
		31.32%		

Total :	8	18	5	7

चौधरी ओम प्रकाश बेरीः अध्यक्ष महोदय, मती जीं ने सवाल का जो जनाब दिया है वह तो ठीक हैं लेकिन मैं इनके नोटिस में लाना चाहता हूं और यह सारे स्टेट के इन्ट्रेस्ट की बात है। मैने 1993 में यह वात कही थी कि इन्सैक्टीसाइड टैस्टिंग लैबोरेटरी जो करनाल में है, उसमें जो टैस्टिंग का काम करते हैं उनको टैक्नीकल आदमी करते हैं 15– 15, 20– 20 साल से करनाल में बैठे हुए हैं, वहां से आम तौर पर उनकी भ्रष्टाचार की शिकायत आतीं हैं। और अगर मैं यह कहूं कि टैस्टिंग लैबोरेटरी करनाल भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है तो इसमें कोई गलत बात न होगी। क्या हाउस में मली महोदय इस बात का आश्वासन देंगे कि वहां से पुराने लोगों को तबदील करके नये लोगों को बिठाया जाएगा?

श्री हरपाल सिंहः ऐसा हैं कि यह तो गवर्नमेंट की पालिसी है कि जहां शिकायत आती है, वहां ऐक्शन लिया जाता है और यहां मैं सदन को पूरा विश्वास दिलाता हू कि उसकी हमें बड़ी चिता हूं। हमने वहां का इन्चार्ज बदल दिया था। दूसरे की जब कंपलैंट आई तो उसको बदल दिया। हम कोशिश करते हैं कि ईमान– दार आदमी को लगाएं, जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो, वह लैब में लगाया जाए। जो आदमी वहां ठीक नहीं हैं, पुराने बैठे हुए हैं, उनको हम जरूर शिफ्ट कर देंगे।

श्री अध्यक्षः प्रश्न काल अब समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गऐ तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Supply of Sub-Standard Coal

***1128. Shri Satbir Singh Kadian ; Will** the Minister for Power be pleased to state—

(a) whether the management of Thermal Power Plants have drawn the attention of the Government in regard to the supply of sub-standard coal which leads to more discharge of waste ash than the standard during the years 1992-93, and 1993-94;

(b) if so, the percentage of waste ash discharged by the said power plants, per tonne standard coal ;

(c) the steps taken by the Government to ensure the supply of standard coal to the Thermal Power Plants; and

(d) the total area of land covered under this waste ash in various power plants in the State ?

बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह,):

(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) प्रति टन स्टैण्डर्ड कोयले के हिसाब से बनी बेकार राख निम्न प्रकार से है –

फरीदाबाद थर्मल पावर स्टेशन = 320 से 360 किलो ग्राम

पानीपत थर्मल पावर स्टेशन = 390 से 420 किलो ग्राम

(ग) बेहतर किस्म के कोयले के मुद्दे के बारे में मामला समय–समय पर कोल इण्डिया लिमिटेड/भारत सरकार के साथ उठाया जाता रहा।

(घ) राख निपटान के लिए इन दो थर्मल स्टेशनों पर व्यवस्थित क्षेत्र निम्न प्रकार से है –

फरीदाबाद थर्मल पावर स्टेशन = 225 एकड़

पानीपत थर्मल पावर स्टेशन = 825 एकड

Number of Students in J.B.T. and O.T.

***1145 Shri Azmat Khan :** Will the Minister for Education be pleased to state **the** institutionwise number of students given admission

in J B T. and O. T . courses during the year 1994-95 in the State ?

शिक्षा मन्त्री (श्री फूल चन्द मुलाना): सूचना की तालिका सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

सूचना

सस्थाबार डी ० एड /ओ०टी० में प्रविष्ट छात्र / छात्राओ की सख्या का ब्यौरा

(क) डी० एड अर्थ 1993–95

क्रमांक	संस्था का नाम	प्रविष्ट अभ्यार्थियों की संख्या
1.	डाईट बीसवामील बढमलिक (सोनीपत)	47
2	डाईट मदीना (रोहतक)	96
3	डाईट डींग (सिरसा)	98
4.	डाईट मोहड़ा (अम्बाला)	99
5.	डाईट विरहा कलां (भिवानी)	98
6.	डाईट पलवल (कुरुक्षेत्र)	48
7	डाईट मात्रश्याम (हिसार)	100
8	डाईट महेन्द्रगढ	97
9.	डाईट शाहपुर (करनाल)	49
10.	ईक्कस (जींद)	100
11.	डाईट गुड़गांव	51
12.	डाईन पाली (फरीदाबाद)	102
13.	राजकीय प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान	99

	लोहारू (भिवानी)	
14.	राजकीय प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, आदमपुर (हिसार)	152
15.	राजकीय प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, मोरनी हिल्ज (अम्बाला)	99
16.	राजकीय प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, जीन्द	98
17.	राजकीय प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, राजपुर (सोनीपत)	100
18.	राजकीय प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, ओढ़ा (सिरसा)	100
19.	राजकीय प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, फिरोजपुर नमक (गुड़गांव)	136
20	राजकीय प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, ऐलनाबाद (सिरसा)	100
21.	राजकीय प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, कोल (कैथल)	96
22.	राजदेवी मल्टीपरपज गर्लज कालेज, भेरिया (कुरुक्षेत्र)	39
23	राजीव गांधी मैमोरियल इन्स्टीच्यूट, पंचकुला (अ ०)	40
	कुल योग	2088

(ख) ओ० टी० (हिन्दी)

क्र०	संस्था का नाम	प्रविष्ठ अभ्यार्थियों की सख्या
1.	डाईट गुड़गांव	87
2	डाईट पलवल (कुरुक्षेत्र)	56
2.	राजीव गांधी मेमोरियल इन्स्टीच्यूट, पंचकूला	56
4.	सी ० आरू ० एम० जाट कालेज (हिसार)	56
	योग	225

ओ० टी० संस्कृत

क्र०	संख्या का नाम	प्रविष्ट अभ्यार्थियों की संख्या
1.	डाईट मीसवामील बढमलिक (सोनीपत)	70
2.	डाईट शाहपुर (करनाल)	58
	योग	128

Construction of a Tourism Complex at Pehowa

***1169. Shri Jaswinder Singh .** Will the Minister of State for **Tourism** be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Tourism Complex in Pehowa; if so, the time by which it is likely to be constructed ?

राज्य पर्यटन मन्त्री (श्री लीला कृष्ण): जी हां। पेहवा में एक यातिका बनाने का प्रस्ताव केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ है। भूमि स्थानान्तरण के याद इस परियोजना का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

Repair of School Building

***1175 Shri Daryao Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether it is a fact that some rooms of Higher Secondary School, Jhajjar is in damaged condition ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid rooms are likely to be repaired ?

शिक्षा मन्त्री (श्री फूल चन्द मूलाना):

(क) जी हां, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय झज्जर के कुछ कमरे क्षतिग्रस्त हैं और उन की विशेष मुरम्मत की आवश्यकता है।

(ख) गत वर्ष 60,000/– रुपये की राशि स्वीकृतिकी गई थी। इस वर्ष 170,375/– रुपये की राशि विद्यालय भवन की मुरम्मत के लिये स्वीकृत की जा चुकी है। कार्य शीघ्र ही कर लिया जायेगा।

Construction of Roads

***1184. Shri Lehri Singh ;** Will the Minister for PWD (B & R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following roads :—

(i) From Kheri-Dabdalan to Mehra (Kurukshetra) ;

(ii) From Dholra to Jana hers (Kurukshetra) ;

(iii) From Seeli Khurd to Ghalaur (Yamunanagar) ;

(iv) From Thaska Khadar to Fatehgarh (Yamunanagar) ;

(v) From Ghalaur to Magra (Yamunanagar) ;

(vi) From Gundyana to Jhinwar Majri (Yamunanagar) ;

(vii) From Gundyani to Mustatabad Railway Station (Yamunanagar) ;

(viii) From Mehmadpur to Thambar ; and

(ix) From KabLlpur to Golni (Yamunanagar) ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid roads are likely

to be constructed ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री अमर सिंह):

(क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) उपरोक्त (क) के अनुसार प्रश्न ही नही उठता।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Embezzlement cases in Haryana State Cooperative Housing Federation

252 Shri Lehri Singh : Will the Minister for Cooperation be pleased to state—

(a) whether any cases of embezzlement in the Haryana State Cooperative Housing Federation have been detected during the period from 1984 to 1987 ; and

(b) if so, the total amount involved in each case together with the names of officers/officials, if any, held responsible therefor ?

सहकारिता मंत्री (श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया):

(क) वर्ष 1984 से 1987 के दौरान, हरियाणा राज्य सहकारी आवास प्रसंघ लि० में गबन का कोई मामला नही पकड़ा गया, लेकिन हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा की गई जांच के आधार पर हरियाणा राज्य सहकारी आवास प्रसंघ द्वारा वर्ष 1984 से वर्ष 1987 तक दिए गए मु० 162. 38 लाख के ऋणों का दुरुपयोग हुआ कहा जाता है।

(ख) चौकसी विभाग द्वारा पहले ही 8 चालान विभिन्न अदालतों में दायर किए जा चुके हैं व अन्य केसों में अभी भी जांच जारी है।

Works Manager in Transport Department

253 Shri Lehri Singh : Will the Minister of State for Transport be pleased to state—

(a) the number of Works Manager working in the

Transport Department at present ;

(b) the number of Works Manager out of those as referred to in part (a) above belonging to Scheduled Castes ; and

(c) whether there is any shortfall in the reserveration of Scheduled Castes in the aforesaid posts ; if so, the time by which it is likely to be wiped off ?

राज्य मंत्री (श्री बलबीर पाल शाह):

(क) 20, श्रीमान जी।

(ख) 2, श्रीमान जी।

(ग) नहीं, श्रीमान जी। कार्य प्रबन्धक के पद श्रेणी 11 के होने के नाते इन पर पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं है। फिर भी अनुसूचित जातियों के लिए सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण है। हरियाणा परिवहन विभाग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1992 के अनुसार कार्य प्रबंधक के 26 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते है और 75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

समस्त जिला फरीदाबाद में प्रदूषण सम्बन्धी

Mr. Speaker : Hon. Members, I have received a notice of Calling. Attention Motion No. 5, given notice of by Shri Karan Singh Dalal, M. L.A. regarding pollution being at the extreme in whole of the district Faridabad. I admit it. He may read his notice and concerned Minister may make a statement, thereafter.

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान अत्यन्त लोक महत्व विषय की ओर अर्किषत करना चाहता हूं कि सारे जिला फरीदाबाद में प्रदूषण जोरों पर फैला हुआ है और सारे इलाके में महामारी फैलने का डर है। औद्योगिक प्रदूषण न केवल हवा में ही गन्दगी फैला रहा है परन्तु नहर का पानी भी पूरी तरह से गन्दा हो रहा है

अतः मैं सरकार से निवेदन करता हू कि इस वर्तमान समस्या के बारे में इस महान सदन में अपना वक्तव्य दें।

वक्तव्य–

उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी

पर्यावरण, वन तथा वन्य–प्राणी संरक्षण मन्त्री (श्री रामपाल सिंह कंवर): फरीदाबाद हरियाणा का एक मुख्य औद्योगिक नगर है। राज्य में कुल 682–डी और मध्यम औद्यौगिक इकाईयों में से 188 इकाईयां फरीदाबाद जिला में लगी हुई है। इसके अतिरिक्त फरीदबाद में लगभग 16188 लघु स्तर की औद्योगिक इकाईयां भी हैं इनमें मे लगभग 95 प्रतिशत लघू इकाईयां प्रदूषण रहित किस्म की हैं मौर इनके लिए किसी प्रकार के प्रदूषण नियंत्रण संयत लगाने की आवश्यकता नहीं हैं। ये इकाईयां अधिकतर इंजीनयरिग श्रेणी की हैं जो कि गंभीर किस्म का प्रदूषण नही फैलाती।

उपरोक्त औद्योगिक इकाइयों में से 266 औद्योगिक इकाईयां ऐसी हैं जो जल को प्रदूषित करती हैं और इन्हें जल (नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974 के अंतर्गत प्रदूषण जल को शुद्ध करने की आवश्यकता है। 197 औद्योगिक इकाईयों ने पहले ही अपने जल शोधक संयंत्र लगाए हुए हैं और ये अपना स्त्राब हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित किए हुए मापदंडों के अनुसार साफ कर रही है। 16 औद्योगिक इकाईयों में जल शोधक संयंत्र लगाने का कार्य प्रगति पर है और 53 इकाईयों को 6 महीने के भीतर शोधक यंत्र लगाने के लिए नोटिस जारी किए हुए हैं जिनके नहीं लगाने पर उनके विरुद्ध जल प्रदूषण (नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

फरीदाबाद जिले में 366 इकाईयां वायु को प्रदूषित करने वाली श्रेणी में आती हैं। इनमे से 102 औद्योगिक इकाईयों ने पहले हैं। वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र लगाए हुए हैं तथा 86 इकाईयों में इन संयंत्रों के लगाने का कार्य प्रगति पर है। 178 औद्योगिक इकाईयों ने अभी तक वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र नहीं लगाए हैं, तथा बोर्ड ने इन इकाईयों को वायू प्रदूषण (नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 के अधीन ऐसे संयंत्र लगाने के लिए नोटिस जा री किए हुए हैं।

जहां तक फरीदाबाद में वायु प्रदूषण का सम्बन्ध है, वहां पर स्थित बड़ी–वड़ी प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाईयो में से एक है थर्मल पावर प्लांट हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सतर्क प्रयत्नों में से थर्मल प्लांट के अधिकारियों ने अपनी इकाईयों के 6 पाथों में से अब 5 पाथों में वायु प्रदूषण रोकथाम संयंत्र लगा दिए है तथा छठे पाथ में वायु प्रदूषण रोकथाम संयंत्र लगाने का कार्य प्रगति पर हैं।

जिला फरीदाबाद में से गुजरने बाली दो नहरो गुड़गांव नहर तथा आगरा नहर) का पानी फरीदाबाद जिने में लगो औद्योगिक इकाईयों के स्त्राव से प्रदूषित नही होता। संघ राज्य दिल्ली से बहने वाली प्रदूषित स्त्राव इन दो नहरों के पानी में प्रदूषण का मुख्य कारण है फरीदाबाद में से गुजरने वाली गुड़गांव नहर। वास्तव में आगरा नहर की ही डिस्ट्रीब्यूटरी है, जो कि बदरपुर थर्मल पावर प्लांट के डाउन स्ट्रीम हरियाणा के कुछ भागों में सिंचाई करती है। आगरा नहर के पानी का मुख्य स्त्रोत यमुना नदी है जिसका पानी देहली की 60,000 से भी अद्योगिक औद्योगिक इकाईयों के बिना साफ किए हुए औद्योगिक स्त्राव तथा संघ राज्य दिल्ली में स्थित 19 मुख्य नालों से बिना साफ किया हुआ व्यवसायिक स्त्राव के छोड़े जाने पर बहुत ही प्रदूषित हो जा

ता है.। आगरा नहर अपने बहाव के दौरान प्रदूषित जल को गुड़गांव फीडर नहर जो कि इसकी शाखा हैं, में डालने से पहले संघ राज्य दिल्ली के ओखला व्यवहारिक शोधक प्लांट और बदरपुर थर्मल प्लांट मे से काफी मात्रा में दूषित जल ग्रहण करती है। इस प्रकार फरीदाबाद–दिल्ली बार्डर के पास आगरा नहर से शुरु में ही गुड़गांव नहर में छोड़ा गया पानी अत्यंत ही प्रदूषित होता है जिस का बी ०ओ०डी ० निर्धारित मापदंडों से अधिक है और इसका कारण ओखला व्यवसायिक यंत्र बदरपुर पावर प्लांट की स्वाद से तथा दिल्ली में 19 नालों से बिना साफ किए हुए मलमूत्र निकास से एवं 60,000 से भी अधिक देहली की औद्योगिक ईकाईयों के व्यवसायिक स्त्राव से प्रदूषित होता युग न कि फरीदाबाद जिले मे लगी हुई औद्योगिक ईकाईयों से।

इस बोर्ड द्वारा नहर के शुरु से लेकर सोहना तक गुड़गांव नहर के पानी की गुणवत्ता को 6 निर्धारित स्थानों पर मापा जा रहा है। बोर्ड पहले से ही इस मामले को देहली प्रशासन के अधिकारियों के ध्यान ला चुका है कि वह अपना मल निकास तथा औद्योगिक इकाईयों का गन्दा पानी यमुना नदी में डालने से पहले साफ करें ताकि गुड़गांव नहर का पानी प्रदुषित रहित गुणवत्ता का हो, इसके इलावा फरीदाबाद जिले में स्थित ओद्यौगिक ईकाईयों द्वारा फैलाए जाने वाले प्रदूषण को कम करने में बोर्ड लगातार अपनी पूर्ण कोशिश कर रहा है।

स्वास्थ्य विभाग ने भी कहा है कि प्रदुषण के कारण फरीदाबाद में कोई महामारी फैलने का अन्देशा नही है।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने वड़ी सफाई से हमारी इस समस्या के बारे में सदन के सामने अपने विचार रखें। ये स्वयं मानते है कि. फरीदाबाद देश का दसवा इंडस्ट्रियल टाउन पै। अध्यक्ष

महोदय, फरीदाबाद में कभी आपको जाने का जरूर मौका मिला होगा जब आप दिल्ली से जाने हुए फरीदाबाद में दाखिल होते है तो वहां इतना जबरदस्त धुआ होता है कि आखों में पानी आने लगता है। इसके अलावा जितने भी वहां उद्योग है, वे बहुत प्रदूषण फैलाते है। मन्त्री जी ने केवल थर्मल प्लाट के बारे में कहा दिया कि इन्होंने वहाँ पर यन्त्र लगा दिया है। यह बात इनकी दुरुस्त है कि थर्मल से जो प्रदूषण होता था वह रुकेगा और उसमें कमी भी आई है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड की ये बात कर रहे हैं वह बोर्ड ईकाइयों का प्रदूषण रोकने की बजाए उनसे चन्दा और पैसा इकट्ठा करने की बात करता है। जिस किसे। इकाई के बारे में हम ग्रीवैंसिज कमेटी में या और माध्यम से वात उठाते हैं कि यह प्रदूषण फैलाती है तो समझो उन लोगों की लाटरी लग जाती है ये उनके पास जाएंगे और पैसे ले लेगें। ये प्रदूषण को रोकने की कोई बात नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्दी जी से जानना चाहूंगा कि फरीदाबाद जिले में आपने पिछले दो साल में कितने उद्योगपतियों के खिलाफ मुकद्दमे दर्ज करवाए हैं और कितने उद्योगपतियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की है। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, पलवल में जी०टी ० रोड पर आलापुर में एवा कारखाना लगा हुआ है, उस कारखाने से बहुत ज्यादा बदबू आने के कारण आस पास के 4–5 गावों के लोग वहुत परेशान हैं। वहां पर मच्छर बहुत ज्यादा पैदा होते हैं। इसके अलावा बल्लभगढ़ में एक लायर वायर फैक्टरी है। उस फैक्टरी के बारे में वहां के जो दूसरे एम० एल० एज है, उनको पता है कि उस फैक्टरी से बहुत ज्यादा मावा में काला धूआ निकलता है। वह इतना ज्यादा होता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। इसके अलावा हथीन में एक शराब की फैक्टरी है, उससे भी बहुत ज्यादा बदबू आती है।

श्री अध्यक्षः दलाल साहब आप सवाल पूछे।

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर साहब, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। माननीय मन्त्री जी मेरे सवालों को नोट करते जाए और उनका ये जबाब दे दें। अध्यक्ष महोदय, हथीन में जो शराब की फैक्टरी है

श्री अध्यक्षः इस बात का इस प्रस्ताव से कोई ताल्लुक नहीं है, आप पोलयशन के बारे में बात करें।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, जो हथीन में शराब बनाने का कारखाना है उसमें बहुत ज्यादा बदबू आती है और उसके आस पास के 15– 20 गांवों के लोग परेशान हैं क्या सरकार उस बदबू का कोई न कोई प्रबन्ध करने के बारे में कार्यवाही करेगी? इसके अलावा, पलवल में जो शूगर मिल लगा हुआ है, उससे बहुत ज्यादा प्रदूषण निकलता है। उस शूगर मिल में बहुत ज्यादा मुनाफा भी है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से और खास करके मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या उस शूगर मिल की कमाई से ही उसके प्रदूषण को रोकने के लिए कोई संयंत्र लगाने की व्यवस्था करेंगे और नसके आस पड़ौस के जो गांब है, क्या उनमें कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने का कोई प्रबंन्ध करेंगे?

श्री राम पाल सिंह कंवरः स्पीकर साहब, वैसे तो आपने यह फैसला किया हुआ है कि एक कालिंग अटैंशन मोशन के जवाब पर दो ही सवाल पूछे जा सकते हुँ। लेकिन दलाल साहब ने एक ही सांस मे बल्लबगढ़ की मारी फैक्टरीज गिनवा दी हे।

इन्होंने वहां की कोई फैक्टरी नही छोड़ी। जैसे इन्होंने कहा कि वहां पर बहुत ज्यादा प्रदूषण है, देने उस प्रदूषण के बारे में अपने मैडीकल औफिसर से रिपोर्ट ली है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि वहां पर

जो प्रदूषण है, उससे न कोई एपिडौमिक बीमारी फैली है और न ही आगे फैलने का कोई अंदेशा है। जिन कारखानों के मालिकों ने प्रदूषण को रोकने के लिए संयंत्र नहीं लगाए, उनको हमने नोटिस दिए हैं और नोटिस के जवाब न आने पर हमने हरियाणा प्रदेश के लगभग 406 कारखानों के मालिकों के खिलाफ कार्यवाही की हैं। हमने 181 कारखानों के मालिकों के खिलाफ वाटर एक्ट के तहत और 225 के खिलाफ एयर एक्ट के तहत भिन्न भिन्न कोर्टस में केस दायर किए हुए हैं और वे केस कोर्टस में लम्बित पड़े हैं। हुसके अलावा, माननीय सदस्य ने स्टायर वायर फैक्टरी के बारे में कहा है। उसके वारे में मैं उनको बता देना चाहता हूं और माननीय सदस्य ने यह माना भी है कि वहां पर थर्मल प्लांट में प्रदूषण रोकने के लिए संयंत्र लगाने के पश्चात उस का प्रदूषण कम दो गया है और वहां पर एक संयंत्र और लगाने जा रहे हैं। इसी तरह से इन्होंने शूगर मिल पलवल का जिक्र. किया। पलवल में संयत्र लगाया हुआ है। जिसके अन्दर एयर पोल्यूशन की पी० ओ० डी ० मात्रा 1000 मिलीग्राम की है, जिसमें थोड़ा मार्जनल 120 पी ० ओ० डी० है जबकि 100 मिलीग्राम होनी चाहिए। इस तरह से वहां एयर पोल्यूशन 598.8 मिलीग्राम है जबकि लिमिट 500 ग्राम की है। यह कुछ ज्यादा है, इनको कहा गया है कि इसको मोडीफाई कीजिए और ट्रीटमैंट प्लांट में भी मोडीफाई कीजिड। इन्होंने कहा है कि वे जल्दी ही इसका प्रबंध कर रहे हैं। इसी प्रकार से यहां पर हथीन डस्टीलिरी का जिक्र आया। कहा गया कि वहां पर लगुनिंग सिस्टम था जो बाद में हटाया गय। वे बताना चाहूंगा कि जो लगुनिग सिस्टम लगाया हुआ था, वह अब भी लगा हुआ है। अब सैन्ट्रल पोल्यूशन बोर्ड ने फैसला किया है कि यह सिस्टम जो बायो मैथानीज का है उसकी पूरी रिकवरी न हीं होती है, इस लिए इसकी बजाये उनसे कहा है कि

बायोमैथानीज सिस्टम अडौप्ट कीजिए और इस सिस्टम पर 90 लाख रुपये खर्च भी कर दिये गये हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जो पहना सिस्टम है उसका खर्चा भी नकारा नही जायेगा। अब प्राईमरी ट्रीटमैंट भी लेटैस्ट मैथड से होगा और जो पहला सिस्टम लगुनिंग का है, वह भी चलता रहेगा। इस तरह पूरा सिस्टम लागू करने से पर्यावरण में जो थोड़ा बहुत गंद जाता था, वह भी खत्म हो जाएगा। इसी तरह से यह जो इन्होंने अशोका डिस्टिलरी के बारे में पूछा था इसका यही जवाब है। एक सवाल इन्होने यह पूछा है कि बुकरम की जो एक फैक्टरी है, उसका ए० पी० सी० एम० अभी तक भी नहीं लगाया है लेकिन फिर भी हमने इसको चौक किया और जो देखा है, उससे यही पता चलता है कि उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन नहीं है लेकिन फिर भी हमने फैक्टरी के मालिक को कहा है कि आप ए० पी० सी ० एम ० पोल्यूशन सिस्टम लगाएं ताकि जो थोड़ी बहुत शिकायत है ऐयर में, वह भी खत्म की जा सके। एफुयूलेंट जो है, उसके लिए इन्होंने पहले ही एक ट्रीटमैंट प्लांट लगाया हुआ है। इसके रिजल्ट जो टेंस्ट के बाद सामने आए हैं, वे विद इन लिमिटस हैं। तो मैं समझता हूं कि दलाल साहब ने जिन फैक्टरियो के बारे में पूछा है, उन सब सवालों की संतुष्टि इनकी मेरे इन उत्तरो से हो गई होगी। वैसे भी हमारी सरकार अपनी तरफ से भरसक कोशिश कर रही है नि कैसे प्रदूषण को रोका जा सके।

श्री अजमत खां: अध्यक्ष महोदय, अब जिन प्वायंटों का जिक्र आया, वे मेरे हल्के से संबंधित हैं। मैं आपके माध्यम से मती जी से एक अर्ज करना चाहता हूं कि ये खुद और अपने अधिकारियों के साथ वहां पर 24 घंटे बिता आएं, या 12 घन्टे बिता आएं फिर बता दें कि वहां का वातावरण कैसे है। वहां पर उस अशोका डिस्टीलिरी की वजह से हालत बहुत खराब है। जी

० टी ० रोड पर बहुत बदबू है। इस फैक्टरी ने 15– 20 गांवों का जीवन नरक बना रखा है। मवेशियों में बीमा रिया फैलती हैं। गुड़गांव कैनाल का जो पानी मछली फार्म के लिए जाता है, उसमें मछलियों का जि तना भी बीज होता है, वह सारा का सारा खत्म हो जाता है। लोग दूसरे पानी में बीज तैयार करके लाते हैं, तब जाकर वह बीज बचता है। ये एक रात बिता आयें, फिर रिपोर्ट करें, हमारी तो अब आदत सी पड़ गई है क्योंकि हमें तो वहीं रहना होता है।

श्री रामपाल सिंह कंवरः अध्यक्ष महोदय, सैन्ट्रल पोल्यूशन बोर्ड की तरफ से जो नई इन्स्ट्रक्शन्ज आई हैं, उनके मुताबिक ट्रीटमैंट प्लांट लगेगा। इसके मुताबिक बोर्ड की तरफ से उनको इन्स्ट्रक्शन्ज दी जा चुकी है कि न्यू सिस्टम आफ पोल्यूशन कण्ड्रोल बोर्ड के मुताबिक ट्रीटमैंट प्लांट लगाए। यह आदेश दे दिया गया है और वह प्लांट अण्डर प्रोसैस है जिस पर वे आलरेडी 90 लाख रुपये खर्च कर चुके हैं। व ह्व प्लांट कम्पलीट हो जाने के बाद कोई कमी नही रहेगी और पोल्यूशन की समस्या खत्म हो जाएगी। जहां पुराना ट्रीटमैंट प्ल औट नहीं लगा हुआ है, वहां प्लांट लगाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो सैकण्ड ट्रीटमैंट करेंगे ताकि पोल्यूशन को रोका जा सके। अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी ने कहा है कि एक रात वहां पर रह कर देखें। मैं जाकर उनके पास ठहरूंगा अगर वे मुझे इन्वाईट करें तो मैं रात भी उनके पास ठहरूंगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः कर्ण सिह जी, आ पका सवाल ही गया है, अब आप बैठे। Hon. Members, now the general Discussion on the Budget for the year 1995-96 will be resumed.

वाक आउट

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आप मरी बात सुनें, पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अभी मुझे एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछना है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः कर्ण सिंह जी, आप अपनी सीट पर बैठे। (विघ्न) राम बिलास जी, आप शूरू कीजिए।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्षः आपने सवाल पूछ लिया है इसलिए अब आप बैठें। मेरी इजाजत के बिना अगर आप बोलेगे तो रिकार्ड नहीं होगा, इसलिए भाप बैठिए।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, आप कम से कम मेरी बात सुन लें। .....

श्री अध्यक्षः जो यें बोल रहे हैं उसको रिकार्ड न किया जाए। (विध्न)

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, अगर मुझे अपनी बात कहने की इजाजत ही नहीं है तो मैं इसके विरोध में सदन से वाक आउट करता हूं।

(इस समय विरोधी पक्ष के सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल हाउस से वाक आउट कर गए)

वर्ष 1995– 96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

प्रो० राम बिलास शर्मा (महेन्द्रगढ़): अध्यक्ष महोदय, श्री मांगे राम गुप्ता जी ने 13 मार्च को इस महान सदन में हरियाणा सरकार का जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उस पर अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। स्पीकर सर, इनकी पूरी स्पीच सुनने के बाद और पूरे बजट को

बार–बार पढ्ने के बाद ऐसा लगता है कि यह बजट नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस महान सदन में जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह सारहीन बजट है। (इस समय सभापतियों को सूचि में से एक सदस्या श्रीमती चन्द्रावती पदासीन हुई) आदरणीय चेयरमैन साहिबा, आप जैसी वरिष्ठ सदस्या को आज हाउस की कार्यवाही को प्रिजाईड ओवर करने का जो अवसर मिला है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हू। (विध्न) चेयरमैन साहिबा, मैं यह कह रहा था कि जो बजट होता है, वह सरकार का संकल्प होता है, सरकार की प्राथमिकताओं का कार्यक्षेत्र होता है, लेकिन यह जो बजट ई यह बजट नहीं है, इसमें कोई दिशा नहीं है, इसमें कोई सकल्प नहीं है, इसमें कोई प्राथमिकता नहीं है, इस में किसी को राहत नहीं दी गई। ऐसा लगता है कि सरकार किसी को राहत देना ही नहीं चाहती। चेयरमैन साहिबा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक के समुद्र से जो लहर उठी उसके भय से डर कर हमारे साथी ने घबराकर अपना घाट छोड़ दिया है और कर–मुक्त बजट यहां प्रस्तुत कर दिया।

इन्होंने, सिन्दूर, चूड़ियां और मंगलसूत्र पर टैक्स माफ कर दिया। चेयरमैन महोदय, इन्होंने अपने चार साल के राज में पुरुषों के लिए जो कुछ भी किया उससे इनको विश्वास हो गया है कि पुरुषों से इनका कुछ नही बनेगा, पुरुषों के ऊपर इनका विश्वास ही नहीं रहा हैं इसलिए ये अब महिलाओं को खुश करने की बात कर रहे हें (विघ्न) बहनों का जितना आदर हम करते हैं उतना कोई नहीं करता होगा। ''यत्र नरीय पूजयन्ते, तव रसयते देवता'' हम इसी संस्कृति के उपासक हैं और हमें इस बात की खुशी हैं। चेयरमैन महोदया, आज ये भोली भाली महिलाओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इनको चार साल बाद बहनों की याद आई है।

चेयरमैन महोदया, अटेली में एक बार चुनाव हुआ था। उन दिनों वहां पर बाबा खेतानाथ जी नाम के एक संत हुआ करते थे कांग्रेस के लोगों ने उनको जबरदस्ती टिकट दे दी जबकि वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। यहां पर राव बसा सिंह जी बैठे हैं, ग्रे भी उन लोगों में शामिल थे। वे बाबा जहां–जहां पर भी जाते थे तो बहनें उनके पैर पड़ती थी, टीका लगाती थी और श्रद्धा में एक–दो रुपए भी देती थी और बदले में बाबा उन्हें प्रसाद भी दिया करते और कहते थे कि जीजी/ बाई मैं चुनाव में खड़ा हुआ हूं। बहनों ने कहा कि बाबा जी, हम तो आपकी ही पूजा करते हैं, पर जीजी क्या करें यह जीजा ही नही मानते है। तो हमारी बहनें भाईयों के पीछे हे। चेयरमैन महोदया, बहनें तभी मांग में सिन्दूर लगाती है जव खेतों में फसल खड़ी हो, जब उसके पति की जेब में पैसा हो और जब उसके बेटे को रोजगार मिला हो। जब घर में अनबन हो, असुविधा हो और दुख हो तो बहनों के लिए सन्दूर के कोई मायने नहों होते हैं। इस सरकार ने बहनों को धोखे में रखने और आसू पोंछने वाली बात की है।

सभापति महोदया, चौधरी भजन लाल जी का सबसे बड़ा संकल्प तो एस० वाई०एल० का था। चार साल से तो हम पूछ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जो कह देगें कि यह बात गवर्नर एड्रैस मे भी आ गई है। चेयरमैन महोदया, इनके राज में लोग बात नहीं कह सकते हैं। हर आदमी इनके उस भाषण को याद करता है जिसमें इन्होंने कहा है कि हम इसको 90 दिन में पूरा कर देगें। उस वायदे का क्या हुआ? एस०वाई०एल० जो हरियाणा के लिए जीवन–मरण है उस बारे में इस वजट मे कुछ भी नही है। चेयरमैन महोदया, 1 नवम्बर 1966 से हरियाणा बना है, तब से लेकर जितनी भी सरकारें चाहे चौधरी देवी लाल की, चौधरी बंसी लाल की और मुख्यमंत्री चौधरी भजन

लाल की थी, इस पर कुछ काम नहीं हुआ है। तब से लेकर आज तक इस मुद्दे पर आन्दोलन हौ चूके हैं और हर सरकार ने अपने गवर्नर एड्रैस में बजट अभिभाषण में और चुनाव के मैनीस्फैटो में एस० बाई० एल० के बारे में वायदे ही किए हैं और इस सरकार ने भी एक नया पैसा इस. बजट में नही रखा है। इसको कितने हल्के शब्दों में टाल दिया है, वह इस बजट के पेज नंबर 8 पर है किः–

हम केन्द्रीय सरकार और पंजाब सरकार से सतलुज–यमुना लिंक नहर के पंजाब क्षेत्र में आने वाले भान को शीघ्र पूरा करने के लिए लगातार अनुरोध कर रहे है। ''

हम चार साल से इनसे पूछ रहे हैं और दो बार तो हम सबने सदन के नेता से प्रार्थना कर ली कि एक ऐसा प्रस्ताव पास क्रो लेकिन यह कहने लगे कि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि बेअन्त सिंह और प्राईम मिनिस्टर जी के बीच में चल रही है। हमने इनकी बात पर विश्वास किया। आज लगातार चार साल हो गए हैं, न तो ये प्रस्ताव पास करने के लिए तैयार हैं और न ही प्राईम मिनिस्टर के पास जाने के लिए तैयार हैं। They are conceiving time and again but they are delivering nothing for the last 4 years. चार साल में एस ० वाई० एल० के ऊपर कोई बताने लायक बात नहीं है कि यह 2–4 कदम आगे बढ़े हों या पीछे हटे हों। इस मामले में हरियाणा की जनता के साथ बड़ा भारी विश्वासघात हुआ है।

11.00 बजे

कांग्रेस ने अपने मैनीफैस्टो में जो बहुत बड़ा वायदा किया था, आज उसको इन्होने डाईलूट कर दिया।

इसके अलावा, इन्होंने बजट में कृषि के बारे में भी बताया। चेयरमैन साहिबा, हरियाणा की जनता पर राम मेहरबान हो जाता है इसलिए बारिश हो जाती है और फसलें हो जाती हैं। लेकिन हरियाणा का जो इकोनोमिक सर्वे है जिसको इन्होंने माना है कि जो फसले हैं वह रिकार्ड तोड़ हुई हें। केन्द्रीय पूल में इन्हौने मैक्सिमम 22 लाख टन चावल दिया है। चेयरमैन साहिबा, चावल की पैदावार किसान ने की है, गेहूं का उत्पादन किसान ने बढ़ाया है लेकिन उस किसान को प्रोत्साहन क्या मिला, तोहफा क्या मिला, इन्होंने किसान को तोहफा यह दिया कि जो करनाल मे एक बीज की बहुत बड़ी कम्पनी हे, जो जूते भी बनाती है और नकली बीज भी किसानों को देती है, जिसके बारे में इस सदन में 9 महीने से बार–बार मुद्क उठ रहा है और सरकार ने उसकी इंक्वायरी भी करायी है। हजारों किसानों का नुकसान सरकार ने माना है परन्तु फिर भी सरकार के कुछ लोग, जब कभी कोई सरकारी काश होता है तो उसी बीज–कम्पनी के यहां होता है और वे यहीं पर चाय पीने के लिए जाते हैं। चेयरमैन साहिबा, किसान जब देखता हे कि जिस आदमी ने उसको पीड़ा पहुंचाई है, नकली बीज दिया है, उसी कें यहां इस सरकार के लोग आते है और चाय पीते हैं तो यह गलत मैसेज कनवे करते हैं। सर, किसान वड़े लोगों से नहीं लड सकता परन्तु इस तरह से किसान को पीड़ा जरुर पहुंचती है, पीड़ा इकठ्ठी होती रहती है। सर, जिस किसान ने हरियाणा में इतना अनाज पैदा करके केन्द्रीय भडांर में दिया हो तो उस किसान को खाद का क्या भाव मिलता है? इस सदन में इस बारे में कई बार चर्चा चली परन्तु नेहरा साहब कोई जवाव ही नही दे पा रहे हैं। जब किसान को महंगाई खाद मिलेगी, बीज नकली मिलेगा वो कर कैसे इतना अनाज पैदा कर पाएगा। इन्होंने, जो चाद पर सबीसडी मिलती थी

उग्रको भी खत्म कर दिया। पंजाब की सरकार ने किसानों को प्रोत्साहन फै स्प में बोनस दिया है। पंजाब और हरियाणा के किसानों की हालत में कोई अन्तर नहीं है इसलिए हमारी सरकार को भी किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य देना चाहिए। दोनों स्टेट के किसानों की मेहनत में कोई अन्तर नहीं है, पसीने में अंतर नहीं है लेकिन सरकार ने किसानों को क्या दिया। सरकार ने सन–फलावर के बारे में बात की है। ये जितनी भी बातें लेकर हरियाणा में आते हैं, किसान उसी बात फो लेकर अपनी मेहनत से उस कार्य में जुट जाता है। सूरजमुखी के लिए भी किसान ने मेहनत करके इसका उत्पादन हरियाणा में बढाया। उसने इसका बीज नहरों के साथ–साथ तथा अन्य जगहों पर भी दिया लेकिन उसके साथ क्या ज्यादती हुई, इसके बारे में मैं आपको 17 सितम्बर, 1994 का ट्रिब्यून अखबार पढकर सुना देता हूं जिसका हैडिग है

"Bungling Hits Sunflower Output."

सर, यह सारी न्यूज आईटम तो बहुत लम्बी है इसलिए मैं इनका रैलबेन्ट पोरशन ही पढ़ देता हूं। यह जो खाद पैदा करने वाली कम्पनी है, ऐसा लगता है कि इसको सरकार नहीं चला रही है वल्कि इसका प्राइवेटाईजेशन इन्होने कर दिया है। इस अखबार में एच० एस० आई० डी० सी ० के बारे में लिखा है–

"It has been found that the seed was of low quality. It is believed that over 800 quntals of this seed is still lying with the HSIDC. The agency is trying to self it to the farmers in the coming rabi crop."

इसमें एक हजार क्विंटल बीज बेकार पाया गया, सब–स्टैण्डर्ड पाया गया। सर, यह 1994 की बात है, परन्तु इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई है। किसानो ने अपनी मेहनत करके, अपने पसीने से फसलें पैदा

करके केन्द्रीय भंडार को भर दिया लेकिन सरकार ने उसको अपनी करामात मान लिया जोकि ठीक बात नहीं है। इसी तरह से आ एरण्ड आर्डर की बात है कुछ बातें बहुत पुरानी हैं, उनको दोहराने से कोई फायदा नहीं है। आज भी मुख्यमंत्री जी ने सदन में बताया है कि हत्या के 84 मामले ऐसे हैं जिनके ऊपर गिरफ्तारी नही की जा सकी है। चेयरमैन साहिबा, लोग इससे सन्तुष्ट नहीं हैं कि गवाह नहीं मिला या क्या नहों हुआ। लोग अपने आसपास जब लोगों का अपहरण होते हुए देखते हैं, हत्या होते देखते हैं तो परेशान होते हैं। कुछ बातें ऐंसी हैं जो इस सरकार के साथ जुड़ी हुई है जींद जिले में सफीदों में बिटटु मन आफ श्री पाले राम बू डा खेड़ा गाव से, साढे चार साल का एक बच्चा 27— 4—94 से लापता है उसका कोई अता—पता नही है। जींद से मेरा नाम राशि राम बिलास, सुपुत्र श्री बाल कृष्ण निवासी नगरपालिका अदि, 7 दिसम्बर 1993 से लापता है। कितनी बार लोग मुख्यमन्त्री जी से मिल लिए और मुख्यमन्त्री जी को लिखकर दिया। मुख्यमन्त्री जी का अपनी आदेश है, कितना स्पष्ट है। 1 4— 1 1— 94 को जींद में लोगों ने रनसे भेट की। इसके ऊपर इनके सीनियर सैक्रेटरी के आर्डर हैं——

"Presented to C.M. He has desired that S. P. Jind may look into this matter personally and every possible steps be taken for tracing the soy. And also stern action be taken against the culprits."

अपहरण, हत्या और छोटा सा हरियाणा व इतना बड़ा पुलिस कप बन्दोबस्त है। अब मैं अगर भूत माजरा की बात करूंगा तो कहेगे कि इनको भूतमाजरा का भूत सवार हो गया है। हरिजन बाला संतोष की बात करूंगा तो ये कहेंगे। चेयरमैंन साहिबा, कोई जिला ऐसा नहीं है जिसमे इस

तरह की बात नहीं हुई। 24 फरवरी के दैनिक ट्रिब्यून में ऐडीटोरियल छपा था। उसमें सुप्रीमकोर्टस ने हरियाणा के हिसार जिले की पुलिस के बारे में कहा थो कि वहां की पुलिस दो आदमियों को गिरफ्तार करके अदालत में जाने से तो रोक सकती है लेकिन कलप्रिट को नहीं पकड़ सकती (विघ्न) एक दुदवा गांव है। चेयरमैन साहिबा आप लोहारू से हैं आप एक–एक गाँव से वाकिफ हैं दुदवा से ढाई साल से एक लड़का अशोक उसकी जीप का कंडक्टर लापता है। क्राइम ब्रांच और पुलिस के अफसरों से मिलने के लिए लड़ के के मां–बाप और पत्नी जाते हैं और रोते पीटते हें तो वे कह देते हें यह तो हमको मालूम है कि यह लड़का और जीप क्हां है लेकिन उस गिरोह के हाथ बहुत लम्बे हैं। हरियाणा पुलिस की अच्छी प्रतिष्ठा रही है लेकिन पुलिस वर्दी में खोये हुए बेटे के बाप को यह कह दे तो उस पर क्या बीतेगी? आखिर कितना समय लगता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाड़ खेत को खा रही है। इसके वारे में सरकार को चिंता करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट चिंता कर रहा है, अखबार के सम्पादक चिंता कर रहे हैं यह राजनीतिक मामला नही है। सुशीला का मामला राजनीतिक नहीं सुशीला समाज की वे टी है। बेटी न चमार की हौती है, न ब्राहम्ण की होती है, न जाट की होती है, बेटी समाज की होती है। बेटियों पर जब अत्ताचार का सिलसिला शुरू होता है, द्रोपदी के साथ जब अत्याचार होता है तो महाभारत इस धरती पर हुआ करता है। सीता की तरफ रावण पाप की दुष्टि से दे खता है तो उसकी लंका जलकर राख हुआ करती है। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, इस बार तो विश्व महिला वर्ष भी मनाया गया। सरकार को इस बारे में चिता करनी चाहिए, कुछ करके दिखाना चाहिए। हरियाणा पुलिस के सारे मामले सी०बी० आई० को जा रहे हैं इसके माने क्या है? सी ०बी०आ ई ० में

हरियाणा के लोग नहीं हैं। हरियाणा पुलिस से हरियाणा के लोगों का विश्वास उठता जा रहा है।

शिक्षा के बारे में इस बजट में कोई नए विद्यालय खोलने की बात नही है। सारी दुनिया के आकड़े थे। हिन्दुस्तान में, हरियाणा में 2.5 परसैट लड़के– लडकियां दसवी के बाद शिक्षा प्राप्त करते हैं। और जिन देशों के साथ हम मुकाबला करते हैं वहां पर 66 परसैन्ट अमेरिका और कैनेडा जैसे मुल्कों में मैट्रिक से ऊपर लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। जो विकासशील देश हमारी कैटेगरी में भाते हैं वहां 47 परसैन्ट लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। हमारे यहां पर केवल 55.9 परसैन्ट लिटेरसी खींच तान कर कागजों में पहुंचायी है और इस क्षेत्र में बहनों का अनुपात तो बहुत ही कम हैं। चेयरमैन साहिबा, शिक्षा के ऊपर कोई विशेष बजट का प्रोवीजन न करना, यह कोई अच्छी बात नहीं है। इंग्लैण्ड में सदन के अन्दर इसी शिक्षा के ऊपर बात आई कि नागरिकों का निर्माण विश्व– विद्यालय में होता है, नागरिकों का निर्माण स्कूल की चारदीवारी से होता है इसलिये जो कौम अपनी पीढ़ी को प्रशिक्षित नहीं करती, वह दो गुणा पाप कर रही है। चेयरमैन साहिबा, इन्होंने यहां पर क्या किया कि जो अनुदान प्राप्त कलियों के प्राध्यापक हैं, उनके वेतनमान तो सरकार ने बढ़ा दिये है लेकिन जो अनुदान प्राप्त प्राइवेट स्कूलज हैं, उनके मास्टर्ज व कर्मचारियों को उनके समान नहीं रखा गया है। अभी इन्होंने इक्मोमिक सर्वे की रिपोर्ट में बताया कि 70,863 आदमी इंजीनियर्ज, डाक्टर्ज, आई०टी०आईज० ट्रेन्ड, टैक्तोक्रेट्स इस समय बेरोजगार हैं और दूसरी और बी–एड, जे०बी०टी० किये हुए लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। एक तरफ चेयरमैन साहिबा, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में, 10– 10 सालों से लड़के लड़कियां इस तरह के केन्द्र चला रहे हैं, उनमें मैट्रिक से सब लोग ऊपर हैं

और इस तरह के कितने ही लोग कई बार जेलों में भी चले गये। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार यूं ही टी०वी० रेडियो पर एडवर्जिमैन्ट्स देती रहती है, जैसे हमने टी०वी में एक माता को बोलते हुए सुना है कि हम सब को एक साथ उठने का वक्त आ गया है, हम सब को एक साथ डुबने का वक्त आ गया है, इस तरह से सरकार इन फिजूल के नारों पर पैना व्यर्थ ही बरबाद कर रही है। इस की बजाये जो लडके लड़कियाँ ढाई–तीन सालों से प्रौढ़ शिक्षा से सम्बधित हैं, जिनको मेरे विचार से 10– 10 साल से कम का तजुर्बा नही है, सरकार को चाहिये कि इन सब को जे०बी०टी० ट्रेन्ड मान ले और उनको जे०बी०टी० का पे स्केल देकर के जहां–जहां इस तरह के स्थान खाली हों, वहां ऐसे बच्चों/बच्चियों को एडजस्ट कर दे, इससे सरकारी पैसे का सदुपयोग होगा। चेयरमैन साहिबा, इन लोगों को पढ़ाते हुए 10– 10, 15– 15 साल हो गये हैं, उम्र उनकी पूरी हो गई है और वे अब ओवरेज वाली कैटेगरी में आ गयें हैं। अतः सरकार इस ओर ध्यान दे।

इससे आगे मैं यह कहना चाहूंगा कि भाई अजमत खां जी जब बोल रहे थे तो कह रहे थे कि हमारे इलाके में उर्दू पढ़ाने वाले कोई नही हैं। मैं तो यह कहूंगा कि उर्दू तो बाद में आती है, पहले तो सृप्टि मैं संस्कृत ही आती थी। देववाणी आती थी। जो जन्म, कर्म है, वह सब कुछ आज संस्कृत में है। चेयरमैंन महोदया, वैसे तो संस्कृत पीठ हमारे कम है। सारे सस्कृत विद्यालय जितने हैं, महाविद्यालय जितने हैं, उन सब ने मिलकर एक सम्मेलन किया और उनकी यह मांग थी कि जो लोग आचार्य ट्रेनिंग लेकर आए है जो लोग शास्त्री पास हैं, जो लोग ओ०टी० ट्रेन्ड हैं, सब जगहों पर सरकार अनुदान देती है लेकिन इन संस्कृत पीठों को कहीं पर भी यह अनुदान

सरकार की ओर से नहीं दिया जाता। जो लोग प्राईवेट संस्थायें खोलकर बैठे है, उनको भी अनुदान दिया जाता है लेकिन जो लोग संस्कृत पढ़ा कर लोगों का उत्थान कर रहे हें, उनके लिये कुछ भी सहायता नहीं है। संस्कृत की शिक्षा–दीक्षा बहुत जरुरी है, इसलिये सरकार को इधर पूरा ध्यान देना चाहिये।

चेयरमैन महोदया, आप तो आर्य समाज विचारों की हैं, आपको याद होगा कि जब अग्रेजों ने यहां पर वेदों को जलवा दिया था, खत्म कर दिया था तो जर्मनी के जो मैक्समुलर थे, उन्होंने अपने जीवन का ग्रह लक्ष्य बनाया कि वेदों की मौलिक प्रति उपलब्ध करवाऊंगा। वेद की धरती हिन्दुस्तान से अगर वेदों को जलवाया गया था, या खत्म करवा दिया गया था तो उसी मैक्समुलर ने ओरिजनल प्रतियां देश में लाकर उपलब्ध करवाई। चेयरमैन साहिबा, सवाल यह है कि शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए न कि निरूत्साहित किया जाए। आज जो संस्कृत पक्ष रहे हैं, वे सारे भूत और भविष्य को जानते हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसलाः चेयरमैन साहिबा, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। मैं भाई राम बिलास शर्मा की विद्वता और योग्यता पर तो कोई प्रश्न नहीं कर सकता लेकिन मैं उनसे आग्रह करूंगा कि यह असत्य है कि मैक्समुलर ने जो हमारे ओरिजिनल वेद थे वे यहां ला कर दिए। यह बात असत्य हैं कृपया आप इसको अपने कथन में ठीक कर लें।

प्रो० राम बिलास शर्माः चेयरमैन साहिबा, यह डिबेट का विषय हो सकता हैं। मैंने तो शुरू में कहा कि वेद की धरती हिन्दुस्तान है। लेकिन एक जलजला इतिहास में एसा आया, एक दबाव ऐसा आया, एक खू खार किस्म की कौम ऐसी आई जिसने यहां की संस्कृति पर, सभ्यता पर, यल के रहन

सहन पर एक जब्रदस्त चौट की। वह कौम इतनी चालाक थी कि उसने सोचा कि हिन्दुस्तान का आदमी प्रेरणा कहां से लेता है। जब उस ने देखा कि यह अपने इतिहास से प्रेरणा लेता है, यह वेदों से प्रेरणा लेता है और यह अपनी संस्कृति से प्रेरणा लेता है तब उन्होंने इन सारी चीजों को यहां से गायब करने का अभियान छेड़ा। यह बहुत लम्बा विषय है।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसलाः चेयरमैन साहिबा, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे ऋषि मुनियों ने और विशेष कर देश के ब्राहमणों ने हमारे वेदों को सुरक्षित रखा है। क्योंकि वेद ब्राहमणों ने कंठस्थ किए हुए थे। मै चाहता हूं कि ये अपने आप को करैक्ट करें। वेद वहां नही गए और मैक्समुलर उनको यहां नहीं ले कर आया। वे यहीं रहे। हमारे देश के ऋृषि मुनियों ने और उच्च कोटि के विद्वानों ने सारे ज्ञान को यहीं सुरक्षित रखा है। आगे आने वाले समय में विदेशों में और दुनिया की सारी धरती पर आध्यात्मिकता की लहर भी यहीं से चलेगी इसलिए आप क्यों ऐसी बात कह रहे है।

प्रो० राम विलास शर्माः चेयरमैन साहिबा, मुझे अच्छा लग रहा है कि राजेन्द्र सिंह बिसला जी की रुचि भी वेदों में है। मैंने शुरू में कहा था अपनी इस बात को ये भी मान रहे हैं कि इन्होंने सुरक्षित रखा। चेयरमैन साहिबा, मुझे उर्दू से विरोध नहीं, उर्दू के अध्यापकों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए और उनको मेवात में लगाया जाना चाहिए। जो बच्चे हरियाणा में उर्दू पढना चाहते हैं, उनको पढ़ाया जाना चाहिए। जो पंजाबी पढना चाहते हैं, उनको पढ़ाया जाना चाहिए। हम किसी भाषा के विरोधी नहीं हैं। परन्तु यदि संस्कृत पढ़ने पढ़ाने वाले नहीं रहेंगे, यह देव वाणी नदी रहेगी और यह मानवीय संस्कृति यदि हिन्दुस्तान से खत्म हो गई तो उर्दू पढ्ने वालों की संख्या भी यहां कम हो जाएगी। चेयरमैन साहिबा, हिन्दुस्तान में यह मानवता

तब तक है जब तक वेदों के संस्कार हमारे ऊपर हैं। जो हिन्दुस्तान के टुकड़े हम से अलग हो गए, वेदों के संस्कार से अलग हो गए वहां मां–बेटी लड़ रही है, भाई बहन लड़ रहे हैं। मूर्तजा और बेनजीर लड़ रहे हैं और उसकी मां और बेटी लड़ रही हैं। तो यह संस्कारों का कमाल है इसलिए मेरा आग्रह है कि संस्कृत के संबंध में जो अनुदान दिया जाता है, वह सब को बराबर दे। अगर सस्कृत को प्राथमिकता नही देनी तो बराबर तो रखें, इसके साथ भेद भाव तो न करें। आज उर्दू के अध्यापको की जिस तरह से खोज हो रही है उसी तरह से संस्कृत के अध्यापकों की भी खोज होनी चाहिए। अब मैं सिंचाई के मामले में कहना चाहता हूं। चेयरमैन साहिबा, नहरो में गाद की बात तो इस बार जब सदन के बाद कोई विद्वान पत्रकार लिखेगा तब आएगी। जैसे मैन आफ दि मैच हुआ करता है, टौपिक आफ दि सैशन हुआ करता है। तो उसमें हरियाणा की नहरों की गाद, मंहगी खाद और चीनी का कड़वा स्वाद वह लिखेगा। यह तो उसके बाद की बात आएगी। चेयरमैन साहिबा, थेने शुरू में कहा था कि यह जो बजट है इसके लिए कुछ रस्मे हैं, कुछ पार्लियाक्टरी कन्वैन्शंज है। चेयरमैन साहिबा, बिजली के दाम तीन बार बढ़ा लिए और फिर कह दिया कि हम बिजली के लिए 476 करोड़ रुपए रेख रहे हैं। कम से कम जब बजट अधिवेशन बुलाया था तो हरियाणा के लोगों की तसल्ली हो जाती कि बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, बिजली को कितना पैसा मिलेगा, ये बिजली कैसे देंगे। लेकिन सदन में बिजली के बारे में चर्चा न हो। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी भले आदमी हैं और इनको उधर ले जाते ही बिजली में फंसा दिया। चेयरमैन साहिबा, यह बजट अधिवेशन है और सरकार कोई भाग नहीं रही। कोई दिक्कत नहीं है। आने जाने वाली और वह जहाज डूबने वाली बात तो साल–छः महींने बाद

आएगी। तो मुख्य मन्त्री जी से मैं आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि जो यह एस ०वाई०एल० का मामला है और चाहे वह यमुना जल समझौते का मामला है इसकी तरफ आपका ध्यान नहीं गया। नरसिम्हा राव जी को बचाते बचाते आपको चिन्ता केन्द्र की ज्यादा रही। अब कुछ दिन हरियाणा की भी चिन्ता करें। एस०वाई०एल० के मामले पर इनसे मैं फिर कहना चाहता हूं कि हरियाणा यदि बचेगा, हरियाणा का गरीब किसान जहां बचेगा, वहां राजनीति भी बचेगीह और पार्टियां भी बचेंगी। इस काम मे तो राजनीति से थोड़ा ऊपर उठकर इस पर एक बार फिर से चिन्ता काम विचार करें। इस पर आप हरियाणा प्रदेश के लोगों को कुछ करके दिखाएं। आपको राज करते हुए चार साल हो गए। चार साल का समय किसी सरकार को अपनी प्राथमिकताएं अभिव्यक्त करने के लिए और अपनी प्राथमिकताओं पर कार्यवाही करने के लिए कोई कम सक्ष्म नहीं होता। लोगों के सामने आपने जो वायदे किए थे क्य से क्य आप उन वायदों को तो पूरा करें। आज हरियाणा प्रदेश के किसान जगह–जगह आन्दोलित हैं। चेयरमैन साहिबा, बहू त से लोग आन्दोलनों में मरे है। अभी 10 अगस्त को नारनौल में दो नौजवान पुलिस की गोलियों से पानी मांगते–मांगते मरे। इसी तरह से नारनौद में बिजली मामते–मांगते एक शमशेर सिह नाम का नौजवान पुलिस की गोलियों से मरा। इसी तरह से निसिंग में बिजली और पानी मांगते मानते किसान मरे। चेयरमैन साहिबा, यह जो आन्दोलन उठते हैं उनके बारे में कह दिया जाता है कि फलां आदमी किसानों को भडका रहा हैं, लेकिन मैं इस सरकार को कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश का किसान आज बहुत ज्यादा समझदार है वह किसी के बहकाने से भड़कता नहीं है। कई बार लोग बिरादरी में फंस जाते पैं कि चौधरी भन न लाल जी उन को पसंद नही है। यह ऐसी बात नही हैं।

चेयरमैन साहिबा हरियाणा प्रदेश का किसान विचारों से जुड़ता है। हरियाणा का किसान सरकारों की परफौरमैंस देखता है। हरियाणा का आदमी सरकारों की कारगुजारी देखता है लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ नही हे। यह इस जिन्दा सरकार का बजट है। इनकी इच्छा शक्ति खत्म हो गई है। वित्त मंत्री श्री मांगे राम गुप्ता जी ने कलम ओर दवात पर टैक्स माफ कर दिया। सेठ तो सयाना है न इन्होंने सोचा कि कलम दवात तो फिर पकड्नी है। साल भर बाद कलम दवात कहां जाएगी इसलिए इन्होंने अपने उपयोग में आने वाली कलम और दवात पर टैक्स माफ कर दिया। लुगाई बेलन से न पीट दे इसलिए इन्होंने सिन्दूर और चूड़ियों पर टैक्स माफ कर दिया। मेरा कहना है कि जो जीजी हैं ये जीजो के गेल रहती हैं। बिजली के रेट बडा कर इस सरकार ने किसान को मार दिया। पीने का पानी मुफ्त देने की दास थी लेकिन इस सरकार ने स्थरों में पीने के पानी पर टैक्स बढा दिया। पहले 10 रुपये महीने के देते थे अब 10 रुपए की जगह 100 रुपया महीना देना पड़ेगा। चेयरमैन साहिबा, इस सरकार ने पानी नापने के नए मैयर्ज इजाद किए हैं। पहले पानी लीटर्ज में नापा जाता रहा है लेकिन इस सरकार ने स्माल ही कर दिया। अव यह सरकार पानी को गजो मैं नाप रही है। अगर 100 गज का प्लाट है तो उसका पानी का रैट 100 रुपया महीना होगा और अगर प्लाट 300 गज का है तो उसका पानी का रेट 300 रुपया महीना होगा। इस सरकार ने पानी को गजों में नाप कर कमाल ही कर दिया। चौधरी फूसा राम जी ऐसे विधायक हैं जिनको मैं यह कहता रहता हूं कि भाई आप पांच साल में कम से कम एक बार जरूर बोलो नहीं तो आपके कान गल जाएंगे।

सभापतिः शर्मा जी, आपको बोलते हुए आधा घंटा हो गया अब आप वाईंडअप करे।

प्रो० राम बिलास शर्माः चेयरमैंन साहिबा, मैं आपका पड़ौसी भी हूं और आपका छोटा भाई भी हूं इसलिए आप मुझे बोलने का टाईम थोड़ा ज्यादा दें। इस सरकार ने 59.71 करोड़ रुपए के घाटे का बजट पेश किया है। चेयरमैन साहिबा, क्योड़क गांव की एक घटना है। उस गांव के हरिजन गांव छोड़ कर कैथल चले गए और उनके बारे में मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि वे सब लोग वापिस अपने गांव में चले गए हैं। चेयरमैन साहिबा, मैं 19 तारीख को जींद हो कर आया हूं और वापिस आते समय मैं कैथल और क्योड़क होकर उनसे मिल कर आया हूं। अब भी उस गांव के 25 हरिजन परिवार कैथल की चार दिवारी के बाहर तम्बू लगाए बैठे हैं। चेयरमैन साहिबा, उनका कसूर केवल यह है कि उनमें से एक हरिजन लड़के ने वहां से जिला परिषद का चुनाव लड़ लिया और उस चुनाव में वहां का एक दिग्गज आदमी चुनाव हार गया। उस गांव के कुछ ठाडे लोगों ने कहा कि यह हरिजन कैसे चुनाव लड़ गया और इसके कारण हम चुनाव हार गए। क्य बिनाह पर उसको गांव से उजाड़ दिया। चेयरमैन साहबा, जब कोई आदमी गांव से उजड़ता है तो उसको बहुत पीड़ा होती है। यदि कोई पक्षी अपना घोंसला छोड़ता है तो उसको बहुत दर्द होता है। फिर यह सरकार हरिजनों के कल्याण की बात करती है। आज भी वह 25 हरिजन परिवार कैथल में तम्बू लगाए बैठे है। चेयरमैन साहिबा, उन हरिजनों के गले में जूतों की माला डाल कर एस०पी० ने कैथल शहर के बीचों बीच साथ साथ चल कर धुमाया और कहा कि तुम बोलो कि हम ढ्ड हैं और चुनाव लड़ने की हमने हिमाकत की है। चेयरमैन साहिबा, एस ० पी० उनके साथ इस तरह की कार्यवाही करे।

इसी तरह से कैथल मे एक एक्स एम०एल०ए० श्री चमन लाल सराफ को उल्टा लटका कर ..... दे दिया। मुख्य मंत्री जी ने यह ठीक किया कि उस बारे में इन्क्रवायरी करवाई लेकिन आज तक वह पुलिस का दरिन्दा औफिसर वैसे ही घूम रहा है उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई।

सभापति माननीय सदस्य ने जिन शब्दो का इस्तेमाल किया है उनको रिकार्ड न किया जाए।

प्रो० राम बिलास शर्मा: चेयरमैन साहिबा, मेवात में जिन लोगो ने जिन्दा गउएं जलाई थी, जिन्होने मंदिर तोड़े थे उनके खिलाफ यानि जिन 595 लोगों के खिलाफ मुकद्दमे दर्ज हुए थे, वापस ले लिए। इसी प्रकार से बौंद गांव में एक भवन में एक सरकारी संस्था चलती है। वहां पर 37 लोगों के खिलाफ जो झूठे मुकद्दमे दर्ज हुए थे, वे तो वापस लिए नही लेकिन उजीना गांव के किसन सिंह की और पस्ला गांव के कुन्दन लाल की हत्या करने वाले लोगों के खिलाफ जो मुकदमें दर्ज किए गए थे, वे वापस ले लिए गए। सरकार सारे गलत काम कर रही है। गुप्ता जी ने जो बजट पेश किया है, इससे आम आदमी में निराशा पैदा हु ई है और लोगों में खामोशी है। यह बजट विफलताओ से भरा हुआ है। गुप्ता जी ने दवात और कलम को तो टैक्स से छूट दे दी लेकिन आम आदमी को राहत नहीं दी। सरकार ने भाईयों पर मार करके बहनों को जो राहत देने की कोशिश की है, वह बजट को प्रस्तुत करने वालों को मजा चखाएगी। धन्यवाद।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह (उचानाकलां): हमारे वित्त मत्री ने इस सदन मै हरियाणा सरकार का लेखा–जोखा रखा है कि 1995– 96 में सरकार क्या करने जा रही है। इसके विषय में जो बजट रखा है, उस पर मैं बोलना चाहता हूं। यह शायद इनका पांचवां बजट है। मांगे राम जी एक वजट जो

पिछली सरकार को रखना चाहिए था, अपने कारनामों की वजह से नही रख सकी थी, इसलिए हो सकता है कि एक और बजट रखने की जरूरत पड़े और 5 साल की अवधि में 6 बजट प्रस्तुत करने का मौका इनको मिल सकता है। मैडम चेयरपर्सन, इसी तरह से डा० मनमोहन सिंह ने भी अपना पांचवां बजट लोक सभा में रखा है। मैडम, आज 4 साल में देश में एक नयी चीज, एक नई बात जिसको हम उदारीकरण या लिबरेलाईजेशन कहते हैं, इस देहा की अर्थ व्यवस्था में आई है। 4 साल का समय इस–लिबरेलाईजेशन को टैस्ट करने का कोई समय नहीं हैं कि इससे इस देश की जनता को कोई लाभ हुआ या इससे देश की जनता को कोई नुकसान हुआ। चेयरमैन साहिबा, मै एक बात अपनी ओर से कहना चाहता हूं। मेरी अपनी राय है कि उदारीकरण के संदर्भ में हरियाणा की सरकार को अपने बजट को नये नुक्तानिगाह से देखना चाहिए और नई दिशा इस बजट को देनी पड़ेगी। जो बजट इस साल आया है वह स्टीरियो टाईप्ड बजट है जैसा कि पहले आता रहा है। मेरा अपना यह विचार है, मेरा यह मानना है कि दिल्ली के नजदीक होने के कारण हरियाणा में अगले 10 साल में उद्योगों का विस्तार होगा। हरियाणा मे जितना उद्योगीकरण होगा उतना शायद देश के किसी अन्य प्रान्त में नहीं हो सकेगा। यह स्वाभाविक है क्योंकि राजधानी के साढ़े तीन तरफ हरियाणा लगता है और जहां पालम ऐयर पोर्ट जैसा हवाई अड्डा है वहां से दुनिया के हर कोने में हरियाणा के उद्योगों में बना हुआ माल पहुंच जाता है। चेयरमैन साहिबा, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि स्टेट में तेजी सै उद्योगों का विस्तार होगा यह एक समस्या ही जाएगी। लेकिन दूसरी जो एक बड़ी समस्या है उसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या है। आज प्रदेश के

नौजवानों में बेरोजगारी है, कितने लोग और नौजवान ऐसे हैं जिनके नाम नौकरियां पाने के लिए रोजगार कार्यालयों के रजिस्टरों में दर्ज हैं। लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी है कि जब किसी को 10वीं, बी ०ए० या एम०ए ० की सन्नद मिलती है तो वह चाहता है कि उसको नौकरी मिल जाए और वह सिर्फ सरकारी नौकरी चाहंता है। चेयरमैन साहिबा, सरकार कितने लोगों को सरकारी नौकरियां दे सकती है। सरकार के पास इतनी नौकरियां देने के लिए कहां हैं जो हर नौकरी नौजवान को दे समे। हर नौजवान को नौकरी देना सरकार के लिए सम्भव नहीं हो सकता है। हरिया णा में जिस कद्र उद्योगीकरण हुआ है मेरा अपना यह मानना है कि लगाने 10 साल में हरियाणा के 100 किलो मीटर तक के ऐरिया में कहीं भो चले जाईये वहां पर उद्योग ही उद्योग लगे हुए होंगे। चेयरमैन साहिबा, इसमें समस्या यह है कि जो भी उद्योग लगता है उसमें तकनीकी ज्ञान वाला आदमी वे लोग लगाते हैं। उनमें 90 परसैंट बाहर के आदमियों को नौकरियां दी जाती हैं। मुझे इस बारे में पता नहीं सरकार इसका पता लगाए कि वे कितने लोगों को बाहर से लाकर नौकरियां देते हैं। चाहे वे लोग बिहार से हैं या यू०पी० से हैं या महाराष्ट्र से या किसी और प्रदेश से हों, लेकिन हरियाणा के लोगों को नौकरियां नहीं देते है। यह स्थिति ठीक नहीं है। अगले 10 साल के अन्दर इतने उद्योग बढेगे जिससे कम से कम 10 लाख रोजगार के नये साधन पैदा होंगे लेकिन अगर बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के रहने वाले लोगों को यह रोजगार मिलता है तो फिर इन उद्योगों को हमारी धरती पर लगाने का क्या फायदा है। चेयरमैन साहिबा, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो लीडरशिप है चाहे वह मुख्य मन्त्री जी हैं, विपक्ष के नेता हैं उनको ब्योक्रेट्स पर नीति के मामले में डिपैंड रह कर नीति तय नहीं करनी चाहिए

यह नजरिया आपको बदलना पड़ेगा हरियाणा में जो बेरोजगारी की भयानक समस्या है यदि इस ओर ध्यान न दिया गया तो यह और भयानक हो सकती है जिससे कि हम जूझ रहे हैं और लड़ रहे हैं। चेयरमैन साहिबा, इस बारे में में फाईनैंस मिनिस्टर को भी कहना चाहूंगा कि वे इन बातों पर गौर करें ताकि हम बेरोजगारी की समस्या से लड़ सकें। चेयरमैन महोदया, मेरा इनको एक सुझाव है, अगर यह मनकर चलें कि कल को 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा तो कम्पनी वाले तो अपने यहां पर अच्छे टैक्नीकूल आदमी रखेंगे। इसलिए इस सरकार को सी० आई० आई० के थ्रू यह पता करना चाहिए कि उनको कितने आदमियों को आने वाले सालों में जरूरत है। मिसाल के तौर पर आप एस्कोर्ट कम्पनी को लें। फर्ज करो उस कम्पनी को 10 हजार आदमियों की जरूरत है। उन आदमियों के बारे में ये सी० आई ० आई० से लिस्ट ले लें कि उनको किस तरह के अदमियों की जरुरत है और उसी तरह की ट्रेरिंग आने यहां पर दी गार अरि लडको को ट्रेन्ड किया जाए। इस तरह उन ट्रेण्ड बच्चों को यह लगेगा कि कि अब उनको रोजगार मिल जाएगा। जब हमारे बच्चे स्प प्रकार का तकनीकी ज्ञान लेने कें लिए आगे आएंगे तभी हम बेरोजगारी से लड़ सकेगे। दूसरी समस्या यह है कि अगर हरियाणा में उद्योगों को विकसित करना है तो यह मानकर चलना पडेगा कि हमारे यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है और म् बिजली है। सब से पहले मैं यह बताना चाहता हु कि हिसार में मुख्यमन्त्री जी ने मान दिया था कि हरियाणा के अन्दर चार साल तक बिजली नहीं बनेगी।

बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): चेयरमैन साहिबा, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मेरे को पता नही इन्होंने कहां से यह ध्यान पढ़ा है और न ही मेरी नौलेज में है कि मुख्य मंत्री जो ने यह बात कही होगा। शायद थर्मल

बेस्ड प्लांट का कहा होगा। पानीपत में हमारे पास एक छठा यूनिट है, डीजल बेस्ड प्लांट के लिए हमने एडवरटाईज किया है और हमारे पास टैन्डर भी आ गए हैं। उससे एक–डेढ साल के अन्दर बिजली मिल सकती है।

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः चेयरमैन महोदया, थर्मन बेस्ड प्लांट 4–6 साल तक लग ही नहीं सकता है। सरकार ने तो इस नीयत से फैसला किया है कि आमदनी सरकार की हो। चाहे हिसार, जमुना नगर या फरीदाबाद में ये प्लांट लगे। बिजली कोई और बनाएगा और यह सरकार तौ यह देखेगी कि वे हमें कितने रेट पर बिजली देंगे। इतनी बड़ी इन्वैस्मैंट राज्य सरकार के बस की बात नहीं है। ये जो उदारीकरण की बात करले हैं तो ये हरियाणा को लगातार बिजली देने में सक्षम नही रहेंगे क्योंकि आबादी बढ़ जाएगी और साथ–साथ कंजम्पशन भी बढेगी। अगर बिजली नही मिलेगी तो उससे कन्जयूमर, दुकानदार और किसान ही मरते हैं। मेरा तो यह अनुरोध हैं कि अगर आप प्राईवेट सैक्टर को बिजली बनाने का काम दें तो बिजली की समस्या का समाधान हो सकता है। मैं आपको मिसाल के तौर पर नोएडा की बात बताता हूं जिसे ग्रेटर नोएडा भी क् हते हैं। वहां पर यू ० पी० वालों ने कलकता की एक प्राईवेट कम्पनी को बिजली बनाने का काम दिया है और उन्होने उनसे– कहा है कि खुद बिजली बेचो, खुद बिल। दो और खुद पैसा इक्ट्ठा करो। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जब तक आप हरियाणा के पांच बड़े शहरों यानी यमुनानगर– जगाधरी, फरीदाबाद, पानीपत, हिसार और गुड़गांव में बिजली देने के काम को प्राईवेट सैक्टर में नहीं देगे, तब तक बिजली की समस्या दूर नहीं होनी। इंडस्ट्रीज के अन्दर, डौमैस्टिड़ बिजली अरि कार्मिशयल बिजली देने का सारा काम अगर आप प्राईवेट सैक्टर मैं दे देंगे तो तीस परसैट, जो बिजली अब हमारे पत्न है, उसकी हम बचत कर

सकेंगे और वह तीस प्रतिशत बिजली हम' किसानों के ट्यूबबैल्ज के लिए, किसानों के घरों के लिए 24 घंटे दे सकेगे।

श्री वीरेन्द्र सिंहः चेयरमैन मैडम, इन्होने जो कहा है, इनकी यत्न आत भी हम सोच रहे है, यह अंडर कंसीड्रेशन है।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः लेकिन आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं। चेयरमैन सर नौएडा में क्या किया है? नौएडा में यह किया है कि उन्होंने बिजली के 75 मैगावाट के प्लांट लगाने का फैसला कर लिया और काम शुरू कर दिया है।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): हमने भी पहले यत्र काम प्राईवेट सैक्टर में देने के लिए ऐडवरटाईजमैन्ट कर रखी है।

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः लेकिन अभी तक तो आपने केवल इजरायल की फर्म से ऐग्रीमैन्ट किया है।

चौधरी भजन लालः हमने दूसरे भी टैंडर काल किए हैं। अब कोई आए और आकर वह 50, 75 या 100 मैगावाट के प्लांट लगा सकता है।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः अगर आपने ऐसा किया है तो आप इस बारे में फौरी तौर पर कार्यवाही करें। अगर आपने ऐसा किया तो किसानों को 6 महीनें के अंदर–अंदर ही राहत आप दे सकते हैं। आज हरियाणा के अंदर किसानों के जो ऐजीटेशन होते हैं, उसका सबसे बड़ा आधार बिजली की कमी है। मैं मुख्य मन्द्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आज किसान केवल दो ही बाते देखते हैं–एक तो बिजली की कमी और दूसरी बात है पानी की कमी। बिजली की कमी तो हम जरूर पूरी कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जिस सिम्टम की बात हेंने कही है, अगर उसी तरीके से हम करेंगे तो

बिजली की कमी पूरी कर सकते हैं। आज आप जो बिजली उद्योग–धंधों में देते है उस बिजली को दूसरे सैक्टर्ज में तबदील करके किसानों को वह बिजली 24 घंटे के लिए दे सकते हैं दुकानों के लिए और धरों के लिए भी हम विजली दे सकते हैं। चेयरमैन साहिबा, इसके अलावा, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता है कि जब बिजली की कमी पूरी होगी तो उससे हमारा खेती का उत्पादन भी बढ़ेगा क्योंकि फिर खेती में किसान को ज्यादा मेहनत से काम करना पड़ेगा। अगर हरियाणा में एग्रीकल्चर सैक्टर में ऐग्रीकल्चर की डाई– वर्सीफिकेशन नही होगी तो हम। रा किसान पिछड़ जाएगा। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि किसान जो चीजें पैदा करते है, उनको उनका पूरा मूल्य मिलना चाहिए। में यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हरी सब्जी खाड़ी के देशों में पहुंचाई जाए तो इससे किसानो को बहुत फायदा मिलेगा। आज किसान अपनी एक किलो मूली हरियाणा की मंडी में ढाई रुपये किलो बेचता है। अगर उसकी उसी मूली का हरियाणा से पालम हवाई अड्डे तक जाने का इंतजाम हो जाए और वहां से वहां वह खाड़ी के देशों में चली जाए तो वही मूली ढाई सौ रुपए किलो में बिकती है। आज मुख्य मन्त्री जी ने मन्त्रियों की तो बहुत लम्बी लाइन लगा रखी है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आप नया डिपार्टमैंट कार्मस का भी शूरू कीजिए। इससे जितने भी छोटे व्यापारी है या किसान है, उनको दूसरे देशो के साथ व्यापार करने का मौका मिलेगा। आज मुख्यमन्त्री के चोरी तरफ जो लोग हैं या जो व्यूरौक्रेटस हैं, उनको दूरदर्शिता से काम लेना चाहिए, तभी हम उनको क्रेडिट दे सकते हैं, लेकिन अगर वह इस बात का क्रेडिट लें कि किसी आफिसर की प्रमोशन है, गह फलां जाति का है इसलिए उसकी प्रमोशन नहीं होने देंगे' तो ऐसी बातों में कोई क्रेडिट देने की बात नही है। हरियाणा में

पहली बार ऐसा हुआ हे कि आइ० ए ० एस० कैडर को कम किया गया है क्योंकि जिन आठ आदमियों की प्रमोशन होनी थी, उन में से आठ जाट थे और एक हरिजन था। उन्होंने कहा इतने आदमियों की प्रमोशन नही होने देगे। लेकिन उनको ऐसी सोच को बदलना पड़ेगा, हमारे पोलिटिकल सिस्टम से अलग हटकर उन को ऐसी बातों को अपनी सोच से निकालना पड़ेगा।

चौधरी भजन लालः ओन ए प्वायंट ऑफ आर्डर चेयरमैन साहिबा, इस सरकार के दिमाग में कभी कोई जात–पात की बात नहीं –गई है। यह सोचने की बात भी नहीं है, जिनका हक है ननको मिलेगा। यह कहना कि जाट है इसलिए कॉल नहीं करने की बात है, यह बिल्कुल बेबुनियाद और गैर–जिम्मेदाराना बात है, इसको आप हाउस की कार्यवाही से निकलवाइए।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः चेयरमैन साहिबा, हाउस में अगर मैंने कोई अनपार्लियामैंट्री बात कही हो तो उसको हाउस की कार्यवाही से निकालो जा सकता है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कहीँ है। जहां तक जात–पात की बात है यह हमारे सिस्टम में इतनी बुरी तरह घुस गई है। हम पौलिटिकल लोग तो इन बातों को सोचते थे लेकिन ब्यूरोक्रेट सोचें, हमारी सरकार के अधिकारी सोचें, यह कोई न्यायोचित बात नहीं है। आदमी वोट लेने के लिए 100 भेष बदलता दै। जिन अधिकारियों का काम सरकार की नीतियों का पालन करना है वे अगर इस किस्म की ऐडवाइस सरकार को दें तो यह कोई न्यायोचित बात नहीं है। सोचने की और बातें बहुत है। आज पानी का मस ना है। चौधरी बंसी लाल जी ने कहा कि सरकार जांच करवाए कि चार नदियों पर जो बांध हैं यह नारनौल और महेन्द्रगढ़ व रिवाड़ी के इलाके में आते थे, यह बांध कोई आज तो नही बने यह 10– 12 साल से बने हैं। साहिबी नदी पर बांध बनने की बात हुई थी उसके बाद सभी मुख्यमंत्री बने

और तब किसी ने छगन नहीं दिया। आज बंसी लाल जी कह रहे हैं कि उनके निर्माण की जरूरत है। यमुना जल समझौते की बात उन्होंने कही। (विध्न) यमुना जल समझौते को कोई राजनीतिक रूप दें लेकिन एक बात से मैं सहमत हूं कि जिस दिन यमुना जल समझौते के अन्तर्गत किसाऊ डैम बनेगा उस दिन वैस्टर्न यमुना कैनाल का सिस्टम है जो आज 14 जिलों की धरनी प्यासी है उसको पानी तभी मिल सकता है जब किसाऊ डैम बनकर तैयार हो। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि चाहे हथनी कुंड बैराज हो, चाहे यमुना जल समझौते के तहत दूसरे कोई काम हों, आपकी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि आप सब कामों न ओं दूसरे नंबर पर रखकर किसाऊ डैम को बनवाने के लिए प्रयत्न करें, तभी हम यमुना जल समझौते का लाभ उठा सकेगे वर्ना हमें उसका नुकसान उठाना पड़ेगा किसाऊ डैम 10 साल नहीं बना तो हरियाणा की जनता को इसका नुकसान भूगतना पड़ेगा। आज हरियाणा के अंदर एस० वाई० एल० की बात है। मैं नहीं समझता कि एस० वाई० एल० बनने में किस किस्म की क्या रुकावट है? केन्द्र सरकार चाहती है, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं और हम भी कई बार मिले है वे इस बात के लिए बड़े प्रयत्नशील हैं। पंजाब के अंदर ऐसा माहोंल भी बनता जा रहा है, हरियाणा भी चाहता है आखिर रूकावट किस बात की है। पंजाब का बजट आया है उसमें पिछले साल भी 10 करोड़ रुपये का प्रौविजन एस ० वाई० एल ० के लिए था और इस बार भी 10 करोड़ रु पये का प्रौविजन है इस हिसाब से एस० वाई० एल० अगले साल भी बनने की स्थिति मे नहीं होगी। आप जहां एस० वाई० एल० बनाने का प्रयत्न करें वहीं दूसरी ओर यह भी देखें कि और कौन से जल साधन हैं जिनको हरियाणा की जनता के लिए, हरियाणा के किसान के लिए जुटा सकते हैं। मैंने कई बार यह बात

उठाई है कि घग्घर, मारकंडा और टांगड़े। नदी पर दो महीने मानसून के दिनों में कई लाख क्यूसिक पानी बेकार बह जाता है बल्कि कई जगह धग्धर का जो ओटू का इलाका है, वह फ्लड की स्थिति में आ जाता है। क्या इस पानी को हम कहीं बैराज बनाकर, रोककर अम्बाला के किसान, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र के किसानों को फायदा नहीं पहुंचा सक्ते हैं, अवश्य पहुंचा सकते हैं और जो इस बैल्ट में जल स्तर पानी का नीचे जा रहा है वह ऊपर आ सकता है। इम बैल्ट को हम राइस बैल्ट कहते हैं, व्हीट बैल्ट कहते हैं यह पानीपत तक हमारी बैल्ट है। मैं चाहता हूं कि बैराज बनाकर इस पानी कौ रोकने का प्रावधान किया जाए। अफसोस इस बात का है कि बजट का 72 परसैट सिर्फ तनख्वाहों पर जाता है बाकी 28 परसैंट से ये क्या नहरों की गाद निकालेंगे और क्या करेंगे। जैसे रामबिलास जी ने जीन्द के एक राम बिलास का नाम लेकर बड़ा कुछ कह दिया कि उसका अपहरण हो गया। मैं उन से कहूंगा कि रामविलास जी, अगर आपके पास पूरे तथ्य न हों तो कम से कम आप बोला न करें। आपको जीन्द के रामविलास के बारे में पूरी तरह से पता होना चाहिये कि इस केस की 6 एस० पीज० ने जांच की है और छःके छः एस० पीज० ने यह लिखा है कि जो यह कमप्लेनेन्टस हें ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं कि वह आदमी गायब है, मिसिंग है। मिसिंग और किडनैपिंग में बड़ा ही फर्क है। जो आदमी मिसिंग है, उसके बारे में यह तथ्य सामने आया कि वह नैटली डिस्टबर्ड था और इस मामले में यू ही प्रतिष्ठित आदमियों को तंग किया जाए, यह ठीक नहीं है। कोई तथ्य यह नहीं बोलता कि आप सरकार को गाली निकालते रहें और कुछ भी सरकार के खिलाफ कहें और हम बैठकर आराम से सुनते रहे', यी नहीं हो सकता।

प्रो० रामबिलास शर्माः चेयरमैन महोदया, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जीं का गुस्सा तो कहीं और है और झाडू मेरे पर डाल रहे हैं। जहां तक इन्होंने तथ्यों की बात कही है, मेरे पास जनसता जोकि एक प्रतिष्ठित अखबार है, उसकी कटिंग है और यह 8 दिसम्बर, 94 की कटिंग है, हिन्दुस्तान अखबार को कटिंग है और यह बूलन्दर किसान अखबार जोकि वहां का स्थानीय अखबार है, उसकी कटिंग मेरे पास मौजूद है। जो मैंने पढ़कर सुनाया है 14– 11 – 94 को मुख्यमन्त्री महोदय के पास 100 से ज्यादा लोगों ने इस बारे में लिख कर भी दि या ओंर मुख्यमन्त्री जी ने जो आर्डर उस पर किये, वे भी मैंने पढ़कर सुनाये हैं। फिर ये कहां से आ गया कि वह आदमी मैन्टली डिरेल्ड है। एक आदमी का अपहरण हो जाए जिसके लिये बार बार लोग मांग कर रहे हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिये। यह तो एक नौजवान है चेयरमैन महोदया, यहां पर तो लड़कियां गायब हो जांच हैं और यहां पर जैसा कि पिछली बार कह दिया गया था कि फलां लड़की का करैक्टर ठीक नहीं था। चेयरमैन महोदया, ये लोग अपनी सरकार की तारीफ करें, परन्तु कम सै कम हमारे ऊपर इल्जाम मत लगाएं कि हम जो कुछ कह रहे हैं, वह सही नहीं हे गयो के आ धार पर कहा करें। मैंने जो कुछ कहा है, वह सब तथ्यों के आधार से कहा है। जो जो अखबारों की कंटिग मेरे पास मौजूद है और लोगों की इस बारे में मांग भी यही है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, तो इससे ज्यादा तथ्य और क्या हो सकते हें। बाकी मागे राम गुप्ता जी यहां पर बै ठे हैं, इनके जीन्द हल्के की यह बात है, वे बता देंगे।

श्री मांगे राम गुप्ताः चेयरमैन महोदया, रामबिलास जी अमूमन जीन्द आते जाते रहते हैं और 19 तारीख को ये जीन्द गये भी थे। यह कहते हैं कि 100 आदमियों ने मुख्यमन्त्री महोदय को दरख्वास्त दी थी। पता नहीं

उस पर कितनों ने साईन किये थे और उन्होंने यह कह दिया कि जांच करो और मुझे जवाब दो। आपको पता ही है कि जांच तो अधिकारियों ने ही करनी है। चेयरमैन साहिबा यह असलियत है कि यह किडनैपिंग का केस नही हे। यह कोई बच्चा नहीं है, 40 सालों का वह नौजवान है, कारोबार करता है। जोकि एक बार नहीं, तीसरी बार गया है। वह अपने ही लैवल पर जाता है। वह मैन्टली ठीक नहीं हे। ओर उसके फादर को भी ये अपोजीशन के लोग बरगलाते हैं। उस को ये कहते रहते हैं कि आप इनके खिलाफ दरख्वास्त दो। उसने तो मेरे खिलाफ भी दोष लगाया है कि गुप्ता जी का भी उसको ग्रिसिंग करने में हाथ है। चेयरमैन महोदया, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें किसी का भी हाथ नही है। वह खुद ही जाता है। पहले वह जब गया तो दो महीने के बाद आया, फिर साल डेढ़ साल के बाद आया और अब भी पता नहीं वह कितने दिनों में वापिस आ जाएगा। मैं नहीं कह सकता कि इसमें कोई गल्त बात हुई है। (शोर)

प्रो० राम बिलास शर्माः चेयरमैन महोदया, वे लोग कल ही मुझे मिले हैं। (शोर) उन्होंने मुझे बताया है। जिस तरह ये सरकार अब कह रही है, उसी तरह सुशीला कांड के बारे में भी कहती थी। (शोर)

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः चेयरमैन महोदया, मैंने जो बात कही है, वह पूरी इंफर्मेशन के आधार पर ही कही है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गल्त बात हुई होगी। मैं तो राम विलास जी को कहूंगा कि जो आप देखते हैं यही सब दुनिया नही है। दुनिया बहुत बड़ी है। आज ये लोग यहां पर क्योड़क के हरिजन परिवारों की बात कहते हैं। अब अगर राजनीतिक बात मैं उठाऊंगा तो बात बहुत लम्बी हो जाएगी (शोर)। मैं तौ यही कहूंगा कि यह न तो मिसिंग है, न ही क्डिर्नौपंग है और न ही इसमें किसी का हाथ हो है।

पुलिस ने पूरी तरह से जांच कर ली है। अच्छे से अच्छे इज्जतदार आदमियों का नाम इस केस के बारे में उस लिस्ट मैं रखा गया था और पुलिस ने उनकी तसल्ली करने के लिए इन सारे इज्जतदार आदमियों को पूरी तरह से इटेरोगेट किया है और कोई इस में अन्याय की बात नहीं हुई है। ये लोग खुद भी इस बात की जांच जाकर करें कि आखिर यह माजरा क्या है तो इनेको तसल्ली हो जाएगी। जितने आप और आपकी पार्टी गरीबों की हमदर्द है, वह हमें पता है। किस तरह से आपने मेवात में वातावरण को खराब करने की कोशिश की थी। किस कदर आपने अपने भाषणों में बातें कही थी।

प्रो० राम बिलास शर्माः चेयरमैन महोदया, चौधरी वीरेन्द्र सिंह ने फरमाया है कि मेवात में हमने वातावरण खराब किया। हमने वातावरण कैसे खराब किया? वहां पर एम ० एल० ए० तो आपके हैं और मन्त्री आपके है। वहां पर जब मन्दिर तोड़े गए तो इनके मन्त्रियो पर वह बात आई। वहां पर 595 आदमियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे।

श्री अजमत खांः चेयरमैन महोदया, अच्छा यह होगा कि यहां पर मेवात का जिक्र न करें वरना इनके दिए हुए घाव तो अभी भरे नहीं हैं।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः तो चेयर पर्सन साहिबा, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब मैंने लिब्रलाइजेशन की बात की तो मैंने शुरु में यह कहा कि सरकार की कंसेप्ट को बदलना होगा। ये कहते हैं कि हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी के अलावा और बड़ी जिम्मेदारी थी जिसको हम समाजवाद के तहत निभाते थे और अब भी हम कायम हैं। लेकिन चाहे दुनिया के अन्दर लिब्रलाइजेशन की बात चले, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज सरकार की सबसे बडी जिम्मेदारी तीन बातों पर है। सबसे पहले ला एण्ड आर्डर, दूसरी शिक्षा के बारे में और तीसरी स्वास्थ्य के बारे में। मैं

फाइनैस मिनिस्टर साहब को कहना चाहता हूं कि इन तीन बातों पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आज शिक्षा का स्तर क्या है। माफ करना हम यहां जोर शोर से कहते है कि हमारे यहां कितने स्कूल अपग्रेड होंगे, दस से 12 कितने होंगे। अभी गुहला चीका के भाई कह रहे थे उनके यहां दस से 12 का स्कूल बन गया। देखने की बात यह है कि आज शिक्षा का स्तर क्या है। हरियाणा का बच्चा अगर दस या 12 जमात पढ़कर अगर अर्जी भी न लिख सके तो वह क्या शिक्षा है। यह ठीक है कि वह दस जमात पढकर कहेगा कि मुझे क्लर्क लगा दो, पुलिस में भर्ती कर लो या चपरासी लगवा दो। लेकिन आज हमारी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। इस बदलते हुए. समाज में अगर हम बच्चों को सिर्फ चपरासी लगाएने या पुलिस में भर्ती करवाएंगे या छोटी नौकरियां देंगे तो कौन आदमी हमारे ऊपर राज करेगा। राज वह करेगा जो अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। अगर हम आज हरियाणा के बच्चों को शिक्षा में पीछे रख देंगे तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों से सब से बड़ी गद्दारी करेंगे। इसलिए जरूरी है कि जो प्राइमरी शिक्षा है उसके लिए यह एनश्योर करें कि गांव में पढ़ाने वाले जो अध्यापक है उनका कैलिबर हो और उनकी अपनी सोच हो। वह टीचर उतना ही विद्वान हो जितना शहर में पढ़ाने वाला टीचर है। इसको हम तभी कर सकते हैं जव हम अध्यापकों की सिलैक्शन के बारे में सोचेंगे। आज फर्स्ट और सैकिंड डिवीजन वाले भाग रहे हैं कि दें जे ०बी ०टी ० बन जाउंगा। आज सब से ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे एम० बी ०ए० के बारे में सोचते हैं। उसके बाद मैडिकल के बारे में सोचते हैं, उसके बाद इंजिनियरिंग के बारे में और उसके बाद आई० ए ०एस० के कम्पीटीशन के बारे में सोचते हैं। अभी पीछे खबर आई थी कि देश की फौज में दस हजार से ज्यादा अफसरों की' कमी बढ़ गई है। लड़

के वहां जाना पसन्द नहीं करते। लेकिन बुद्धिजीवियों का क्रेज एम ०बी० ए ० में है। जो एम० बी०ए० की ट्रेड है उसमें हरियाणा प्रदेश का बच्चा नहीं आ सकता क्योंकि उसको यह पता ही नहीं है कि एम०बी०ए० क्या है और आई० ए०एस० क्या हे? मैं कोई जातिपाति की बात नहीं करता। सवाल आता है कि हरियाणा प्रदेश की जो 3० हजार पुलिस फोर्स है उसमें 25 हजार सिपाही हैं अगर उनमें कोई जैन जाति से हो तो आप बता दें अगर है तो मैं गलत राजनीति कर रहा हू लेकिन जैन जाति से कोई नहीं है। आज हमारे समाज मैं हरिजन कब तक पिसते रहेगे, दलित वर्ग के लोग कब तक पिसते रहेंगे और बैक्ग्वर्ड क्लासिन के भाई कब तक पिसते रहेंगे। जब कोई लोग लेने की बात हो तो कह दिया त्राता है कि नही साहब आपको बैक से इतना लोन नहीं मिल सकता क्योंकि आप इतनी बड़ी नई फैक्टरी नहीं लगा सकते लेकिन जिस किसी ने पहले से बड़ी फैक्टरी लगाई हो या उसके बाप दादा ने बड़ी फैक्टरी लगाई हौ उसको पूरी इजाजत है कि वह जितना मर्जी कर्जा ले ले। आज हमें सोचना पडेगी कि वह हरियाणा का गरीब आदमी जिसको गरीबी के रेखा से ऊपर उठाने की बात करते हैं चाहे वह किसान हो, चाहे वह दलित वर्ग हो और चाहे वह हरिजन हो उसको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की बात करते हैं। मैंने इस बारे में मुख्य मती जी को एक डेढ़ साल पहले सलाह दी थी लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मेरी उस बात में सत्यता थी। मैंने मुख्य मंत्री से यह कहा था कि आप दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दें। एक हरिजन वर्ग से और एक बैकवर्ड क्लास से।

12.00 बजे

श्री सभापतिः चौधरी साहब, आप वाइंड अप करें आपको बोलते हुए आधा घंटा हो गया है।

श्री कर्ण सिंह दलालः चेयरमैन साहिबा, मैं आपके माध्यम से चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी को सुझाव दूंगा। वह हरिजन और बैकवर्ड क्लास की बात करते हैं, मैं कहूंगा कि एक महिला को भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः महिलाएं तो टू इन वन भी हैं और हमारी बहन करतार देवी जी तो थ्री इन वन हैं। वह हरिजन भी हैं, मंत्री भी हैं। और पढी लिभी भी है। उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही है कि एक महिला भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बननी चाहिए। एक वात मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे बच्चों को इस किस्म की शिक्षा मिल रही है जिसके कारण वे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारी तरक्की की जो रफ्तार है, जो तरक्की की दौड़ है, उसमें हमारे हरियाणा प्रदेश के बच्चे, गांवों के बच्चे पीछे रह जाएंगे। सारा पैसा चन्द हाथों में सिमट कर रह जाएगा। चाहे वह कोई राजनीतिक हो और चाहे कौई सामाजिक हो उसके पास पैसे की ताकत रह जाएगी। मैं सरकार से यह पुरजोर सिफारिश करता हूं कि सरकार शिक्षा पद्धति को सुधारे। चाहे वह टीचर्ज की सिलैक्शन है और चाहै वह बच्चों के एडमिशन हैं। इन बातों के बारे में पुनर्विचार करने की जरूरत है। बहन करतार देवी स्वास्थ्य मंडी हैं। मैं इनकी बात कहना चाहूंगा कि गांवों के अन्दर जो पी ०एच०सीज ० हैं अगर उनमें किसी डाक्टर का ट्रांसफर कर दिया जाता है तो वह यही कोशिश करेगा कि वह वहां न जाए और वह दो महीने का डैपुटेशन करवाना चाहता है जैसे रोहतक जिले के डिग्गल गांव के पी ०एच०सी० में किसी डाक्टर का ट्रांसफर कर दिया जाता है तो वह रोहतक डैपुटेशन करवाने की कोशिश करता है। राजौन्द के पी ०एच०सी० में किसी डाक्टर की ट्रांसफर की जाती है तो वह कोशिश करके कैथल

डैपुटेशन करवाता है। आप इस बारे में विचार करें कि ऐसा क्यों है। गावों में बहुत ज्यादा मौतें होती हैं और आजकल तो खास करके गांठों में यह सिस्टम चल गया हैं कि गांवों में सलफास की गोली खा करके अनेको लोग मरते हैं। अगर किसी जगह पर अच्छा डाक्टर हो तो और अच्छी देखभाल करने वाला डाक्टर हो तो उन सलफास की गोली खाने वाले लोगों को बचाया भी जा सकता है। जो हम एक स्वस्थ समाज की संरचना करना चाहते है। वह समाज भी कायम कर सकते हैं। एक बात में पुनर्विचार के लिए कहना चाहता हूं। मुख्य मैली उस पर गौर करें। आप हरियाणा के अन्दर ऐसे अदायरे कायम करें जिसमें बच्चों को ऋण दिया जाये। उसको छौटी मोटी फैक्टरी लगाने के लिए और बड़ी फैक्टरी लगाने के लिए धन की उपलब्धता करायी जानी चाहिए ताकि वह अपना काम अच्छी प्रकर से कर सके। सरकार को इसे पूर्ण सहानुभूति के साथ देखना होगा। जो मान्यताएं आज तक हमारी कायम हैं, उनको एक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है ताकि हरियाणा में औद्योगिक क्रांति हरियाणा से बाहर जाने की बजाये यही पर रह सके और यहीं के बच्चे लाभ उठा सके। यही मैं आपसे कहना चाहता था। धन्यवाद।

चौधरी भजन लालः चेयरमैन साहिबा 5– 10 मिनट एक दो मैम्बर को बोलने देने के बाद मुझे भी बौलने का समय दे दीजिए क्योंकि पूरा जवाब तो कल वित्तमंत्री जी देगे लेकिन कुछ मुझे शेयर मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहूगा, इसलिए आप धण्टा मुझे भी समझ चाहिए।

अनेक आवाजेंः हमें भी बोलने का समय चाहिए।

श्री सभापतिः आपको मौका देंगे, आप बैठिये। अगर जरुरत हुई तो हम समय बढ़ा लेंगे।

श्री जय सिंह राणा (नीलोखेड़ी): आदरणीय सभापति महोदया, 13 मार्च को जो बजट हरियाणा के वित्त मंत्री महोदय ने सदन में पेश किया है इस पर उसी दिन से चर्चा चल रही है। सभी सदस्यों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए है। मैं भी अपने विचार व्यक्त कदने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार बधाई की पाल है और वित्त मंत्री भी बधाई के पाव हैं कि इस बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया। जो राहत, सुविधाएं किसानों को व्यापारियों को मिल रही थी उनको जारी रखा गया है। किसी पर किसी प्रकार की सबसिडी हटायी नहीं गई। चेयरमैन साहिबा, बहुत से सदस्यों ने इस बजट को जनविरोधी बजट बताया है। इस बजट में कोई जन विरोधी बात नहीं है। इस बजट में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो जनता के हित में न हो। यह सारे का सारा बजट दर्शाता है कि इसमें जनता के हितों का तथा हर वर्ग के कल्याण का ख्याल रखा गया है। हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और इस प्रदेश की 82 परसैंट जनसंख्या ग्राणीण क्षेत्रों में रहती है। इस बजट में किसानों का पूरा ध्यान रखा गया है 70 परसैंट बजट ग्रामीण इलाकों मे खर्च करने का प्रावधान बजट मे रखा गया है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्री का खासकर ध्यान इस बजट में रखा गया है। चेयरमैन साहिबा, जहाँ तक किसानों का सवाल है, किसान की जो जरूरतें हैं चाहे वह बिजली है, चाहे वह खाद है या किसान के काम आने वाली कोई दूसरी सामग्री है, इस बजट में उसका पूरा ध्यान रखा गया है। नहरों के लिए बजट में 19.9 परसैंट कुल बजट का हिस्सा दिया गया है। इसी तरह से खाद तथा कृषि उपकरणों पर जो सबसिडी पहले से ही मिली हुई हे, वह सबसिडी जारी रखने का प्रावधान इस बजट में है। चेयरमैन साहिबा, पानी की बात नम्बर एक पर आती हे क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश में नहरों का पानी होना बहुत

जरुरी चीज है और इस बजट में इसका पूरा ध्यान औंर विचार रख। गया है। मै मुख्य मन्त्री जी को वधाई देना चाहता हू जिन्होने यमुना जल समझौता करके एक महान कार्य किया है। यह समझौता एक ऐतिहासिक समझौता है जिससे प्रदेश को बहुत लाभ पहुचेगा। इस समझौते की आधारशिला हथनीकुण्ड में रखी गई। यह बहुत ही अच्छा फैसला हुआ है जिससे किसान के खेत में और अधिक पानी पहुंचेगा और उसकी उपज अधिक बढ़ेगी जिससे किसान के खेतों में हरियाली होगी चार उसके चेहरे पर रौनक होगी। चेयरमैन साहिबा, एस ०वाई०एल ० का जिक्र बार–वार सभी सदस्य सदन मे करते रहे हैं, सभी राज नैतिक पार्टियां करती रही है, चेयरमैन साहिबा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। एस० वाई० एल० का पानी हरियाणा की धरती पर आना बहुत जरूरी है। असल में तो इसकी शुरुआत ही गलत ढंग से हुई। चाहे कोई भी मुख्यमन्त्री रहे हो या सरकार रही हो उस वक्त टसने गौर नहीं किया। इस नहर की शुरुआत टेल से की गई जब कि इसकी शुरुआत हैड की तरफ सें की नानी चाहिए थी। यदि इसकी शुरुआत टेल की बजाय हैड की तरफ से की गई होती तो आज यह समस्या पैदा ही न होती और ये दिन न देखने पड़ते। एस०वाई० एल० का पानी कई वर्ष पहले ही हरियाणा में आ चुका होता। चेयरमैन साहिबा, 1987 में हरियाणा में जो सरकार बनी थी उसने हरियाणा की जनता को यह नारा दिया था और इस नहर को बनाने का वायदा किया था इसी वायदे पर वह सरकार बनी थी। उस सरकार ने लोगों से वायदा किया था कि एस०वाई०एल० का पानी हरियाणा में ला कर देंगे। चेयरमैन महोदया, जैसे कि आप स्वयं भी जानती है कि उस समय जैसा नहर बनाने का अच्छा मौका शायद हरियाणा में कभी दौबारा न आए। उस वक्त केन्द्र में भी वही सरकार थी और हरियाणा प्रदेश में भी वही

सरकार थी। जिसका पिता केन्द्र में डिप्टी प्राईमिनिस्टर था और स्टेट में बेटा प्रदेश का मुख्य मन्त्री या। (विध्न) ज्य समय पंजाब की बागडोर गवर्नर के हाथ में थी, जो मर्जी कर सकते थे लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं थी कि हरियाणा की धरती पर पानी आए। अगर वे चाहते तो ले सकते थे, लेकिन इन्होंने यह कोशिश नहीं की क्योंकि पानी आने से मुद्दा ही खत्म हो जाता है और वोट मांगने का यह साधन ही खत्म हो जाता। (विघ्न) चेयरमैन महको, आज वर्तमान सरकार ने प्रयास किया है और कर रही है कि हरियाणा के किसानों को पानी मिले। अगर इन प्रयासों में ये हमारे सहयोगी बनते और पूरा सहयोग देते तो काम हो सकता था। इनकी तो खुद की नीयत ठीक होनी चाहिए थी कि हरियाणा की धरती पर एस० वाई०एल० का मानी आए। यह सबकुछ हो सकता था और हो सकता है। लेकिन इनकी तो सहयोग देने की नीयत ही सहीं रही है। सिंचाई के बारे में मैं और भी कहना चाहता हूं, वित्तमंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं जिन्होंने बजट मैं नहरों के लिए काफी फण्ड एलाट किए हैं, फिर भी मरो इनसे अनुरोध है कि टेल तक पानी पहुंचाने के लिए, नहरों की खुदवाई के लिए और फण्ड दे ताकि टेल तक पानी पहुंच सके। बाढ़ के वक्त भी फसलें नष्ट हो जाती हैं, इसलिए ड्रेनों की खुदवाई के लिए भी ये फण्ड दें। चेयरमैन महोदया, पिन्से दिनों निगटू में मुख्यमंत्री जी ने अनाज मण्डी का शिलान्यास किया है, मगर वहां पर ड्रेन नहीं है। अगर ड्रेन नहीं बनी तो वहां पर रखी फसल का काफी नुक्सान हो सक ता है, व्यापारी भी वहां पर नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए मेरा इनसे अनुरोध है कि निगटू से पुण्डरी तक ड्रेन ले जाएं।

चेयरमैन साहिबा, बिजली मंत्री भी यहां पर बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने सोच–समझकर एक योग्य व्यक्ति को यह महक्मा दिया है। (विध्न)

इनका इस बारे में पहले भी तजर्बा है और उनमें योग्यता भी हए। इन्होंने जब से इस कार्यभार को सम्भाला है तो इनका ज्यादा से ज्यादा प्रदाम यहीं रहा है कि सबको बिजली मिले, विशेषकर किसानो को ज्यादा से ज्यादा बिजली मिले। (विघ्न) किसानों को बिजली मि ली भी है। मेरा बिजली मती जी से भी अनुराध है कि मेरे हल्के में दो सब–स्टेशन्ज ऐसे हैं जो 33 के वी के हैं, उनको तो 132 के बी. का बनाने का काम कुछ तो हो चुका है और कुछ पड़ा हुआ है। हमारा जीरी और पैडी का सीजन आ रहा है, इसके शुरु होने से पहले ही 132 के ०वी ० का सब–स्टेशन बनाने का कार्य कर दें ताकि किसानों के ट्यूब–बैल्ज को बिजली मिल सके। चेयरमैन महोदया, कृषि के बारे मे मैं यह कहना चाहता हूं कि जब से यह सरकार आई है तो कृषि के क्षेत्र में किसानों को ठीक भाव मिले हैं, अच्छी फसलें हुई हैं। मैं भी खुद किसान हूं, ग्हेती के अलावा मैंने कोई दूसरा काम ही नही किया है। मेरा खेती का ही काम है। (बिध्न) चेयरमैन महोदया, लोग तो गुमराह भी करते हैं।

श्री सभापतिः राणा जी, आप लोग आपस में बात न करें और आप जल्दी ही वाईडअप करें।

श्री जब सिंह राणाः जहां तक किसानों की आर्थिक स्थिति का सवाल है, चार साल में फसलों के भाव की वजह से और अच्छी फसल होने की वजह से आर्थिक स्थिति में सुधार आना है। मार्केटिंग बोर्ड ने भी किसानों को राहत पहुंचाने के विप्र काफी कार्य किम् हैं, जैसे सड्कों का काम ही मार्केटिंग बोर्ड ने काफी किया है। किसानों की फसलों को मंडी तक लाने के लिए जो रास्ता बनाने का काम मार्केटिंग बोर्ड ने किया है वह बहुत सराहनीय है। इस बोर्ड ने ऐसे ऐसे रास्ते बनाएं हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं

सकता था लेकिन मार्केटिंग बोर्ड ने उन रास्तों को बनाकर किसानों को सुविधा पहुंचाई है। आज किसान भी इस बात को मानते हैं। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि अब भी काफी रास्ते ऐसे हैं जिनमें किसान अपनी फसल तो क्या, पशुओं के लिए चारा भी नहीं ला सकते हैं, इसलिए ऐसे रास्तों को भी सरकार को बनाना चाहिए। जिन मार्केट कमेटियों में अपने फंड हैं, वे किसानों की भलाई के लिए ही है इसलिए इस पैसे को किसानों की भलाई में लाने के लिए किसी किस्म की देरी नहीं करनी चाहिए और उस काम को पूरा करना चाहिए। यह मेरा एक सरकार को सुझाव है (विघ्न)

चेयरमैन साहिबा, अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने बड़े भारी कार्य किए हैं। मैं पिछली बार भी इस सदन का सदस्य था इसलिए मुझे पूरा पता है कि जब यह वर्तमान सरकार आयी थी तो उस समय हर तरह के स्कूलों में हर कैटेगरी के टीचर्ज के खाली पद पड़े थे जिनको भरने की कोशिश पिछली भरकर ने नहीं की थी। मुझे पता नहीं कि उसका क्या कारण रहा होगा। उसका कारण तो ये स्वयं ही जानते होंगे। लेकिन वर्तमान सरकार आने के बाद चौधरी भजन लाल जी ने जब इस प्रदेश की बागडौर सभाली तो उसके बाद बहुत से खाली पदों को भरा है और बकी भी जो खाली पद पड़े हुए हैं उनको भी भरने की कोशिश की जा रही है। यह कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि यह तो बहुत बड़ा कार्य है। खासतौर पर देहातों के स्कूलों मे तो टिचर्ज के पद बिल्कुल ही खाली पडे थें जहां दस टीचर होने चाहिए थे तो वहां पर दो ही मिलते थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने कन्याओं के लिए बी०ए० तक की शिक्षा मुक्त की है। चेयरमैन साहिबा, यह बहुत बडा निर्णय इस सरकार ने लिया है। ऐसा करने से शिक्षा का बहुत प्रसार होगा। मैं सरकार से यह भी चाहूंगा कि दस जमी

दो स्कूलों की आज बड़ी जरूरत है। मेरे अपने हल्के में ही नीलोखेड़ी और तरावड़ी दो बड़े' कस्बे हैं। वहां तो स्कूल हैं लेकिन देहातों में किसी भी गांव मैं दस जमा दो का स्कूल नहीं हैं इससे बड़ी भरि। असुविधा बच्चों को होता है क्योंकि वे दसवी पास करने के बाद कहां जाएं। इसलिए मैं सरकार से कहूगा कि वह ऐसा क्राईटेरिया बनाए कि देहाती क्षेत्रों में पांच किलोमीटर के अदर अंदर कम से कम एक दल जमा दो का स्कूल जरूर खोला जाए जिससे विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए 5 कि ० मी ० से दूर न जाना पड़े। मैं अनुरोध करूंगा कि मेरे हल्के में शामगढ़, अमीन और तरावड़ी में एक हाई स्कूल है, उसका दर्जा बढ़ा कर 10 जमा दो का किया जाए। (घण्टी) चेयरमैन साहिबा, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

चौधरी बलवन्त सिंह मायनाः चौयरमैन साहिबा, मैंने अपनी बात कहनी है मुझे भी बोलनैं का टाइम दीजिए।

श्री सभापतिः आपको भी बोलने का समय मिलेगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल): चेयरमैन साहिबा, हरियाणा के वित्त मन्त्री की तरफ से पिछले दिनों जो बजट प्रस्ताव रखे गए थे वह मूठ का पुलिन्दा था। हमारे माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने इस तरीके से हरियाणा के इस महान सदन में कागजों का पुलिंदा रखा जिसमें अखबारों के जरिए स्वयं भी इस बात का इजहार किया कि हरियाणा में कोई कर नही लगाया गया, जो सुविधाएं दिखा सकतै थे, दिखाने की कोशिश की लेकिन मैं यह बात दावे से नह सकता हूं कि जब से मौजूदा सरकार ने हरियाणा के लोगों की कमान संभाली है, हरियाणा के लोगों की दिक्कतें व समस्याएं बढ़ती जा रही है। हरियाणा के लोगो का जीवन स्तर नीचे गिरता जा रहा है। मैंसे इस सदन में बार बार एक बात कही है, आप सभी जानते हैं कि जो प्रजातन्त्र की

नींव रखी गई थी, उसका जो मूलभूत सब्जैक्ट मैटर था, वह यह था कि खून का जो रिश्ता है, वह विचारों के रिश्ते से पतला है। विचारों का संबंध गाढा है, खून का रिश्ता इतना गाढ़ा नहीं है। हरियाणा के लोग न जाने कितनी उम्मीदों से लोगों को, नुमाइंदों को चुनकर इस विधान सभा में भेजते हैं कि वे जाकर उनकी समस्याएं वहा उठाएंगे। लेकिन आप जानती हैं कि हरियाणा में जो नुमाइंदे हैं, खासकर सत्ताधारी पक्ष के भाई हैं, वे किस तरीके से प्रजातन्त्र का मजाक उडा रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने नहरों के बारे इस बजट में जिक्र किया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हमारे जिला फरीदाबाद के लोगों ने ऐसा क्या कसूर कर रखा है कि उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता। वित्त मन्द्री जी चौथा, पांचवां बजट इस सदन में रख रहे हैं। मै हमेशा एक बात कहता हूं और मुख्यमंत्री की मेरी बात बुरी लगती है। फरीदाबाद और मेबात में बिश्नोई की एक भी वोट नहीं है, वहा की जनता की तारीफ करनी पड़ेगी कि इनको वहां से संसद सदस्य चुना। हमारे जिला फरीदाबाद की और मेवात की कोई समस्या ऐसी नहीं जिसके लिए इन्होंने वायदा न किया हो।

(इस समय सभापतियों की सूची मे से एक सदस्य श्री मनी राम केहरकला पदासीन हुए।)

श्री राजेन्द्र सिह बिसलाः सभापति महोदय, मेरा प्यायंट आफ आर्डर है। मैं आप के माध्यम से इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि चौधरी भजन लाल जी के नेतृत्व में पिछ ले चार साल में, फरीदाबाद जिले में जितना काम हुआ है, उतना तो जब से हरियाणा बना है तब से नहीं हुआ था। मुख्यमन्त्री जी पिछलीं 26 तारीख को मोहना ग्रांम में यमुना के पुल का शिलान्यास करके आए है, जिसकी कास्ट 10 करोड़ रुपए है। मैं मुख्यमन्त्री

जी को, इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। फरीदाबाद जिले में जितना हमारा हिस्सा बनता है, इससे ज्यादा विकास के काम करवा दिए हैं, किए हुए काम के लिए धन्यवाद करना चाहिए, अहसान मानना चाहिए। आप विपक्ष के सम्मानित सदस्य हैं, विपक्ष का भी रोल बड़ा जरूरी है। जो काम इन्होंने किए हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहिए।

श्री कर्ण सिंह दलालः सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से और सारे सदन से प्रार्थना करता हूं कि बजट में जो एस ० वाई० एल ० नहर का जिक्र हुआ है, एस ० वाई० एल० हमारे जिला फरीदाबाद की किसी नहर के माध्यम से नहीं जाएगी। हमारे फरीदाबाद और मेवात एरिया को किसी नहर से अगर फायदा होगा तो वह आगरा नहर से होगा। सभापति महोदय, मुझे इतना दु:ख है कि जो बजट इन्होने पेश किया है उसमें इन्होंने नहरों का जिक्र किया है लेकिन हमारे मेवात और फरीदाबाद इलाके की जितनी नहरें हैं, वे सारी की सारी सूखी पड़ी हैं। अगर सरकार इस इलाके के प्रति चिंतित हो तो क्यों न इस इलाके की बहबूदी के लिये पैसा खर्च करे लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान ही नही है यह भी पता चला है कि यू० पी ० सरकार तो आगरा कनाल का नियन्त्रण हरियाणा को देना चाहती है लेकिन हरियाणा सरकार इसके लिये इच्छुक नहीं है (शोर) हरियाणा सरकार ही आगरा कैनाल का प्रबन्ध अपने हाथ में नहीं लेना चाहती। सारे का सारा पैसा हिसार, सिरसा और खासतौर से आदमपुर में ही सरकार खर्च कर रही है। दूसरे इलाकों के बारे में सरकार चितित नही है।

सिचाई मन्त्री(चौधरी जगदीश नेहरा): चेयरमैन महोदय, दलील सहिब यू ही इधर तक दर की बातें कह कर हाउस को मिस–लीड कर रहे है कि हरियाणा सरकार आगरा कैनाल का नियन्त्रण अपने हाथ मे नही लेना

चाहती और यू. पी. सरकार हमें इसका नियन्त्रण देना चाहती है। आगरा कैनाल का नियन्त्रण हमारे हाथ में आए, इस बारे में 1975 में मीटिंग हुई, और उनका उत्तर भी मैंने इनको पढ़ कर सुनाया था। उसके बाद फिर 1988 मे मीटिंग हुई, फिर 1989 मे हुई, और फिर मुख्य मन्त्री की 1992 में मीटिंग हुई। हम तो लगातार यह कोशिश करते रहे हैं कि आगरा कैनाल का प्रबंध हरियाणा सरकार के पास आ जाए तो फिर ये किस आधार पर यह कह रहे हैं कि हम आगरा कैनाल का प्रबन्ध लेने में इच्छुक नहीं है। यह सब निराधार बाते हैं।

श्री कर्ण सिंह दलालः चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से मुख्यमन्त्री महोदय, वित्तमन्त्री व सिंचाई मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि अगर वे सचमुच में फरीदाबाद के इलाके के साथ सहानुभूति रखते हैं तो आगरा कैनाल का नियन्त्रण अपने हाथ में ले कर के हमारे इस इलाके के किसानों के खेतों को पानी दिलवाने की व्यवस्था करें ताकि किसानों को थोड़ी सी राहत मिल सके। उस आगरा कैनाल का पानी हमारे सामने से हमारी छाती से होकर गुजरता है, हमारा किसान बेचारा सामने खड़ा देखता रहता है लेकिन हमें उस पानी को इस्तेमाल करने की इज। जस नही है। किसानों के खेत इस पानी के बगैर सूख रहे हैं। जब तक हमारी सरकार इस आगरा कैनाल का नियन्त्रण अपने हाथ में नही लेती तब तक इस इलाके का विकास नही हो सकता। मैं एक बात और बताता हू कि हमारे इलाके में होडल व हसनपुर डिस्ट्रीब्यूट्रीज हैं और जो अधिकारी इनसे सम्बन्धित है, वे दोनों एक्सीयन व एस० डी ० ओ० मथुरा में बैठते है और लोगो को अपनी प्रोब्लमज के लिए मथुरा जाना पड़ता है।

चौधरी जगदीश नेहराः ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट्रीज आधी उधर पड़ती हैं इसलिये वे वहां बैठते है।

श्री कर्ण सिंह दलालः मैं आपको बताता हूँ कि गुड़गांव कैनाल की पानी की कपैसिटी इस समय 2,240 क्यूसिकस की है, जोकि फरीदाबाद के एरिया को भी फीड करती है और इस समय कहा पर केवल 300 क्यूसिकस पानी ही चल रहा है, उसमें से भी 100 क्यूसिकस पानी थर्मल प्लांट को चला जाता है। इतनो बुरी हालत है। इस को देखकर सरकार खुद ही अन्दाजा लगा सकती है कि हमारे फरीदाबाद जिले के साथ कितना भेदभाव हो रहा है। वहां के किसानों के खेतों के लिये पानी बिछल नहीं मिल रहा है, जिस के कारण किसान बुरी तरह से दुखी हैं। इसके साथ मैं सरकार से यह भी कहूंगा कि आगरा कैनाल और गुड़गांव कैनाल की जो डिस्ट्रीब्यूट्रीज हैं, उन पर जो पुल बने हुए है, उनकी मुरम्मत की भी आवश्यकता है। उनकी डिस्ट्रीब्यूट्री मेरे हल्के मे है और वहां से जो चान्दपुर सब–माईनर के लिये स्कीम इन्होने बनाई है, वह लुक लिफ्ट इरीगेशन की स्कीम है। वहां से मर बिजली चली जातीं है तो पानी पीछे की ओर धक्का मारता है जिससे सिकन्दरपुर गांव में पानी भर जाता है और वह गांव डूब जाता है। हरिजनों के वहां पर हजारों गांव है। वे बेचारे बनाते रहते हैं और उस डिस्ट्रीब्यूट्री का पानी उन्हे डूबो देता है मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार चौनल बनाकर उस पानी को गोछी ड्रेन में डाल दे ताकि वहां के लोग इस पानी के खतरे से बच सके। इससे बडेर का जो इलाका है, उसको भी पानी मिल जाएगा।

इसके बाद मैं चेयरमैन साहिब वित्त मन्त्री महोदय को यह कहूंगा कि यहां पर पंचायत संस्थाओं का भी जिक्र आया। रोजाना इस बारे में बड़े

लेख आते रहते हैं कि जो पैसा पंचायत के लिये सरकार से चलता है, वह सही जगह पर नहीं पहुचता क्योंकि उसका बांटने का अधिकार ए० डी० सीज ० व डी ० सीज० को सरकार ने दे रखा है। मेरा सुझाव है कि क्यों न उस पैसे के सीधा ही पंचायतों को देने की सरकार व्यवस्था करे ताकि वह पैसा ठीक समय पर पंचायतो के पास 'पहुच सके और उस का सदुपयोग हो सके। वहां पर एक ए० डी० सी ० का आफिस या ब्लाक का दफतर है। हो सकता है कि वे एक काम पर एक 'लाख रुपए लगा दें, और उसी काम को पंचायत 50–60 हजार रुपए में कर दे। अखबारो मे रोज लिखा होता है कि अगर एक रुपया यहां से चलता है, तो वह पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाते हैं। तो इसी तरीके से यहां पर एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि फरीदाबाद का बहुत विकास हुआ है। पिछले दिन से ले कर आज तक आठ हजार सिपाहियों की भर्ती हो चुकी है लेकिन हमने आज तक किसी मुख्यालय में भर्ती होती नही देखी। (विघन) चेयरमैन साहब, मेरा आपसे अनुरोध है कि पिछले दिनो महेन्द्रगढ़, के इलाके को बिजली के मामले में सुविधा दी जाती थी। वहां पर पाना बहुत नीचे है इसलिए इन्होंने वहां के लिए बिजली की दरों में रियायत की घोषणा की थी। सुना है अब ये उस रियायत को बन्द करने जा रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो यह गल्त बात है। हमारे बिजली मन्त्री हमारे पूरे इलाके को नही जानते। हमारे बुडेल के इलाके में पानी नहीं है। जो खादर का इलाका है उसमें जल स्तर बहुत नीचा बै। मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे इलाके में रहने वाले किसानों के लिए भी बिजली की रियायती दरों की घोषणा करे। बुडेल में रहने वाले किसानों की एक ही फसल होती है। एक फसल से वे बिजली के बिलों का भूगतान नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस बारे में उनके लिए भी सरकार गौर

करे। चेयरमैन साहब, हमारे फरीदाबाद जिले में एक होडल शहर है। उसके साथ यू० पी ० का एक कोसी शहर है। आप वहां जा कर देखें या सरकारी अधि– कारियों को भेज कर पता करवाएं कि कितने उद्योग वहां पर लग रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार भी उत्तर प्रदेश की तरह रियायत दे कर होडल में उद्योग लगवाएं। अगर सरकार रियायत देगी तो इंडस्ट्रियलिस्टस कोसी की बजाए होडल में अपने उद्योग लगाएंगे। इसी तरीके से चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस हरियाणा के बजाने पर सारे हरियाणा की जनता का हक है लेकिन आज जो विकास के काम हो रहे हैं वे चुने हुए क्षेत्रो में ही हो रहे हैं। हमारे फरीदाबाद में कोई गवर्नमैंट टैक्नीकल एजूकेशन का सैंटर नहीं है, हमारा इतना बडा जिला णै लेकिन वहां पर कोई ऐसा हस्पताल नहीं है जहां हमारे लोग ठीक तरह से ईलाज करवा सकें। वहा पर एक बादशाह खां हस्पताल है लेकिन अगर आप वहां जाते हैं तो क्या आपको उचित दवाइयां मिलती हैं? उचित दवाइयां बिल्कुल नहीं मिलतीं। चेयरमैन साहब, इसी तरीके से हमारे पलवल का जो शूगर मिल है, पिछले से पिछले साल उसका 50 लाख रुपया भूना शूगर मिल को दे दिया गया। चेयरमैन साहब, दो साल गुजर चुके हैं उस पैसे का कहीं कोई जिक्र नहीं है। मैं मुख्य मंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो चूना में आपने 50 लाख रुपया भेज दिया है वह वापिस आना चाहिए।

श्री सभापतिः वह सारा पैसा फार्मर्ज की भलाई के लिए है। जितना पैसा हरकों बैंक से जा रहा है वह सारा फार्मर्ज की भलाई के लिए जा रहा है। किसी दूसरे काम के लिए नहीं जा रहा है। यह बात प्रोसिडिग्ज में भी है।

श्री कर्ण सिंह दलालः चेयरमैन साहब, पलवल की अनाज मंडी एक माना हुई अनाज मंडी है। वह सारे हरियाणा प्रदेश में एक सबसे बड़ी जानीमानी अनाज मंडी मानी जाती है। उस मंडी का जितना पैसा इकट्ठा होता है वह सारा पैसा वहां से दूसरी जगह पर ले जा कर खर्च कर देते हैं। पलवल मार्किट कमेटी ने पिछले तीन चार साल में वहां पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया है। अगर किया है तो फरीदाबाद जिले के जो दूसरे मैम्बर हैं वह बता दें। (विघ्न)

श्री सभापतिः दलाल साहब, आपका टाईम समाप्त हो गया आप बैठ जाए।

श्री कर्ण सिंह दलालः चेयरमैन साहब, मुझे आप दो मिनट का टाईम और दे दें।

श्री सभापतिः नहीं, अब आप बैठिए। अब श्री बलवंत सिंह जी बोलेंगें। (शोर)

वाक आउट

श्री कर्ण सिंह दलालः चेयरमैन साहब, आप मेरी बात सुनने की कृपा करे। (शोर)

श्री राजेन्द्र सिंह बिसलाः चेयरमैन साहब, मेरा प्यायंट औफ आर्डर है कि दलाल साहब पलवल हल्के मे विधायक है इसलिए इनको पलवल हल्के तक ही सीमित रहना चाहिए, इनको सारे फरीदाबाद जिले का ठेका नहीं लेना चाहिए। वैसे ये मेरे छोटे भाई हैं, उस नाते से मैं इनका सुझाव देना चाहूगा कि जो धमेन्द्र कुमार एक्टर है उनसे इनकी शक्ल मिलती जुलती है इसलिए ये फिल्म इंडस्ट्रीज में चले जाए' और वहां जा कर एक्टिंग करे। (हंसी)

श्री कर्ण सिंह दलालः चौयरमैन साहब, आप मुझे बोलने के जिए एक सिमट का टाईम दे दे ताकि मैं अपनी स्पीच वाईंड–अप कर सकूं। (शोर)

श्री सभापतिः दलाल साहब आप कृपा करके बैठ जाएं। अब श्री बलवंत सिंह मैना बोलैंगे।

श्री कर्ण सिंह दलालः चेयरमैन साहब, अगर अस्प मुझे मस्सेने के लिए समय नहीं दे रहे हैं तो हम एज ए प्रोटैस्ट सदन से चाक आउट करते है।

(इस समय हरियाणा विकास पार्टी के उपस्थित माननीय सदस्य सदन से उठ कर बाहर चले गए।)

वर्ष 1995–96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

चौधरी बलवंत सिंह मायना (हसनगढ़): चेयरमैन साहब, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। माननीय वित्त मंत्री श्री मांगे राम गुप्ता जी ने 13 तारीख को जो बजट पेश किया है, मैं उसके विरोध में बोलते हुए कुछ कहना चाहूंगा। मुझे एक बात याद आ गई। हमारे वित्त मंत्री श्री मांगे राम गुप्ता जी ने माननीय सदस्य श्री राम कुमार कटवाल की बुआ के पास बैल कर यह बजट तैयार किया है इसलिए इन्होंने सिन्दूर, मंगलसूत्र और चूड़ियों पर टैक्स माफ कर दिया। इन्होंने यह नहीं सोचा कि हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है, इसलिए हरियाणा प्रदेश के किसानों को टैक्स में राहत दी जाए। हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश होते हुए भी इन्होंने किसानों को पानी देने के लिए पैसे का पूरा प्रावधान नहीं किया। जैसे एस० वाई० एल० नहर की बात करते हैं। आज हमें एस० वाई० एल० नहर के बारे में चर्चा करते हुए पौने चार साल हो चुके

हैं और उसकी हर बजट सैशन में बात उठती है तो सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है कि उसको 6 महीने के अन्दर पूरा किया जाएगा। इस बजट में इस सरकार ने एस० वाई० एल० नहर के लिए 16.66 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस पैसे के बारे में मैं यह कहता हूं कि यह तो ऊंट के मुंह में जीरा डालने वाली बात है, इतने पैसे से एस० वाई० एल० नहर बनने वाली नहीं है। भाखड़ा नहर की सफाई के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्य मंत्री थे, उन्होंने इसकी पटरी बनाने के लिए और गाद निकालने के लिए 1 करोड़ 90 लाख रुपये रखे थे। इस सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया जिस वजह से ये वहां से अपना पूरा पानी इस भाखड़ा नहर में नहीं ला सके। हरियाणा प्रदेश के अन्दर रोहतक जिला है, डब्ल्यू० जे० सी० का पाना उसमें आता है। इस डब्ल्यू० जे ० सी ० की हालत बहुत ही खराब है क्योंकि उसमें बहुत अधिक गाद भरी हुई है। गाद भरे हत्थे के कारण उसमें पूरा पानी कमी भी नही आ पाता। अब मेरी प्रार्थना है कि वर्ल्ड बैक से जो पैसा आया है, उससे इसकी सफाई कराई जाये। हमारे वहां पर जे ० एल० एन० और र्जे एस0 वी० साथ साथ चलती है। उनमें भी रेती और गाद भरी हुई है। इसी प्रकार से वहां पर चाहे दुरेहड़ा, सुसाना या भालोट माईनर हैं, सब में रेती भरी हुई है। इन की टेलों पर कभी भी पानी नहीं जाता। हर सैशन में मैं इसकी आवाज उठाता हूं और हर बार सवाल करता हूं, क्वैश्चन लगता है, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि हसनगढ के जोहड़ में पानी डालने के लिए भी पानी नहीं मिला, आबपाशी की तो बात ही छोड़िए। इसी प्रकार से पीने का पानी भी नहीं जाता। कसरेहटी में पीने का पानी कभी नहीं जाता। आज रोहतक में जे ० एस० बी ० और जे ० एल० एन० पैरलल चलती है, वहां पर

इनकी सीपेज की वजह से 20 हजार एकड़ रकबा खराब हो चुका है और किसान बर्बाद हो चुके हैं। कारण यह है कि झझर सब–ब्रांच में मिट्टी भरी हुई है। मोरियां जो बनी हुई हैं, वे पहले की हैं और रेत से वे दब चुकी हैं जिसके कारण पानी की कैपेसिटी कम हो गई है मैं कह रहा था कि वहां पर सीपेज की वजह से किसानों की 20 हजार एकड़ का रकबा खराब हो चुका है, उसकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही। नेहरा साहब जब ग्रिवेंसिज कमेटी की मीटिंग में जाते हैं तो उस समय भी यह मामला उनके साथ उठाया जाता है। डिच ड्रेन बनाने की बात कई बार आई लेकिन नही बनाई जा रही। नेहरा साहब अपने हल्के में पूरे जोर शोर से डिच ड्रेन बना रहे हैं लेकिन रोड्तक जिले की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इससे साफ पता चलता है कि सरकार रोहतक जिले के साथ भेदभाव कर रही है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वर्ल्ड बैक से जो पैसा आया है, उससे सभी हरियाणा की नहरों की, माइनरों की और नालों की गाद निकाली जाये ताकि हरियाणा की चप्पा–चप्पा जमीन को पानी मिल सके। हरियाणा सरकार ने अपने बजट में से तो इस काम के लिए कोई पैसा नहीं रखा। लेकिन वर्ल्ड बैक से जो पैसा इस काम के लिए आया है, मेरा अनुरोध है कि जिन किसानों का 20 हजार एकड़ का रकबा सीपेज की वजह से खराब हो चुका है और किसान अपना रकबा बोने से महरुम हो जाते हैं, सरकार उसका एक सर्वे करवाये और जितने भी गांव इस सीपेज के अन्दर आते हैं, उनकी फसल का मुआवजा सरकार दे। चेयरमैन साहब, ओलावृष्टि से किसानों की जो फसल बरबाद होती है, वह कुछ परसैट ही होती है, लेकिन इन बेचारे किसानों की तो पूरी फसल बोर्ड ही नहीं जाती। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इन बेचारे किसानों की क्या गलती है जो सरकार ने आज तक उनकी तरफ कोई

ध्यान नहीं दिया। चौधरी भजन लाल जी तो किसानों के बड़े हितैशी बनते हें। अगर ये उनके हितैशी बनते हैं तो उनके हित की बात की तरफ तो ध्यान दें जो डिच नहर बनाई जानी है, वह बनाई जाए ताकि जो पानी वहां फर खडा है उसको निकलवाने का प्रबन्ध किया जाए। चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहूंगा कि यह पानी कब तक निकलवा देंगे और किसानों को फसल के नुकसान का कितना मुआवजा देंगे और कब तक देंगे? इस बारे में ये हाउस में आश्वासन दें। सिंचाई के बारे में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भालौट माईनर, सिसाना माईनर और दुल्हेडा माईनरज की तरफ भी ध्यान दें।

चेयरमैन सर, अब मैं शिक्षा की बात कहना चाहता हूं। शिक्षा मन्त्री जी ने कहा कि हमने नकल को रोकने के लिए पग उठाए हैं। हम इस बात को मानते हैं कि नकल को कुछ हद तक रोका भी है, लेकिन ग्रामीण शिक्षा की ओर सरकार ध्यान नही दे रही है। गांवों के अन्दर 10 जमा 2 के स्कूल्ज हैं, उनका रिजल्ट बहुत ही पूवर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों के स्कूल फेल हो गए हैं। साम्पला गवर्नमैंट हाई स्कूल के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वहां का एक आध बच्चा पास हुआ हो तो अलग बात है, पूरे के पूरे स्कूल में एक भी विद्यार्थी पास नहीं हुआ। जहां तक मैं समझता हूं इसका एक कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में जो अध्यापक हैं, वे पूरे नहीं हैं कहीं पर साईंस टीचर नही, कहीं पर गणित का टीचर नहीं है और कही पर अंग्रेजी का टीचर नही है। दूसरा इसका जो कारण मैं समझता हूं वह यह है कि गांवों में अच्छे अध्यापकों को भेजा नहीं जाता। इस मामले में गांवों के साथ भेदभाव किया जाता है। गांवों के स्कूलों की हालत बहुत ही बूरी है। मैंने पिछले सैशन में अपने हल्के के अटावल गांव के स्कूल की छत के बारे

में बताया. था कि उसकी छत गिरने वाली है और मुझे यहां पर यह आश्वासन दिया गया था कि बरसात से पहले उसकी मुरम्मत करवा दी जाएगी लेकिन बड़े शर्म की बात है कि इस स्कूल की छत पर अभी तक किसी ने गौर तक नही किया है। उस छत के नीचे न तो कोई बच्चा और न ही कोई अध्यापक बैठ सकता है (घण्टी) चेयरमैन साहब, अगर इस प्रकार की हालत गांवों के स्कूलों में होगी तो बच्चों को सही शिक्षा नही मिल पाएगी। इसी तरह से कलावड गांव मेरे हल्के में पड़ता है। इस गांव में दस जमा दो का लड़कियों का स्कूल है। इस स्कूल के पीछे एक जौहड़ है जिसका पानी बरसात होने के कारण स्कूल की दीवारों तक आ गया है। सीलन होने के कारण उसकी छत गिरने तक की नौबत आ गई है। इस बारे में किसी ने कोई सुनवाई नहीं की, तालाब का पानी बाउंडरी–वाल तक लग रहा है। लोगों की यह मांग है कि इस पानी को सरकार निकलवाए। गांव वाले मुझ से कहते हैं कि अगर सरकार पानी निकलवा देगी तो ठीक बात है, बड़ी मुश्किल से स्कूल की बिल्डिग बनी है, अगर पानी नहीं निकला तो वह गिर सकती है। गांव वालो का यह भी कहना है कि अगर पानी निकलवा दिया जाए तो वे जौहड़ को अपने खर्चे पर अपने तरीके से खुदवा लेंगे और दीवार के साथ पुश्त करवा देंगे ताकि यह समस्या खत्म हो सके। इसके साथ ही गांव की कुरडियों का पानी गांव के अन्दर फैला हुआ है, जिसके कारण बदबू उठती है और बच्चों को कर्य बीमारियां हो रही हैं। इस बारे में ये बताए कि इस पानी को कब तक निकलवा देंगे? नकल रोकने में कुछ काम हुआ है और हम इमको मानते भी हैं। शिक्षा के अन्दर नकल रोकने की आज बात हो रही है और नकल रोकने वाले। को ईनाम दिये जा रहे है। पहले मिनिस्टर साहिबान तो चाहती थी कि नकल बन्द हो जाए। लेकिन

दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे नकल को रोकने के लिए शीला बहन का उनके घर में ही मर्डर कर दिया जाता है और मर्डर करने के बाद उसको नहर में फैक दिया जाता है।

सभापति महोदय, 1966 से शहरों के अन्दर अध्यापकों को मकान भला मिलता था। आज इस सरकार ने वह भी बन्द कर दिया है बल्कि यहां तक कर दिया कि जो चिट्ठी उनको लिखी गई है, उसमें यह लिखा है कि जो पिछले चार साल भत्ता लिया है, वह भी वापिस दिया जाए। सभापति महोदय, मकान मालिक तो किराया ले गया है, अब अगर वह अध्यापक अपनी तनख्वाह से वह पैसे भी देगा तो वह गरीब अध्यापक क्या करेगा? इसलिए सरकार को इस फैसले को भी वापिस लेना चाहिए।

इसी तरह से सांपला गांव है। वहां पर पी ० एच० सी ० है और डाक्टर वहीं पर नही रहता है क्योंकि रोहतक वहां सै 26 किलोमीटर पड़ता है। अगर किसी को चोट भी लग जाए तो वहां पर पट्टी करने का सामान तक नही मिलता है, सिर दर्द हो तो गोली भी नही मिलती है। इसी तरह से बलियाना में भी कोई नही होता। मेरे कहने का मतलब है जहां पर पी ० एच० सी ० और सी० एच० सी० हे, वहां दवाईयां मिलनी चाहिए। वैसे इस सरकार का दिल नहीं है कि वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था की जाए। (इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

अध्यक्ष महोदय, अब मै सड़को के बारे में कहना चाहूंगा.। सड़को की बहुत ही बुरी हालत है। मैं अपने हल्के की बात कहुगा। सापला से लेकर डीगल तक, सांपला से लेकर अटायल, सीमली से कालहोरा और मसूड से मोरखेड़ा तक चारों तरफ सड़कें टूटी पड़ी है। उन पर कोई भी आ–जा नही सकता है। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि हमने सब सड़कों की मरम्मत कर

दी है और इस बारे में अमर सिंह जी ने भी दावा किया है। अध्यक्ष महोदय, मैने पिछले सैशन में हसनगढ़ से लेकर खेरनपुर तक सड़क बनाने के लिए कहा था और बालंद से करोंथा तक भी कहा था, लेकिन आज इनको चार साल हो गए हैं, वहां पर एक टोकरी मिट्टी भी किसी ने नहीं डाली है और वहां पर कुछ काम ही नही हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं बसों के बारे में कहता हूं। इन्होंने 363 नई बसें खरीदीं और उस पर 25 प्रतिशत ज्यादा किराया लगा दिया। यह सब सरकार के लिए पैसा कमाने का तरीका है। उन बसिज में न कोई पुलिस का कर्मचारी, न पास वाले बैठ सकते हैं और न ही आम आदमी बैठ सकता है। सरकार को उन बसिज में कर्मचारियों को, पुलिस के कर्मचारियों को और पास वालों को अलाऊ करें। इस बारे में सरकार को चाहिए कि उन बसिज में भी आम आदमियों को बैठने की सुविधा मिल सके।

13.00 बजे

इसी प्रकार से वाटर वर्क्स के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा। सर, मैंने भी कहा था कि वाटर वर्क्स की बहुत बुरी हालत है। हसनगढ गांव में पीने का पानी नहीं जाता। इसी तरह से किसरैदी, नयाबास, अटायल, खेड़ी सांपला, खरावड, रटौली और करौथा गांवों में भी पीने का पानी नही जाता है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जहां भी ट्यूबवैल का प्रावधान हो तो वहां पर सरकार को जरूर इसका प्रावधान करना चाहिए, ताकि लोगों को उन गांवों मे पीने का पानी मिल जाए। स्पीकर सर, इसके अलावा मैं बिजली के बारे में भी कहना चाहूंगा क्योंकि माननीय बिजली मंत्री यहां पर बैठे हुए है। आज इन्होंने बिजली के रेट तो बढ़ा दिए। कमी तो ये बिजली के रेट दो रुपये से दस रुपये और कभी दुकानदार के दो रुपये से चालीस रुपये और

कभी 65 रु० प्रति हार्स पावर मोटर के हिसाब से बढ़ा देते हैं, लेकिन फिर भी बिजली समय के मुताबिक लोगो को नही मिलती है। जब लोग सो जाते हैं तब जाकर बिजली आती है जिसके कारण पढने वाले बच्चों की फ्लाई नहीं हो पाती और जब लोग सुबह सोकर उठते हैं तो उससे पहले ही बिजली गायब हो जाती है। मैं मत्री जी से एक बात जानना चाहूंगा कि मेरे हल्के के सिमप्ली गांव में एक बहुत पुराना ट्रांसफार्मर है। उस गांव की आबादी आज चौगुनी बढ़ चुकी है लेकिन फिर भी आज तक वहां दूसरा ट्रांसफार्मर नही लगाया गया। इसी तरह से रटौली गांव के रणधीर सिंह को अपना ट्यूबबैल लगाने के लिए कनैक्शन की जरूरत थी लेकिन चार साल से उसको बिजली का कनैक्शन नही मिल पाया। कनैक्शन लेने के लिए उसके ट्यूबवैल का फासला केवल पांच फुट का है। लेकिन उसको इन्होंने कनैक्शन नही दिया है तो स्पीकर सर, यह तो स्थिति बिजली के बारे में है। मैं इनको एक बात बताना चाहूंगा वैसे तो यह मजाक की बात है। एक डाक्टर ऐसा था कि उसको आता जाता कुछ नहीं था। एक बार कोई आदमी डाक्टर के पास गया और उससे कहने लगा कि मेरे पेट में दर्द है तो वह डाक्टर उससे कहने लगा कि तू कपड़े उतारकर कमरे में अन्दर जाकर बैठ जा। जब दूसरा आदमी उसके पास आया और उसने उस डाक्टर से कहा कि मेरे सिर में दर्द है तो उसने उस आदमी से भी कहा कि तू भी अपने कपड़े उतारकर कमरे में अंदर जाकर बैठ जा। इसी तरह से जब तीसरा आदमी उस डाक्टर के पास आकर कहने लगा कि मेरे माथे में दर्द है तो उसने उस आदमी से भी यही कहा। जब वे तीनों अंदर जाकर बैठ गए तो वे कहने लगे कि यह कैसा डाक्टर है जो सभी को एक ही तरह से कहता है। जब उन तीनों ने देखा कि वहां पर पहले से ही एक और आदमी टेबल के नीचे बैठा हुआ है तो

उन्होंने उससे पूछा कि तू यहां क्यों बैठा है तो वह कहने लगा कि मैं तो बिजली का बिल जमा करने आया था लेकिन इस डाक्टर ने मुझसे कहा कि तू अपने कपड़े उतारकर अंदर कमरे में जाकर बैठ जा। तो स्पीकर सर, यही हाल इस सरकार का है, यह लोगों से झूठे वायदे करती है। (विघ्न) सर, मैं इस पूरे बजट का विरोध करता हूं। यह सारा बजट किसान विरोधी है तथा हरियाणा की जनता के विरुद्ध है। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हुआ आपका धन्यवाद करता हूं।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो बजट का जबाव बिल मती जी ने देना है लेकिन कुछ प्यायंट ऐसे हैं जिनके बारे में क्लैरिफाई करना जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए कुछ सदस्यों ने कुछ प्यायंट रेज किए हैं उनके बारे में मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं ओम प्रकाश चौटाला जी के दारा उठाए गए प्यायंट के बारे में कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि देश की गलत नीतियों की वजह से, गलत पोलिसीज की वजह से साउथ में काग्रेस हार गयी है। वे आज इस सत में नहीं है जबकि उनको आज होना चाहिए था, लेकिन किसी काम से शायद चले गए होंगे। लेकिन उनकी पार्टी के अपोजीशन के लडिर्ज यहां बैठे हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा कि जब चौधरी देवी लाल हार गए थे तो उस समय ऐसी कौन सी पोलिसी या नीति थी वह कैसे हार गए। अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते है कि प्रजातंत्र में हार जीत तो लगी ही रहता है लेकिन जहां तक देश की नीतियों का ताल्लुक है, पिछले चार साल मे इस देश का नाम संसार में ऊचा ही हुआ है, चाहे वह विदेश नीति हो, चाहे वह उद्योग नीति हो चाहे वह किसानों के लिए अच्छा भाव देने की बात हो चाहे खाद पर सबसिडी देने की बात हो, हर लिहाज से इस देश का नाम

प्रधानमंत्री की रहनुमाई में ऊचा हुआ है। इस वारे में जितना बार भी बधाई दें उतनी थोड़ी है। आप बाहर जाकर देखें। बाहर की कंट्रीज के लोग हिंदुस्तान की बहुत तारीफ करते हैं, कितनी शानदार इकोनोमी ठीक हुई है। अगर हमारे मुल्क की इकोनोमी ठीक नही होती तो बाहर के देशो में हमारे देश की कदर कम हो जाती। रशिया जैसा मुल्क, बहादुर मुल्क टूट गया, 15 टुकड़े हो गए। अगर समय पर देश की इकोनोमी ठीक न होती तो हिंदुस्तान की भी रशिया से बुरी हालत हो सकती थी। तारीफ करने की बजाय ओम प्रकाश चौटाला जी ने गलत नीतियों की वजह से क्रीटीसाइज किया हैं। स्टेट के मामले में, स्टेट सब्जैक्ट्स के आधार पर जनता वोट देती है। अगर हमारा काम ठीक नहीं होगा तो लोग हमें वोट नहीं देंगे। साल–सवा साल के बाद चुनाव होंगे अगर हमारा काम ठीक नहीं होगा तो जनता हमारे खिलाफ जनमत देगी, काम ठीक होगा तो लोग हमें चुनेंगे। लेकिन इनका राज भी जनता खूब देख चुकी है, चौधरी वैसी लाल का राज भी देख रखा है, जनता जानती है कि किसका शासन ठीक है। जनता ने फैसला करना है। इस्तीफे की बात कहते हैं क्या किसी के कहने से इस्तीफा होता है? यह सरकार बजट का 71 परसैटं देहात पर खर्च करने जा रही है जिसमें किसान, हरिजन, मजदूर, बैकवर्ड, नौजवान, महिलाओं सबको इसमें कवर किया है ताकि इस बजट का ज्यादातर भाग लोगों की भलाई के लिए खर्च किया जाए। अध्यक्ष महोदय, कह दिया इतना कर्जा हो गया सरकार के ऊपर। हम आएगे तो हमें देना पड़ेगा कर्ज तुम दोगे, तुम झूठे वायदे तो कर सकते हो कि लोगों के कर्जे माफ कर देंगे। लोगों का सत्यानाश करके रख दिया। ब्याज की रकम हमको माफ करनी पड़ी यह प्रदेश के लोग जानते हैं लेकिन लोगो को गुमराह करने के कोई मायने नहीं हैं। इसी तरह चौधरी बंसी लाल

ने कुछ मुद्दे रेज किए। एक तो कहा कि शाहबाद से किसान गन्ना पंजाब में ले जा रहे हैं और यहां के लोग रोकते हैं। 90 रुपये में पंजाब के मिल वाले गन्ना लेते हैं इस बात में कोई सच्चाई नहीं है और सच्चाई इसलिए नहीं है कि यू० पी ० से गन्ना हरियाणा प्रदेश में आता है। जितना अच्छा भाव गन्ने का पिछले तीन साल मे हरियाणा ने दिया है किसी भी राज्य ने इतना बढ़िया भाव नही दिया। (थम्पिंग) गन्ना बाहर ले जाने पर कोई बैन नही है कोई पाबन्दी नहीं है अच्छा भाव मिले तो गन्ना, गेहूं, जीरा सारे हिन्दुस्तान में कही भी जा सकती है कोई बैन की बात नही है बाहर से भी आ सकता है यहां से भी जा सकता है जहां अच्छा भाव 'किसान को' मिले वह ले जा सकता है। इसी तरह से चौधरी बंसी लाल ने शीरे के बारे में कहा कि मोलेसिस का भाव बहुत कम है। ऐसा लगता है कि इनको अपने जमाने का भाव याद रह गया। अब जो हमने तय किया शै 45 रुपये, 29 रुपये, ए,बी, सी क्लास–1, क्लास–2, क्लास–3 हमने अलग–अलग रेट तय किए हुए हैं। पहले 1992 में भाव बढ़ाया और फिर 1994 में भाव बढ़ाया ताकि भाव बढ़ने से किसानो को अच्छा दाम मिल वाले दे सकें और दूसरे, इन्होने कह दिया कि शीरा 180 रुपये के भाव में लेते है, उसका भीं हमने 200 रुपये भाव कर दिया है। उसमें से जो मिलों को लगता है, डिस्टीलरीज को देते हैं, जो रेट जब तय करते हैं, जिस भाव में शीरा देते है, उसका हिसाब लगाकर बाद में प्रूफ लीटर के पीछे क्या रेट होना चाहिए वह तय करते हैं। सारे भाव लगाकर के उसी के हिसाब से आगे ठेके नीलाम होते हैं। जब ठेके नीलाम हो जाएं तो बीच में बढ़ा नहीं सकते और आज हरियाणा प्रदेश में किसी भी मिल की तरफ किसी भी किसान का पैसा बकाया नही है। 15 दिनों के अन्दर–अन्दर पेमैंट करने का हमारा कायदा है। भूना मिल की एक शिकायत इस बारे में

–आई थी और फौरन ही दूसरी जगह के बैक से पैसा भिजवा दिया गया ताकि किसानों को ठीक समय पर पेमैंट हो जाए।

इसके माथ–साथ अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस वक्त हरियाणा के अन्दर 10 कोआपरेटिव मिलें हैं और एक प्राईवेट है, वे सभी ठीक तरह से चल रही हैं, वहा कहीं पर भी कोई पेमैंट की दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना सोचे समझे यह कह देना कि इससे ज्यादा रेट गन्ने के मिल सकते हैं, मिल वाले चुक्वा लेंगे। स्पीकर साहब, हम भली भांति जानते हैं कि किसान को कितना पैसा मिलना चाहिये और सारे देश में हमने पहल करके, हरियाणा ने अच्छे भाव देकर के सारे देश को एक रास्ता दिखाया है और सोइंग होने से पहले पांच रुपये का रेट हमने बढ़ा दिया ताकि किसान का गन्ना ज्यादा आए और किसान इसी कारण से भाव को देखकर ज्यादा उल्ला बोए।

दूसरी बात इन्होंने शीरे के बारे मे भी कही कि किसी एक फैक्टरी को ज्यादा फायदा होता होगा। साथ में इन्होंने आडीटर जनरल की रिपोर्ट का भी जिकर कर दिया। मैं इनको बताना चाहता हूं कि पहले इसके लिये पुराने नार्मज बने हुए थे। उन नार्मज को लगभग सभी प्रदेशों ने रिवाईज कर दिया और रिवाईज भी ऐसे नही किया। उन्होंने बाकायदा कमेटियां बना करके और नार्मज फिक्स करके कि किस प्रदेश में सीरे में से कटैन्ट्स के मुताबिक कितनी सप्रिट बन सकती है। अब सब कुछ मार्डेनाइज हो गया कुछ नई मिलें भी लग गयी। आज में और भले में बड़ा अन्तर है। मैं अब यह कहना चाहता हू कि पंजाब में जो नार्मज थे, उनके अनुसार वहां पर 30.5, 30.6, 30. 25 की सप्रिट की ऐवरेज निकली है और इन्होंने यहा पर पानीपत व हिसार की डिसटिलरी के बारे में भी कह दिया। मैं इनको बताना

चाहता हूं कि 1991–92 मे पानीपत में जो डिसटिलरी है वहां 30.04 और हिसार में जो असोसीऐट डिमटिलरी है उसकी फिगर सी रें की है, 31.77 इसी तरह से 1992–93 में पानीपत की 30.26 और हिसार की 32.24 ओर 1993–94 में पानीपत की 26. 14 और हिसार की 29.50 है यह रिकार्ड की बात बता रहा हूं। यू ही फिजुल की गल्तव्यानी करना यह कोई मुनासिब नही है। ये जो फिगर्ज मैं दे रहा हू, कहो तो इसकी एक कापी. आप लोगों को भी दे दू, कहीं जा कर मिला लेना।

इसी तरह से चौधरी बंसी लाल जी ने फरीदाबाद, आनन्दपुर, बड़खल और पाली क्षेत्रों में माइनर्ज की बात भी कह दी। साथ में यह कह दिया कि सारे की परसैन्टेज दूसरी स्टेटो में जैसाकि यू ० पी ० है कहीं नही ले रहे है। मैं इनको बता देता हु कि पजाब में 65 परसैन्ट और हरियाणा में 50 परसैन्ट है। 65 परसैन्ट सैन्टर गवर्नमैंट लेती है और हम 50 परसैन्ट लेते हैं। यह भी रिकार्ड की बात है।

दूसरे अध्यक्ष महोदय, जब चौधरी बंसी लाल जी मुख्य मन्त्री थे, उस वक्त का बताता हू। वैसे जो उन्होंने कहा, वह ठीक है कि सारे एच० एम० एल० को चलना चाहिये। एच० एम० एल० के लिये उन्होंने इस तरह का फैसला किया था और उसके बाद में लोग कोर्ट में चले गये और उसके बाद राज्य सरकार को 10– 12–86 को फिर लीज वापिस करनी पड़ी क्योकि कोर्ट ने यह कह दिया था कि आप उसको कैंसिल नही कर सकते। मैं यह रिकार्ड की बात कह रहा हू। दिल्ली हाई कोर्ट में इसके लिये अपील की गई और उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 4– 12–86 में, जबकि चौधरी बंसी लाल जी मुख्य मंत्री जी थे, माइनिंग लीजों को समाप्त करने के आदेशों को अवैध घोषित किया और 10– 12–86 को राज्य सरकार, उच्च

न्यायालय के आदेशों पर रोक लगाने की अपील को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। तदनुसार लीजियो को खानो के कब्जे दिनांक 18– 12–86 को वापिस किये गये। भारत सरकार ने जनवरी 1994 को माइनज एण्ड मिनरलज रेगुलेशन एक्ट और डिवैल्पमैंट एक्ट 1987 में संशोधन करके उन खनिजों को जो पहले सरकारी उपक्रमी को दी जाती थी अब निजी क्षेत्र में देने के लिये छूट दे दी। भारत सरकार ने यह भी कह दिया कि चाहे निजी क्षेत्र हो, चाहे सरकारी क्षेत्र हो, सब को एक बराबर का दर्जा दिया जाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस लीज से कितना फायदा हुआ है। वर्ष 1986 में खनिजों से 5 करोड़ 12 लाख रुपए की आय थी तथा 1991–92 में 9 करोड़ 93 लाख रुपए की आय थी 1 यह बाद में बढ़ कर 1993–94 में 18 करोड़ 27 लाख रुपए हो गई और 1994–98 में 22 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। तो कहां तो पांच करोड़ और कहां 22 करोड़। यह रिकार्ड की बात है। अध्यक्ष महोदय, एक इन्होंने लिबर्टी सीड कापी– रेशन का जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय, यह ठीक बात है कि उनके सीड की शिकायत आई। हमने बाकायदा 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया और तीन को गिरफतार किया। 1580 एकड़ जमीन में यह सीड बीजा गया था और 238 किसान इससे प्रभावित हुए थे। जो हमें आकड़े उपलब्ध करवाए गए हैं, उनके मुताबिक सीड में नुक्स था। अरली वैरायटी और लेट वैरायटी का सीड मिक्स हो गया था। उसकी वजह से एक वैरायटी पहले पक गई और दूसरी पकी नहीं, किसान को कच्ची काटनी पड़ी। उसके लिए बाकायदा डी ० सी ० की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया और तीन आदमी गिरफ्तार किए गए। कमेटी ने किसानों को कहा कि आप हमारे पास बैठ कर बात करे। किसानों के

नुमायदों ने बैठ कर बात की। उन्होंने कहा कि हमें तीन हजार एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। अन्दाजे के मुताबिक उनका नुकसान एक हजार रुपए एकड़ के हिसाब से हुआ है। हमने कहा नहीं किसान को ज्यादा मुआवजा दिया जाए। डी ० सी ० और किसानों की आपस में बात चल रही है। हम चाहते हैं कि किसानों को पूरा मुआवजा मिले और बल्कि ब्याज समेत मिले। अगर किसान का एक हजार रुपए एकड़ का नुकसान हुआ है तो हम उसे दो हजार रुपए देंगे और अगर दो हजार का हुआ है तो चार हजार रुपए देंगे और जिन्होंने गल्त बीज बेचा है उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। आपने कह दिया कि हमने उनका लाइसैस क्यों नहीं कैंसिल किया। हमने उनका लाइसैस कैंसिल कर दिया है और उनको आगे लाइसैस देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने चार नदियो का जिक्र किया। ये राजस्थान की नदियां हैं। इनके बारे में हम अब क्या कह सकते हैं। एक तो ये हमारे सामने बैठे हैं, जिन्होंने मसानी बैराज शुरु करवाया था। उसके बाद बंसी लाल जी का राज आ गया। उन्होंने तो इसको स्टार्ट किया था और बंसी लाल जी ने उसको रोका नहीं और वह आगे बनता चला गया। ठीक है उसकी जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी कि साहबी और कृ ष्णावती नदियों का पानी राजस्थान से आता था और दोहन नदी का पानी तो पूरे एरिया में फैलता था। उससे कोई नुकसान का सवाल नहीं था। बल्कि पानी के साथ नई मिट्टी आती थी। जहां कहीं पानी का बहाव आता है तो फसलें टेढ़ी हो जाती हैं लेकिन कहीं भी कोई नुकसान की बात नहीं हुई। एक बार इत्तफाक से पानी ज्यादा आ गया था और वह दिल्ली की तरफ चला गया। उस समय दिल्ली की सरकार में भी चौधरी देवी लाल सर्वो सर्वा थे और इधर भी उनका राज था। लेकिन मैं इतनी बात कह सकता हूं कि

उस बैराज को बनाने सै बहुत भारी नुकसान हुआ है। यह बात ठीक है कि राजस्थान ने भी छोटे छोटे बांध बनाए है, हमें पता लगा है। हमने उसके बारे में बात की। राम बिलास शर्मा जी ने भी कहा कि वह भी मेरे साथ राजस्था न जाने के लिए तैयार हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि कहोने हमारे साथ चलने के लिए कहा क्योकि यह हरियाणा प्रदेश के हितों का सवाल है। राजस्थान के सी ० एम० श्री शेखावत ने यह कहा था कि चौधरी भजन लाल जी आप आए हम चल कर उस जगह को देखेंगे। अगर उन बांधों से हरियाणा प्रदेश को नुक्सान होता है तो वह नहीं होने देंगे।

श्री अध्यक्षः मसानी बैराज पर किवाड़ लगे है या नहीं लगे है।

चौधरी भजन लालः जी नहीं, अभी तक किवाड़ नहीं लगे हैं।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट औफ आर्डर है। आपने यह वात सही पूछी शै कि उसके किवाड़ लगे हैं या नही लगे है। स्पीकर साहब, वहां पर किवाड़ नही लगे है। अभी तक वहां पर रैगुलेटर नहीं लगे हैं। जब तक उस बांध पर रैगुलेटर नहीं लगेंगे तो राजस्थान से जो पानी आएगा उसमें कावट कैसे होगी। स्पीकर साहब, पानी आने में जो रुकावट है वह राजस्थान बालों ने जो बांध बाध रखे हैं उनसे है हरियाणा वालों ने जो बांध बांध रखे हैं उनसे कोई रुकावट नहीं है। जिस समय हरियाणा के अन्दर बहुत भयंकर फ्लड आया था उस समय वह डैम बनाने की अरजैसी थी इसलिए वह बांध बना था। हम बार–वार यह कह चुके है कि वह डैम वाजिब नही है और ये भी कह चुके है कि वह बांध वाजिब नही है लेकिन ये यह बात नहीं कह रहे कि राजस्थान वाले उन बाधों को कब तक हटाएंगे?

प्रो० राम बिलाश शर्माः स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री जी ने यह बात ठीक कही है कि साहिबी नदी पर जो बाध है उससे कोई फायदा नही है। वह बनाने से 40 करोड़ रुपए का नुक्सान हुआ है। जिस समय यह बांध बनाया गया उस समय सम्पत सिंह जी की पार्टी की सरकार थी। उस मामले के बारे में हमारे मुख्य मती जी की और राजस्थान के मुख्य मंत्री जी की वार्ता हो रही है लेकिन यह सरकार जो काम शुरु करती है वह पूरा नही हो सकता लेकिन हमारी पार्टी की सरकार जो काम शुरु करती है वह पूरा होता है। हमारी पार्टी की सरकार ने तो अयोध्या में मन्दिर बना दिया था आप साहिबी बांध का काम पूरा नही कर सकते?

चौधरी भजन लालः राम बिलास जी आप मेरे छोटे भाई है। आपने वह काम करके अयोध्या का भट्ठा बिठा दिया। उस समय वहां पर कितनी जाने चली गई इस प्वायंट को मैं टच नही करना चाहता। (शोर)

प्रो० राम बिलास शर्माः रघुकूल रीत सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई। अयोध्या में मंदिर बनने पर ही गुजरात में हमारी पार्टी की सरकार बनी। (शोर)

चौधरी भजन लालः उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी और हिमाचल प्रदेश में भी आपकी पार्टी की सरकार बन गई। आपका क्या मुकाबला है। (शोर)

प्रो० राम बिलास शर्माः आपने नैशनल इन्टेग्रेशन कमेटी की मीटिंग में हमारी पार्टी की सरकार बनने पर बधाई दी थी।

चौधरी भजन लालः आप मंगलसूत्र, चूड़ियों और सिन्दूर की बात कर रहे थे। मैं इस प्वायंट को कहना नहीं चाहता था। बी ० जे ० पी ० के आधे से ज्यादा लीडर कंवारे हैं इसलिए इनको क्या पता सिन्दूर कैसा होता

है, मंगलसूत्र कैसा होता है और चूड़िया कैसी होती हैं। मैं गिरजाघर, गुरुद्वारे और मंदिरों में कोई फर्क नहीं समझता। यह सब भगवान की पूजा के स्थल हैं। राम बिलास जी राम की ठेकेदारी केवल आपकी नहीं है, सब की है। अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी ने नहरों की सफाई के बारे में बात कही। नहरों की सफाई करने के बारे में जितने भी माननीय सदस्यों ने सवाल पूछे, उनके तफसील से जवाब दिए गए। जहां तक फ्रीडम फाइटर्ज का सवाल है कि उनका मान और सम्मान होना चाहिए, यह बात ठीक है कि उनका मान और सम्मान होना चाहिए क्योंकि फ्रीडम फाइटर्ज की मेहरबानी से आज हम यहां पर बैठे हुए हैं। उन्हेंने हमारे देश को आजाद करवाया इसलिए हमारा धर्म बनता है कि उनका मान और सम्मान होना चाहिए। हरियाणा सरकार ने फ्रीडम फाइटर्ज को पूरी सुख और सुविधा दी है। जितनी सुविधाएं एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर्ज को आज की सरकार ने हरियाणा प्रदेश में दी हुई हैं, उतनी सुविधाएं किसी भी प्रदेश में नही हैं। जहां तक रिजर्वेशन के कोटे की बात है। हमारे यहां 50 परसैट रिजर्वड कोटा है। हम 50 परसैंट से ज्यादा उसको बढ़ा नहीं सकते, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। बंसी लाल जी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि. ये वकील हैं इसमें 20 परसैट हरिजन, 17 परसेंट एक्स सर्विसमैन, 10 परसैंट बैकवर्ड और 3 परसैंट फिजिकली हैन्डीकैप्ड लोगों को यह रिजर्वेशन दी गई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि रिजर्वेशन 50 परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्षः अदर बीसीज को कहां खपाओगे?

चौधरी भजन लालः इसके लिए एक कमीशन बनाया गया था, उसकी रिपोर्ट आ गई है, उसको एग्जामिन किया जा रहा है। अदर दैन

बीसीज के बारे मे पूरी तरह से सोचना पड़ेगा। जल्दी में हम एक कम्युनिटी को शामिल कर लें कोई दूसरी रह जाये, दिक्कत आ सकती है इसलिए सारा मामला कैबिनेट में जायेगा और जो भी कैबिनैट में फैसला हागा वह यहां पर हम बताएंगे।

अध्यक्ष महोदय, यहां एक बात कर्मचारियों के बारे में कह दी। कर्मचारियों का कमीशन हमने बैठाया है। इसके अलावा पहले भी जब मैं मुख्यमन्त्री था तो जितनी सुविधाएं हम दे सकते थे दी हैं, इतनी सुविधाएं पहले किसी सरकार ने नहीं दी। बसो लाल जो को कर्मचारी अब भी याद करते हैं कि कैसे दिल्ली में उनके साथ किया गया था, उनके जख्म अब भी हरे हैं, जब जून 87 में चुनाव हुए तो बंसी लाल जी का खुद का पता नहीं लगा कि ये कौन सी हवा में उड़ गए। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे कर्मचारी और अधिकारी बहुत काबिल है दूसरे प्रदेशों में जाओ तो पता चलेगा कि कैसा राज उनका है और कैसा हमारा है। क्या उन कर्मचारियों का रोल है और किस ढंग से वे काम कर रहे हैं, यदि उनका मुकाबला हमारे कर्मचारियों के साथ करेंगे तो हमें बड़ा फख होगा कि हमारे मुलाजिमों का रोल सबसे अच्छा पायेगा। यहां पर एक बात कह दी कि शराब के ठेके पर लाठी चार्ज कर दी। वहां एक नेता था। मेरे को जहां तक पता है श्री जगननाथ जी और मनीराम जी थे। दोनों रोज रात को एक–एक बोतल पी जाते थे प्रौ० उस दिन भी पी रखी थी। वे पहले हमारे साथी रहे हैं। बंसी लाल जी जान सकते हैं कि शराब पी गई थी या नहीं, क्योंकि ये खुद शराब तो नहीं पीते, बीड़ी नहीं पीते, हां लोगों का खून जरुर पीते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक बात कह दी कि एस०एस०एस० बोर्ड के सदस्यों ने इन्टरव्यू देने वाले कैन्डीडेट्स से सवाल पूछे कि तूने ये

कमीज कहां से सिलवाई, सलवार कहां से सिलवाई। ऐसी बात इन्टरव्यू पर बोर्ड या कमीशन को पूछनी नहीं चाहिए। मजाक में कोई बात हो जाए तो अलग एं। अध्यक्ष महोदय, धीरपाल सिँह जो ने झज्जर और एस०वाई०एल० के बारे में कहा। एस०वाई०एल० के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, उन सभी बातों को बार–बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। राम विलास शर्मा जी ने यहां पर एक बात कह दी। (विघ्न)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 15 मिनट बढ़ा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है।

श्री अध्यक्षः हाउस का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1995– 96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि प्रस्ताव करने में क्या दर्ज था। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा प्रस्ताव हमने पहले ही अपने राज में किया हुआ है और इसी सदन में किया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं वह बात कहना नहीं चाहता था लेकिन बार–बार जब ये बात उठाई जाती है तो उसका जवाब तो देना ही पड़ता है। इसी काम्पलैक्स मे, इसी बिल्डिग की दूसरी साईड में पंजाब का सैशन भी चल स्ट्रा है। अगर हमने कोई ऐसा प्रस्ताव पास कर दिया और वे भी ऐसा ही कोई प्रस्ताव ले आएं कि हम यह नहर नही बनने देंगे तो हम क्या कर लेंगे? अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे स्टेट के हितों को नुकसान पहुंचता हो। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि यह बात स्टेट के हित में नही है इसलिए मेहरबानी करके बार–बार इस बात को न उठाए,।

आखिर उनकी भी सरकार होगी, वे लोग भी अपने इन्ट्रस्ट की बात कर सकते हैं। अगर उन्हेंने ऐसा कुछ किया तो फिर हरियाणा प्रदेश का क्या बनेगा? इसी प्रकार से ये लोग हर बात को उलझाने की कोशिश करते है ताकि कोई ऐसी स्थिति पैदा न हो जाए कि हम एस०वाई०एल० बनवाने में कामयाब हो जाएं। ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से बिगाड़ पैदा हो ये किसी मसले को सुलझाना नहीं चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, यमुना जल के बारे मे कितना शानदार समझौता हुआ है। ये लोग 1970 से लगे हुए थे, लेकिन इस बारे में 24– 25 साल में कोई समझौता नहीं करवा सकें और अब जब कि हमने समझौता करवा दिया है तो इनको तकलीफ हो रही है। एम०वाई०एल० का फैसला करके 95 प्रतिशत नहर बनवा दी है तो इनको तकलीफ हो रही है। अध्यक्ष महोदय, चाहे एस०वाई० एल० का मामला हो या यमुना जल समझौते का मामला हो, बहुत ही शानदार फैसला हुआ है और प्रदेश के हित में हुआ है। श्री राम भजन अग्रवाल जी ने बिजली की कमी के बारे में क्या और यह भी कहा कि खम्बे लोहे के हें जो कि गल गए या खराब हो गए और बिजली ठीक नहीं पहुंचती है। इसके साथ ही उन्होने एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है कि डिस्ट्रीव्यूशन और बिजली पैदा करने के महकमे अलग– अलग हो जाए' तो ज्यादा अच्छा है। उनका यह सुझाव विचार करने योग्य है। यह ठीक है कि बिजली कोई पैदा करे और बिजली डिस्ट्राव्यूट कोई करे। इससे यह हिसाब लगाया जा सकता हैं कि मान लो अगर महकमे ने एक लाख यूनिट बिजली दी तो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले महकमे से उसका हिसाब पूछा जा सकता है। यह बात बिल्कुल ठीक है। अध्यक्ष महोदय, लाईन लासिज भी पहले के मुकाबले में काफी कम हुए है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सेल्ज टैक्स की बात है इन्होंने कहा कि सेल्ज

टैक्स सलैब्ज होनी चाहिएं। सेल्स टैक्स के बारे में मैं सारे सदन को बताना चाहूंगा कि सारे नार्दन इण्डिया में या देश को चार हिस्सों में बांट कर ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए कि क्ले टैक्स और मार्कीट टैक्स का रेट एक जैसा होना चाहिए ताकि उसमें टैक्स की चोरी न हो पाए या कोई बेईमानी न कर सके। अध्यक्ष महोदय, इसी बारे में हरियाणा ने सबसे पहले पहल की है और हरियाणा की अगुवाई में और स्टेटो सै मुख्य मन्त्रियों की एक बैठक हमने हरियाणा भवन, नई दिल्ली में बुलाई थी। हमने इस बारे में प्रधान मन्त्री जी से प्रार्थना की और उन्होंने उस मीटिंग में केन्द्रीय वित्त मंत्री को भाग लैने के लिए भेजा। 4– 5 मती भी हमारे साथ थे। उस मीटिंग मे अच्छी डिस्कशन हुई। उसके बाद चीफ सैक्रेटरियो से हमारी मीटिंग हुई। इससे पहले चफि सैक्रेटरियो की भी एक बैठक हुई थी। अब यह मामला काफी नजदीक लगा हुआ है और हम चाहते है कि सारे देश मे सेल्ज टैक्स एक जैसा हो जाए ताकि कही पर भी कोई बेइमानी न कर पाए। माईनोरिटीज के साथ एट्रोसिटाज का कोई सवाल ही नही है। एस०वाई०एल० के बारे में डा० राम प्रकाश जा ने कहा और शिक्षा के बारे मे भी कुछ सुझाव उन्होने दिए और यह भी कहा कि एस०सीज० और बी० सीज० को रोस्टरवाईज रखना चाहिए। यह बात कि है, रोस्टर सिस्टम हमने अपनाया हुआ है। उन्होंने एक बात सूर्य ग्रहण के बारे में कही। इस मेले के लिए जितना भी प्रबन्ध हम कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ब्रह्म सरोवर पर भी काम लगा हुआ है और अगर कोई सड़क वगैरा ठीक नही है तो उसको भी ठीक करवा देंगे। श्री राम बिलास शमी जी ने भी एस०वाई०एल० नहर का जिक्र किया और प्रस्ताव का भी जिक्र किया इस बारे में मैंने अभी बता दिया है। बीज के बारे मे भी मैंने बताया है हत्या तथा बलात्कार की बात भी आई। सका कारण

कुछ भी रहा हो लेकिन ला–एण्ड आर्डर जितना शानदार हरियाणा प्रदेश के अन्दर है उतना कही नही है। आप बाहर जा कर देखेंगे पड़ौसी राज्यो में तो आपको पता चलेगा कि सबसे शानदार ला–एण्ड आर्डर अगर कहीं है तो वह हरियाणा प्रदेश के अन्दर है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता कि राम राज्य हो गया है। राम राज्य तो राम चन्द्र जी– के वक्त में भी नही था। उस जमाने में भी राक्षस थे और सीता जी का हरण हो गया था। (विघ्न) ऐसे राक्षस राज्य में आज भी हैं जो कि ऐसे काम कर सकते हें। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः डा० राम प्रकाश जी ने नहर के बारे में कहा था कि कहा कही सै नहर टूटी हुई है, उसके बारे मैं भी अगर बता दें तो ठीक रहेगा।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, नहरे तो बार–बार टूटती रहती है। इस बारे मे इन्होंने पिछली बार भी बताया था और नेहरा साहब वहां क पर गए भी थे और देखकर आए थे। वहां पर हम साईकल बनाने जा रहे हैं और आने वाली बरसात से पहले ही उम्मीद है कि हम उसको ठीक कर देंगे ताकि वहा पर पानी फिर से न आए।

अध्यक्ष महोदय, एक इन्होंने सस्कृति की बात कर दी और सुशीला कांड की बात कही है। यह केस हमने सी ०बी ०आई० को दिया है। कुछ भाई तो यह कह रहे थे कि उसमें भजन लाल के किसी रिश्तेदार का हाथ था। भजन लाल के गाव के आदमी का हाथ है और कोई बिशनोई है। इनको तो पता नही जाति से क्या फोबिया हो क्या है। क्या जाति–पाती सें काम चलेगा ? अध्यक्ष महोदय, हमारे दिमाग में न तो कभी जाति–पाती की बात आई है और न ही कभी आएगी। हमारे लिए 36 बिरादरी के भाई सब एक समान है। जो सियासी आदमी सबको एक साथ लेकर नही चलता है

वह जिन्दगी में कभी कामयाब नही हो सकता है। एक बात और कर्ण सिंह दलाल ने कह दी कि मैं फरीदाबाद से एम०पी ० बन गया। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यह कोई छोटी बात नही है। बाकी लोग तो जात–पात देखकर ही टिकट मांगते हैं कि यहां पर फलाना बिरादरी के इतने लोग हैं इसलिए मैं तो यहां से इलैक्शन लडूगा। अध्यक्ष महोदय, जहां पर एक वोट भी मेरा न हो और वहां से डेढ़ लाख वोटो से लोग भजन लाल को जिता दें तो यह कोई छोटी बात नही है। यह इसलिए है क्योंकि भजन लाल सैकुलर आदमी है और सबको साथ लेकर चलता है। यह उसी का नतीजा है। मेवात में भी चार सैगमैंट हैं और वहां का मेल कैडीडेट मेरे मुकाबले में हो और मैं वहां पर भी सभी जगहों पर जीता और मैं डेढ़ लाख– वोटों से जीता था। (विघ्न) आप सुनिए तो सही। हनने बहुत काम किए है और जिस मिल की बात आप कर रहे है यह भजन लाल के जमाने की ही लगी हुई है। यह आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा पिछले 3– 4 सालों मे और भी जितने विकास के काम हुए हैं, वह भी हम आपको बता देंगे।

अध्यक्ष महोदय, चौधरी बीरेन्द्र सिह जी ने औद्योगीकरण के बारे मे कहा और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कहा। अध्यक्ष महोदय, हमने तो बहुत पहले ही संकल्प किया है कि इन्डस्ट्री को हरियाणा प्रदेश में लगाएंगे। बहुत से लोग तो बाहर से आ रहे हैं। हमने यह फैसला किया है कि इसमें जितने भी उद्योग लगेंगे उनमें हमारे हरियाणा के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। अगर कोई बहुत बड़ा टैक्नीकल आदमी हरियाणा मे नही मिलै तो वह कम्पनी अखबार मे तीन बार एडवर– टाईज करेगी और इसके बाद भी उन्हे कोई आदमी हरियाणा का नहीं मिलता है तो वे बाहर से ले

सकते हैं। अगर वे ऐसा करेंगे तो ही हम उसको लाईसैस देंगे, जमीन देंगे, बिजली और पानी देंगे और तभी उसको लोन देंगे।

चौधरी बलवन्त सिंह मायनाः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, बहादुरगढ़, सांपला और रोहतक के अन्दर फैक्टरियां लगी हुई हैं और फैक्टरियों वालों ने लोगों की जमीन ली हैं 1 वहां पर रहने वाले गरीब लोगों को नौकरी नहीं दी जा रही है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, वही तो मैं बता रहा हूं। हमने दो लाख के करीब हरियाणा प्रदेश के कुछ पढ़े–लिखे और कुछ अनपढ़ लोगों को रोजगार दिया है।

अध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में भी कहा गया कि इसको प्राईवेट सैक्टर में दे दिया जाए। इस बारे में हमने अढ़ाई–तीन महीने पहले ही फैसला कर दिया है और बाकायदा इस बारे में एडवरटाईज भी किया था। पहले तो इसकी मियाद 28 फरवरी तक थी और इसको बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया है। इसमे कोई भी आदमी 75 मैगावाट से 100 मैगावाट तक प्लांट लगा सकता है। चाहे वह डीजल से लगाए या चाहे वह कोयले से लगाए। वह किसी भी शहर में अपना प्लांट लगा सकता है, इस बात की हमने छूट दे रखी है। इसके लिए हमने टैण्डर भी इन्वाईट कर रखा है ताकि प्राईवेट लोग भी आएं और यहां पर माकर प्लांट लगाए।

अध्यक्ष महोदय, एक इन्होंने यह भी कह दिया कि हमने लोन मंहगे रेट पर ले लिया। हमने बाकायदा एडवरटाईज किया है और दो बार तो इसकी मियाद भी बढ़ाई कि हरियाणा बिजली बोर्ड को पैसे की आवश्यकता है। यह आवश्यकता क्यों शै क्योंकि हम किसानों को सबसीडाईज करके बिजली देते हैं। इसलिए बिजली बोर्ड को साल में साढ़े तीन करोड़ रुपए का

घाटा हो जाता है। हमें भारत सरकार से 2.30 रुपए प्रति यूनिट पर बिजली मिलती है और हमें घर की बिजली जो है वह 1.55 रुपए में पड़ती है और किसानों को हम बिजली 50–60 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से देते हैं। हरियाणा में आप यह समझ लीजिए कि बिजली बोर्ड को कम से कम 1.20 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से किसानों को सबसीडाईज करके बिजली देने में घाटा होता है। इन्होंने कह दिया कि 16.50 परसैन्ट में लोन लिया लेकिन हम तो कहते हैं कि नहीं 18 परसैन्ट में भी हमने लोन लिया है और मैं यह भी कहता हूं कि अगर इससे भी ज्यादा परसैन्ट में कोई हमें लोन देने वाला हो तो हम उस से लोन लेने के लिए तैयार हैं। हम उसका लोन वापस कर देंगे। हमने यह कंडीशन रखी है कि जब हमारे पास पैसा हो जाएगा तो हम आपका लोन वापस कर देंगे। अगर कोयला लेने के लिए पैसे न हो, सामान लेने के लिए पैसे न हों तथा इसके अलावा हम जो बिजली भारत सरकार से 50 करोड़ रुपये की लेते हैं तो वह महीने में 25 करोड़ यानी आधा हो जाता है क्योंकि बिजली का पैसा वहां से कम मिलता है। अगर हम भारत सरकार को पैसा नही देंगे तो वह हमें बिजली नहीं देंगे। एक बार जब उन्होंने बिजली काट दी थी तब हाहाकार मच गया था। तब हमने बड़ी मुश्किल से उनसे कहकर दोबारा से कनैक्शन जुडवाया और उनसे वायदा किया कि हम आपको बिजली का पैसा देंगे। अध्यक्ष महोदय, अगर रेल के किराए के लिए पैसे न हों, कोयले के लिए पैसे न हों तो क्या बिजली जादू से बनती है इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसी बातों के कहने का कोई फायदा नही है। हमने बहुत ज्यादा बिजली का उत्पादन किया है और किसानों को भी हमने बिजली दी है। हम चाहते हैं कि किसानों को पूरी बिजली मिले, कारखाने लगें, फैक्ट्री लगें। 1989– 90 में जब सम्पत सिंह जी के पास यह

महकमा था तो उस समय लाइन लौसिज 29.19 था लेकिन हमने इनके मुकाबले में लाइन लोसिज को कम किया है। 1990–91 में लाइन लौसिज 27.59 था लेकिन बाद में जब हमारा राज आया तो लाइन लोसिज 27.27 तथा 1992– 93 में 25.22 और 1993– 94 में लाइन लौसिज 24. 53 था। अध्यक्ष महोदय, हमने लाइन लासिज को भी क्य करने की कोशिश की है, लेकिन मै इस बात सै भी इन्कार नहीं करता कि लाइन लौसिज और भी कम होने चाहिएं और बिजली की चोरी भी कम होनी चाहिए। हमने बिजली की पहले के मुकाबले मे ज्यादा पैदवार की है और किसानों को दी है। अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि पिछले दो तीन महीनों में ही बिजली की हमको कोई शिकायत नही मिली है और हम जहां पर भी जाते हैं तो लोग तारीफ करते है और कहते है कि बिजली में काफी हद तक सुधार हुआ है। हमारी आगे भी पूरी कोशिश होगी कि बिजली मे सुधार किया जाए।

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर सर, मेरा प्यायंट आफ आर्डर है। सारे, हरियाणा मे बिजली नही है बच्चों के पढने के लिए बिजली नही हैं ....

श्री छत्तर सिंह चौहानः स्पीकर सर ..... (विघ्न)

श्री अध्यक्षः इन्होंने बिना इजाजत से जो कुछ कहा है, वहू रिकार्ड न किया जाये।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक बात और कह दी। मैं अपनी बात दो मिनट में पूरी कर लेता हू। मैं बंसीलाल जी से कहूंगा कि वे अपने मैम्बर्ज को पढ़ाया करें, सिखाया करें,। इनको हाउस को चलाने का तरींका सीखना चाहिए। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, यह भी जिक्र किया कि कैथल जिले मे क्योड़क मे 25 परिवार वापस नही गए। राम बिलास जी ने

भी कहा कि ये उनको वहा पर जाकर देख आएं। बड़ी गजब की बात है। शमी जी, आप तो ब्राह्मण हो, इसलिए ब्राह्मण तो गलत नहीं बोलता क्योकि वह डरता है कि कही ऊपर से शिवजी महाराज न आ जाए'। आपको तो यह बात शोभा नही देती।

श्री अमर सिंह ढांडेः स्पीकर सर, ...

श्री अध्यक्षः आप बैठिए। यह रिकार्ड न किया जाए। (व्यवधान)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, लोग मेरे पास भी आए थे। वहां हरिजनों में आपस में झगड़ा था।

प्रो० राम विलास शर्माः स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैंने गलत बोला।

चौधरी भजन लालः मैंनै गलत बोलने के निरा नही कहा बल्कि मैंने कहा कि आपने ठीक नही कहा।

प्रो० राम विलास शर्माः स्पीकर सर, मैंने इस सदन में बड़े ही आग्रहपूर्वक यह बात कहीं थी कि 19 तारीख को मैं उन लोगों से कैथल में क्योड़क में मिलकर आया हूं। आज भी 25 परिवार कैथल में हैं और वह वापस क्योड़क में नहीं गए। कुछ परिवार तो जरूर वापस चले गए हैं लेकिन 25 परिवार आज भी क्योड़क में नहीं गए।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 5 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए।

आवाजेंः जी हां।

श्री अध्यक्षः हाउस का समय पाँच मिनट के लिऐ और बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1995–96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, डर की वजह से कोई परिवार नहीं गया। डिप्टी कमिश्नर डी०आई०जी०, कमिश्नर और एस०पी ० सब ने मौके पर जाकर गांव में जाकर लोगों से बात चीत की और कहा कि किसी आदमी के साथ ज्यादती, जुल्म, अन्याय हो गया तो हमारे से बुरा कोई नहीं होगा। हरिजनों को पूरा विश्वास देकर के आए। हरिजनों का आपस का झगड़ा था कत्ल हो गया और कत्ल की बिनाह पर ऐसा मामला हो गया इसमें भी हम जात–पात को ले आएंगे तो कोई अच्छी बात नहीं।

श्री अमर सिंह ढांडेः अध्यक्ष महोदय, हम तो यह कहते हैं कि जो 25 परिवार चले गए हैं उनको बसाने की कोशिश करें। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लालः शुरु में आए थे लेकिन चले गए। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, राम बिलास जी ने पृथला कांड की बात कहो थी। इस मामले में दो आदमी पकड़े हैं और सी०बी०आई० ने जांच की और जांच करने के बाद उसमें कुछ मिला नहीं। आज सें लगभग दस दिन पहले बाकायदा कोर्ट ने जमानत ले के छोड़ दिया। जो बातें कहीं थीं उनका मैंने जवाब दिया है बाकी बातों का जवाब विस्तार से कल वित्त मंत्री जी देंगे। बहुत शानदार बजट पेश किया है, इसकी सराहना सबको करनी चाहिए।

Mr. Speaker : Nov the House is adjourned, till 9.30 A.M. tomorrow, the 22nd March. 1995.

***13-47 hrs.**

(The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Wednesday, the 22nd March, 1995.)